ध्येय IAS

GENERAL STUDIES

with just a little help

Study Tide

Hkkjr dk Hkwxksy

CLASS NOTES (FOUNDATION BATCH)

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

OUR CENTRES:

NORTH DELHI	EAST DELHI	ALLAHABAD	LUCKNOW	VARANASI
A-12, 13, Ansal Building, 201, IInd Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009 Ph. : 011-47354625, 27655121, 09540062643	D-151A, Opposite Laxmi Nagar Metro Station, Gate No. 1, Above Bulldog Showroom, Vikas Marg Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Ph :011-43012556, 9311969232	17 C, Shree Ram Towar, IInd Floor Near Yatrik Hotel, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad Ph. : 0532-2260189, 08853467068	Ist Floor, Arif Chamber-IV, Purania Chauraha, Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4025825, 09506256789	N-1/71 AB-R Madhav Market, Nagva, Lanka, Varanasi (U.P.) Ph. : 07408098888

"Without Creating a new problem old problem can not be solved."

Production उत्पादन → वस्तु goods, सेवायें Services

उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमे उत्पादन के साधनो की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल मे परिवर्तित किया जाता है।

उत्पादन के साधन
Factors of Production

Land	Labour	Capital	Enterpreneur
भूमि	श्रम	पूँजी	(उद्यमी)
↓	↓	↓	↓
किराया (Rent)	Human Resources	Interest (ब्याज)	Owner ने implementation किया।
	↓		↓
	Ways (मजदूरी)		profit (लाभ)

=) Profit के लालच पर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है

पर profit जरूरी है reason (Normal Profit)

(1) Base planning & Risk → उद्यमी का होता है इसलिए profit उसका हक है

Thinking में

ex. 1 pin made

Rent – २ ₹
Ways – २
Interest – २
Ent. – २
८ ₹ – साधन लागत (Factor Cost)

← नाजार में आयी

← २ ₹ सरकार ने Tax लगाया

Market Cost
10 ₹
||
८+२

Study Tide

एक साल देश का उत्पादन 8 ₹ हुआ — ex.

Rent		
~~Land~~ -	२	income
Ways -	२	income
Interest -	२	income
Profit -	२	income
	8	- देश की income

Production में ही income generate होती है

⇒ उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही आय का सृजन होगा दोनों बराबर होगा

⇒ उत्पादन को बढ़ाकर आय का सृजन किया जाता है - legal और illegal (whole World policy)

⇒ demand का बढ़ना ← Economics का fuel

⇒ demand के बढ़ने को केवल पैसा पर्याप्त है जरूरी नहीं कि इससे production बढ़े। क्योंकि Production के लिये Land, Labour, Enterprenur भी चाहिये।

⇒ Technology भी चाहिये Machine चाहिये। इन सबके अभाव में Supply बहुत कम हो जायेगी और फिर जरूरी ~~बढ़ी~~ बढ़ेगी क्योंकि महंगाई आसमान छुयेगी।

⇒ पूरी दुनिया में Note छापने का Base production ही होता है।

⇒ Money is a medium of विनिमय exchange.

⇒ उत्पादन दे तो उसके बराबर ही पैसा चाहिये नहीं तो फिर गिर जायेगी economy

⇒ RBI उतना ही पैसे ~~छापता~~ है जितने में demand supply बराबर रहे। जितना पैसा Market में absorb हो जाये। Absorption, production पर depend करेगा। यानि जितना पैसा हमें उस समय में बाजार में उपलब्ध सभी उत्पादित माल उपलब्ध हो

⇒ अर्थात्

Production = Income

। ही सिक्के के दो पहलू

Growth Rate →

Study Tide

Growth Rate → | Implication

Production | Income

2011 - 100 ₹ | 100

+10

Growth Rate - (10%)

2012 110 ₹ | 110 ₹

10 ₹ अतिरिक्त आय का सृजन हुआ।
Additional income

अमीर

गरीब

उत्पादन में 10% वृद्धि हुयी लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है

⇒ आय की असमानता को कम करने का तरीका कार्ल मार्क्स ने कहा →
"अमीरों से छीनो गरीबों को बांटो"

⇒ पर यह practical नहीं तो हमारी सरकार गरीबों को ऊपर उठाकर असमानता कम कर सकती है

⇒ अतिरिक्त उत्पादन द्वारा अतिरिक्त आय का सृजन करके गरीबों की pocket में भेजे और यह high growth rate के कारण होगा। इससे असमानता कम होगी पर भारत में यह अमीरों की जेबों में जा रहा है जिससे असमानता तय नहीं है

Necessary Condition - growth rate का बढ़ना

Sufficient Condition - वितरण (अमीरों को न देकर गरीबों तक अतिरिक्त आय का पहुंचना)

⇒ Indian government केवल Necessary Condition को focus करती है न कि वितरण को। Both Conditions are important

⇒ हमारी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये growth rate जरूरी है

Study Tide

Income = 8 (Country level)

Consumption
उपभोग
5

Save (person level)
बचत
3

↓

Bank

↓ reason

(1) Safty

(2) Interest ब्याज

↓ Bank ने loan दिया नहीं तो Bank को घाटा होगा।

looner

↓

(Country level) निवेश Investment

एक व्यक्ति की बचत दूसरे का निवेश बनी Bank बनी के माध्यम बना।

Microeconomics — One person study (economic study)

Macroeconomics — One Country Study

Indian Economy

Consumption उपभोग व्यय

↓

Revenue Expenditure

Investment निवेश व्यय

↓

Capital Expenditure

Pr

Production	=	Income	=	Expenditure
उत्पादन		आय		व्यय

1 सिक्के के 3 पहलू

Study Tide

भुगतान Payment → जरूरी नहीं कि यह खर्चा हो

Payment के बदले में कुछ प्राप्त हो तो वह खर्चा होगा

Payment - 4200 (हमारा खर्चा) → बदले में benefit - Room (1 महीने तक)

Payment - 1700 (हमारा खर्च) → बदले में benefit - food

Payment - 2000 (मित्र को उधार) → बदले में service ~~आया~~ नहीं

→ खर्चा नहीं (expenditure नहीं)

Payment - 1 ₹ (भिखारी को) - खर्चा नहीं पर payment

Payment - 10,000 (charitable कामों में) - खर्च माना जायेगा।

यह एक अपवाद है

⇒

Payment → 2000 किराया - benefit 1 साल से कम

↓

राजस्व व्यय Revenue Expenditure

Payment → 2000 रेडियो खरीदा → benefit 1 साल से ज्यादा

↓

पूंजीगत व्यय Capital Expenditure

↓

asset (all material)

↓

जो 1 साल से ज्यादा benefit दे वे खर्चे asset हैं

Study Tide

~~N.N.P~~ National Income

1 April — 30 March (1 economic Year)

जब तीनो Transaction होंगे (Production, Income, Expenditure) तभी राष्ट्रीय आय होगी।

हमारी Income → तीनो होंगे

छात्र को scholarship - production नही (Income है, खर्च भी है)

वृद्धावस्था पेंशन - production नहीं (Income है, खर्च है)

मकान बनवाया - production हुआ asset का income उसके लिये जिसको दिया } आयेगा N.I मे

Expenditure

↓ उसे कोई रकम दी

तो NI मे नही जुड़ेगा क्योंकि production नही हुआ।

↓ जो Broker आयेगा बीच मे

तो उसकी NI मे जुड़ेगा।

जिसने वो मकान broker बीच मे आयेगा उतनी बार NI मे जुड़ेगा क्योंकि वो production करके Income या रकम उसने भी खर्च की होगी।

Study Tide

Vicious Circle of Poverty

गरीबी का दुश्चक्र

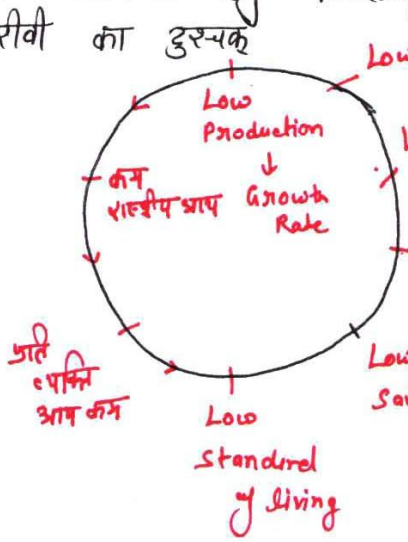

व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय / जनसंख्या

Capital formation - पूंजी निर्माण -

देश के भीतर उन सब चीजों का निर्माण करे जिससे देश मे उत्पादन बढ़े।

सबसे प्रमुख - Infrastructure - road, dam, electricity, Railway, transportation

विकसित देशों का infrastructure मजबूत इसीलिये production काफी अच्छा।

India मे Delhi का infrastructure बहुत मजबूत है present मे ↓ इसलिये production - services का goods का काफी अच्छा है

Investors को attract न कर पाने का कारण - Infrastructure मे

① Investment amount बहुत ज्यादा

② पैसा लगाने और उसका ~~result~~ return या profit आने मे बहुत time लगता है

↓

waiting period काफी लम्बा

③ Return काफी कम

Infrastructure - development की key है

⇒ J.P. Group ने Yamuna Express way बनाया - private sector

Delhi — Agra

⇒ Infrastructure बना production बढ़ा लेकिन भुगतान बढ़ा Toll Tax बढ़ा।

अभी Toll Tax कम है पर जिस तरह यह बढ़ेगा profit बढ़ेगा। पर महंगाई बढ़ेगी।

Public Private Partnership - Present

Agra मे infrastructure बढ़ने से travel बढ़ा जिससे tourist बढ़े होटल industry develop होने के बजाये down जा रहा है क्योंकि Yamuna Express way के जरिये कम समय मे आदमी वापस पहुंच जाता है समय की बचत होती है लेकिन इससे आदमी का आगरा मे रुकना बंद हो गया। जिससे आगरा के प्रत्येक व्यवसाय खासकर होटल व्यवसाय पर फर्क पड़ा

Study Tide

⇒ सभी गरीब देशो की समस्या यही है ◯

⇒ Investment ⟶ Growth Rate (सीधा सम्बन्ध)

⇒ इसीलिये PM Infrastructure मे निवेश ला रहे है बाहर से

⇒ power instrument को break करने का ⟶ Investment
गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ेगा ⟶

ex. गुजरात → most developed
→ infrastructure काफी मजबूत
→ •

Investment

बढ़ाने में उपयोग पूंजी

↓ घरेलू पूंजी
Domestic Capital
↓
भारत के लोगो का पैसा
↓
यह बेहतर है विदेशी पूंजी के उपयोग से

↓ विदेशी पूंजी
Foreign Capital
↓
यह पूंजी use करने पर विदेशो का हम पर आर्थिक दबाव बनता है और फिर राजनैतिक दबाव बनता है

पुराना उपनिवेशवाद - First Political dominate then Economical dominate

Neo उपनिवेशवाद - First Economical dominate then Political dominate

आयात - Dollar में भुगतान

Crude oil का 80% हम आयात करते है

(1) Borrowing उधार (1951-91)

(2) FDI
↓
Foreign Direct Invest
प्रत्यक्ष देशी निवेश

Study Tide

1950- योजना आयोग Planning Commission

Qu- क्या पैसा पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है — 1950 में

Qu- अगर है भी तो क्या हम इस स्थिति में है कि इसे use कर पाये।

पैसा पूंजी use करने के लिये 2 Machine जरूरी

- Bank (2002 तक)
  - linking thing
  - one person — another person
  - saving — investment
- Company
  - Mutual Cooperation (Partnership)

* 1950 में Bank की स्थिति
  - बहुत खराब थी (बहुत कम Bank थे)
  - all Bank - private area में थे
  - ⇒ शहरो तक सीमित थे
  - ⇒ 1955- Imperial Bank को government Bank बनाया और इसको SBI और 7 सहकारी बैंको में स्थापित किया (Total- 8 Bank)

1806- Calcutta प्रेसिडेंसी Bank
Bombay " "
Madras " "
} 1921 में इन्हे जोड कर Imperial Bank बनाया गया।

1775 — Hindustan Bank सबसे पहला

1969 — 14 Bank का सरकारीकरण
14+8 = 22

DSA-

Study Tide

DSA → Direct Selling Agent (जो बैंको का विज्ञापन करते है तथा उनके लिये ग्राहक जुटाते है)
बैंको के agent
पहले मे इनको कमीशन मिलता है।

Company (2001 के बाद)

आपसी संयोग पर आधारित

एकल स्वामित्व
↓
सबसे पुराना तरीका
↓
majement & ownership same

Partnership
2 people
↕
owner & majement same

Company
more people
↓
कम्पनी का मालिक कम्पनी नही चलाता। (BOD) जो चलाता है वो मालिक नही होता (शेयर होल्डर मालिक होते है)

XYZ Company

~~संचालक~~ दल (जो Bussiness चलायेगी)
Managment head
→ CEO
→ M.D.
→ E.D.
} इनको कमीशन और Salary मिलती है

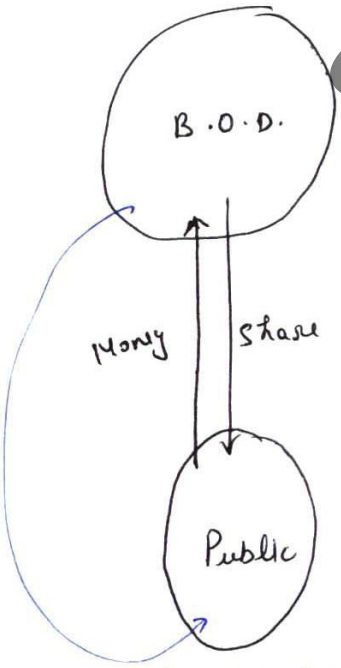

जो व्यक्ति जितना % पैसा लगायेगा तो उतना % मालिक होगा।

लाभांश – साल भर बाद profit होने पर मिलेगा।

Study Tide

1956- India में Company Concept आया।

FDI → foreign Direct Investment खुले द्वार की नीति
विदेशी कम्पनियों को भारत आने का निमंत्रण

Indian Company ——— Western Company

① पूंजी ज्यादा
② Technology ज्यादा
③ बेहतर Businessman
Enterpreneurship
} Mains question

⇒ quality better than old (विदेशी कम्पनियां प्रतिस्पर्धा में रोज नई तकनीक विकसित कर रही है)

⇒ quality ⊕ better + लागत भी कम (कम लागत में अच्छी तकनीक बनाने के कारण इनकी बिक्री ज्यादा)
Latest Technology- Market King

⇒ Aug 1995 में first call ज्योति बसु ने किया

भारत के लोगो ने ~~2005~~ 1995 में Reliance power के शेयर आने पर काफी जोश दिया 10 हजार करोड़ के शेयर बेचे गये जिसको 63 गुना ज्यादा response मिला। यहीं से भारत में शेयर होल्डिंग की शुरुआत हुयी Major level पर। उसके बाद से यह निरंतर बढ़ रहा है इससे प्रेरित होकर कई विदेशी कम्पनियां भी भारत आयी और उन्होंने भी अपने शेयर बेचे। जिससे भारत की भरपूर जनसंख्या और उसके बाजार का विशेष महत्व प्राप्त हुआ। शेयर मार्केट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को नये आयाम अपने स्तर निर्माण के उत्थान में सहायता प्रदान की।

Study Tide

BPO = भारत में निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति होने की वजह से बाहर की कम्पनियाँ यहाँ से विज्ञापन, वर्जरह कराती हैं
विश्व स्तरीय है India का BPO

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण -

उदारीकरण ने भारत को एक विशेष पायदान पर लाकर खड़ा किया है पर आर्थिक क्षेत्र में। उदारीकरण में प्रशुल्क कम करके कोय ध्यान कर बाहर की वस्तुये भारत में आयी जिससे विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत की ओर हुआ। 125 करोड़ की जनसंख्या जो विश्व पटल पर सर्वाधिक है पूरी दुनिया को अपने उत्पादो को बेचने का एक सस्ता और मजबूत बाजार उपलब्ध कराती है

निजीकरण से सरकारी उपक्रमो की बाध पर कार्यकुशल होने का दबाव बढ़ा साथ ही निजीकरण से आधारभूत संरचनाये भी मजबूत हो रही है परन्तु साथ ही कीमतो में भी वृद्धि हो रही है जो भारत की असमानता कम करने के लक्ष्य से इर ले जा रही है

वैश्वीकरण - इसकी भारत को जरूरत भी है और यह एक नाग की तरह पात लगाकर एक बार डसाकर फिर अपने पाश को कस कर भारत जैसे विकासशील देशो को पर कब्जा करने का सर्वसुलभ हथियार बनता जा रहा है। विकसित देश अपने बाजारो में विकासशील और गरीब देशो को आने की अनुमति कई मानको से गुजरने के बाद देते है जबकि भारत जैसे गरीब देशो में वे बेरोकटोक आवागमन कर रहे है जिससे हमारे आन्तरिक बाजार पाटे में जा रहे है

Study Tide

विदेशी पूंजी का उपयोग भारत मे होने पर भारत मे capital बढ़ेगी जिसका उपयोग infrastructure मजबूत करने मे किया जा सकता है लेकिन इससे भारतीय बाजारो मे विदेशी वस्तुओ की उपलब्धता बढ़ेगी। जिससे नई तकनीक और कम लागत का उपयोग करके भारत मे निर्मित वस्तुओ से बेहतर उत्पाद बनाये ~~जायेंगे~~ जायेंगे और बेचे जायेंगे। इससे भारतीय बाजार पुनः गर्त की ओर गिरना प्रारम्भ हो सकता है इसलिये विदेशी निवेश आवश्यक है पर साथ ही भारतीय उत्पादो और उद्यमो को बढ़ावा देना भी जरूरी अन्यथा भारत मे एक तरीके से उत्पादन होगा पर उत्पादन करने वाली मशीनरी ठप्प होने की सम्भावना है वैश्वीकरण के दौर मे विकसित देशो ने विकासशील और गरीब देशो को ~~आने से रोक रखा~~ है उनके देश आने मे रोका तथा उनकी मशीनरी ठप्प न हो उसके लिये subsidy की सहायिकी दी गई और साथ ही शुल्क लगाये गये है कोटा निर्धारित है

Study Tide

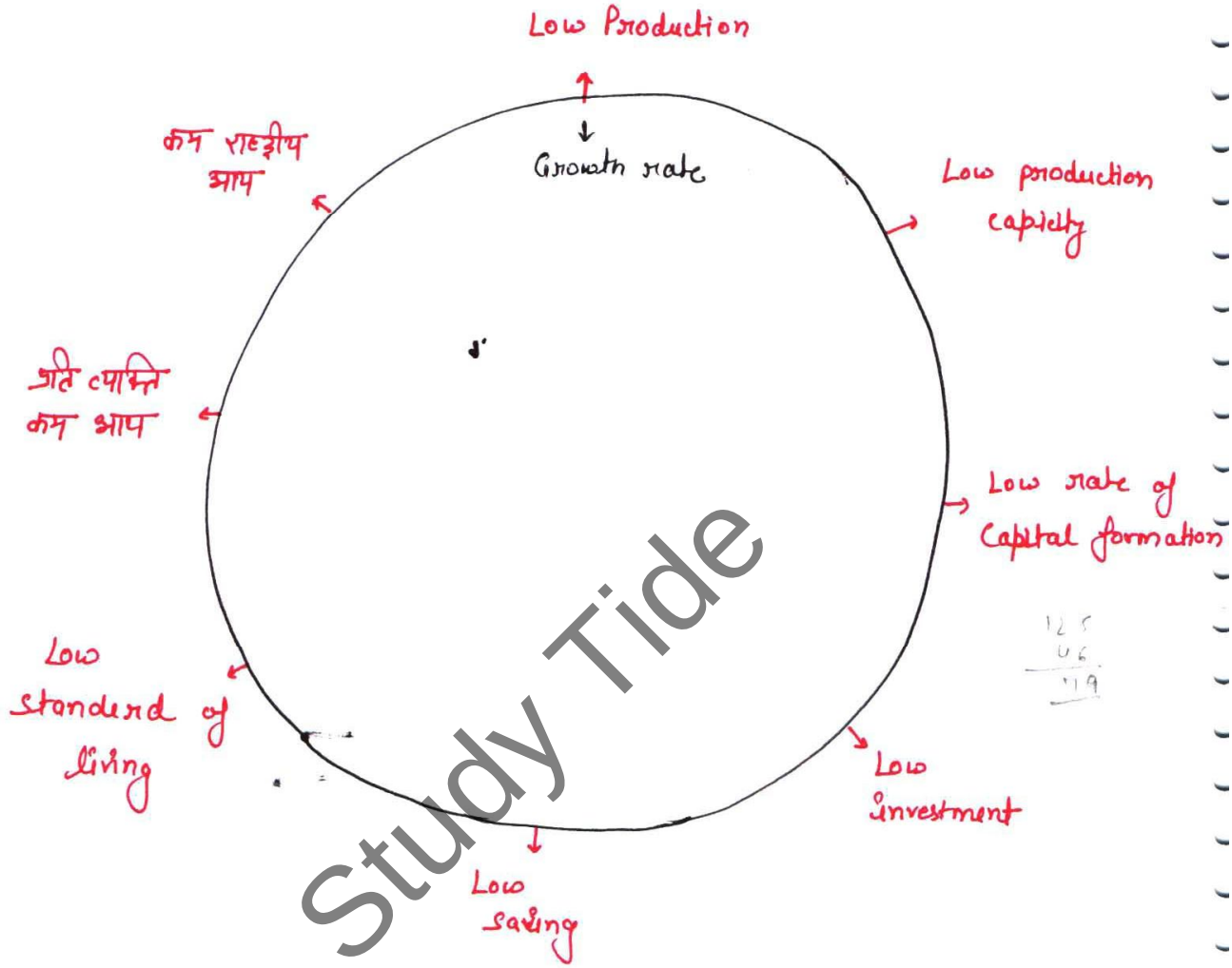

Study Tide

प्राथमिक क्षेत्र - कृषि , खनन और उत्खनन

द्वितीयक क्षेत्र - कृषि , खनन और उत्खनन , विनिर्माण

तृतीयक क्षेत्र -

8-8-2015

⇒ 1990-91 में अर्थव्यवस्था worst condition में थी।

» विदेशी मुद्रा भण्डार 1 बिलियन से कम हो गया था। फिर सोना गिरवी रखके पैसा लाया गया।

↓ इस स्थिति का कारण

1950 में योजना आयोग बना। पंचवर्षीय योजनायें बनी।

↓

पं नेहरू ने भारत में बड़े उद्योग धन्धों को लगाने पर बल दिया।

↓

1951-56 तक नेहरू ने home work किया और महालनबिस को मॉडल तैयार करने को कहा। - Russia के Model का copy था।

↓

1956 में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई।
1956 LIC, Company अधिनियम, IDBI, आये
Growth rate 5% पहुँच गया।

↓

3rd पंचवर्षीय योजना आयी।

↓

1962 में China - India war हुई। भारत हारा।

↓

लड़ाई के कारण विकास के resources war की तरफ मोड़ा गया।

↓

1964 में नेहरू dead

↓

1965 में India - Pakistan

↓

1966-67 में अकाल

↓

1971 में लड़ाई

↓

1975 में emergency

Study Tide

1977 में आम चुनाव हुये उसमे जनता पार्टी आयी, कांग्रेस का घोर विरोध हुआ

1962-77 कुछ नही हुआ। (15 साल) - हरित क्रांति के अलावा

1977 में स्थायी सरकार, मोरारजी देसाई आये (

↓

1991 में भारत में economic reform शुरू हुआ

1977 में मौका था पर राजनीतिक दलो का Moral Value Zero हो गया था हमारे Prime Minister बड़े उम्मीद पर भारत ने यह मौका आन्तरिक कलह की वजह से खो दिया।

↓

1980 में राजनारायण, चौधरी चरण सिंह के कारण सरकार गिर गयी।

↓

1983 में ~~उन्ह~~ Indira Gandhi PM बनी पर ज्यादा कुछ कर न पायी।

↓

फिर राजीव गाँधी आये और सैम पित्रोजा आये mobile लाये।

↓

1990-91 में भारत पर था तब नरसिम्हा राव आये।

↓

उन्होंने बड़े कदम उठाये और एक finance minister दूँढा

↓

मनमोहन सिंह ~~#~~

↓

24 July 1991 - New Economic Policy

→ LPG (Liberization
Privatization
Globalization) Model

Study Tide

साध्य - aim
साधन - government policy to gain aim

⇒ Reform → change in policy
बहुत बड़े स्तर पर बदलाव
पुरानी सारी policy खत्म कर दी जायी
⇒ Borrowing खत्म कर दी जायी
⇒ FDI की तरफ आयी

1991 में Reform में drawback - Agriculture पर silent था।
1991 में Bank, Company भी मजबूत नहीं थी
केवल एक ~~से~~ रास्ता बचा FDI → खुले द्वार की नीति
" Beggars are no more choosers."

विदेशी कम्पनियाँ भारत आयी
Question - 1991 से पहले क्यों नहीं आयी

1944 → World War ending पर था India का participation indirect था
↓
विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ायी, देशों के बीच व्यापार प्रभावित, और infrastructure बरबाद
↓
यह realize किया गया कि development जरूरी है और यह आपसी सहयोग से ही possible
closed economy - देश की सीमाओं के अंदर की अर्थव्यवस्था
open economy - पूरी दुनिया के साथ व्यापार
↓
Bretton wood, USA में सम्पन्न हुआ GATT आया
1995 में WTO हुआ

Study Tide

American System (1944 में बनाया गया)

⇒ World Bank

⇒ IMF (International Monitary fund)

⇒ ITO (International Trade Organization)

↓ यह नहीं बन पाया 4 साल बाद

GATT बना ⟶ फिर 1 Jan 1995 में WTO बना

World Bank (5 Bank Gp)

Main

IBRD

↓

International

Bank

for

Reconstruction & Development → यह केवल देशों के अंदर निर्माण में use हो सकता है

भारत में 40% से ज्यादा योगदान World Bank का था।

IMF

यह loan केवल International level पर use किया जा सकता है शुरू में 5 देशों में common currency – hard currency लागू की गयी।

भारत का ₹ soft currency है ↓

America (USA) का Dollar

Japan का Yen

Britain का Pound Sterling

Gurmany का Mark

France की Frank

Study Tide

⇒ 1 American
1 Asian
3 European } मजबूत देश

Basket of currency

⇒ इन सबमे सबसे ज्यादा weight dollar को दिया गया। (40%)
80% भुगतान Dollar मे होता है - 2014 मे
No 2 पर China का Yuan आ गया। - 2014 मे

Export (निर्यात
X

Import (आयात)
M

X - M = -ve ⇒ आयात ज्यादा, निर्यात कम
(1972-73, 1975-76) - exception

सभी गरीब देशो की same स्थिति except China.

Export मे Dollar की supply RBI को, निर्यात देगा विदेशी मुद्रा अर्जन करेगा। (100 $)

Import करेंगे तो Dollar की demand करेंगे। माना (150 $)
अब हमारा अर्जन कम होगा। हम RBI से 150 $ की मांग की लेकिन RBI के पास केवल 100 $ है 50 $ की कमी।

X
[Supply
[$100]]

M
[Demand
[$150]]

कुछ cases मे Import कम नही किया जा सकता ex. Raw oil कच्चा तेल

90% हम आयात करते है

IInd option - कोई agency 50 $ का loan दे और यह loan IMF देता है

Study Tide

World Bank और IMF दोनो एक दूसरे से अलग काम कैसे का तरीका पर दोनो ~~British~~ Bruttenwood की देन क्या आप सहमत है?

बिना IMF का सदस्य बने ~~GATT~~ World Bank का सदस्य नही बन सकते।

⇒ विकसित देश 55% Voting Power — गरीब देश → IMF में 45%

⇒ विकसित देश World Bank और IMF के सहायता से गरीब देशो पर दबाव बनाया जाता है।

⇒ BRICKS → एक नये Bank का बना रहा है
ताकि American System से निकल सके।

⇒ ITO- Watch Dog
जो दो देशो के बीच व्यापार पर नजर रखता था।

⇒ 70 के दशक तक आते आते विकसित देश again develop हो गये।

⇒ 1951- 1991 तक भारत में लगने वाली पूंजी का 40% World Bank ने दिया।

⇒ 90 के दशक में Market Saturate हो गया विकसित देशो का
↓
demand बंद गयी

economy का death process start हो जाता।

demand रुकते ही मंदी आ जाती है

e.g. →

Study Tide

⇒ Sweden का स्लोगन - 3 तच्चे for job
क्योंकि population बहुत कम है

⇒ America में सबके पास TV हो गया तो उसकी industry कैसे चलेगी बिना demand के।

↓
दो विकल्प है उनके पास

(i) industry बंद कर दो
(ii) अपने market में बाजार नहीं तो दूसरे देश में बेचो।

⇒ 1930 का मंदी - Britain में यूरोप और अन्य देशों में [illegible]
सारे industry बंद हो गये थे

1970 के दशक में मंदी के कारण America की मजदूरी भी हमारे भारत में आकर बेचने को मजबूरी थी। ताकि मंदी से निकल सके।

⇒ उस समय भारत Growth और development के लिये कोशिश कर रहे थे

⇒ और America अपने survival के लिये लड़ रहा था।

⇒ Rugar और Reagan ने meeting हुयी पर कोई हल नहीं निकला

⇒ फिर उन्होंने export किया। - American से
फिर भारत में Import किया गया ताकि से American अर्थव्यवस्था को बचा सके।
फिर भारत सरकार ने Aggressive Tax लगाया ताकि भारतीय Industry बची रहे।
दुनिया के सभी देशों को वैश्वीकरण [illegible] अपनाना था।

Smuggling बढ़ी क्योंकि भारत और नेपाल में कीमतों में बहुत अंतर था।
1970-80 में smuggling वही जिनकी माप में कम value में ज्यादा था।
ex. gold
gold पर custom duty बहुत ज्यादा थी।

Study Tide

⇒ भारत सरकार ने gold पर 10% custom duty लगा दी थी।

⇒ 1982 में Asian Games हुयी

भारत में Colour TV आये। - 1982 में

भारत के TV में quality खराब थी।

भारत मांग जाल की तरफ बढ़ रहा था। विकासित देश अपने survival के लिये लड़ रहा था।

1990 में World Bank और IMF का use विकासित देशो ने India के खिलाफ किया।

India IMF के पास गया for loan

↓

IMF ने शर्तें रखी loan के लिये

↓

शर्त रखी → घरेलू policy में बदलाव करे

→ सीमा शुल्क (आयात 130% था) उसको घटाकर 30% लाये।

→ excise tax उत्पाद कर को 22% से बढ़ाये। (भारत के उद्योग मरेंगे और विकासित देशो को फायदा।)

→ रुपये का अवमूल्यन करे।

⇒ Loan लिया अपनाकित करने के बाद

⇒ इसके बाद विकासित देशो ने अपनी problem को हमेशा के लिये solve करने को globalization का concept दिया गया।

Business

Labour, Capital, Services, Technology, Goods - यह सब चीजे जहाँ बिना किसी रोक टोक move करे वहीं globalization है।

∴ Terms & Condition - India ने decide की।

Study Tide

9-8-2015

Company

⇒ Company का concept विकसित देशों से आया।

⇒ 1956 - Company Law भारत में आया पहली बार।

↓

कई बार संशोधन हुये

↓

2013 में नया Company Bill आया

⇒ India में बनने वाली हर company का registration compulsory कर दिया गया। भारत की सारी कम्पनी Company Act 1956 के अन्तर्गत Registered हैं।

↓

यह Company का Mother Act है

⇒ RBI – RBI Act 1934 के अन्तर्गत बना

↓

यह RBI का Mother Act

⇒ Banking Regulation Act 1949 - for Banks

⇒ Partnership में business — partnership firm कहलाता है

↓

यह partnership form 1932 के अन्तर्गत registered हैं

यह आवश्यक नहीं कि registration कराया जाये

private partnership firm को

Registered firm — Unregistered firm

↓

legal matter में safe

(लाभदायक)

Study Tide

Company Act ने कार्यकारी किया registration को।

ROC - Registrar of Companies (most powerful)

↓

कम्पनी से related matter का Boss

every state में इसका एक office - UP - कानपुर

civil Service group 'B'

⇒ नामकरण - नाम की उपलब्धता - I^st Step

↓

form भरवाया जायेगा 6 preferences भरवाई जायेगी।

↓

unique नाम मिलते ही बन जायेगा। (ABC Company)

↓

Name का Approval हो गया

↓

अब Registration शुरू होगा

↓

2 Book prepare करवानी होती है

a) Memorandum of Association

पार्षद सीमा नियम

↓

Company का संविधान है

↓

ज्यादा imp

↓

क्या करना है

Superior

b) Articles of Association - कैसे करना है

Subordinate

पार्षद अन्तर्नियम

↓

Company का Trailows है (rules & regulation) → Office Manual

दोनों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

अगर otherwise illegal माना जायेगा।

Study Tide

सबसे ऊपर company law है
Memorandum Article

⇒ CA, Company Secretary (C.S.), Advocate यह Memorandum, Article तैयार करते है (Specialist)

Company Law > Memorandum > Article

Memorandum

⇒ 6 clause (उपबंध) → 1. name clause (ABC Company)

2. → Registered office clause (Company सारे offices का अधिकृत कार्यालय उपलब्ध पूरा detail बतायेगी)

↓

(Head office) Corporate Office

3. → Object clause → किस चीज का bussiness करेगी विषयवस्तु उपबन्ध

Trading
↓
बनी हुयी चीजो को खरीद-बिक्री करना

Manufacture
↓
Raw Material से बनायेगे।

Goods
↓
Colour TV
बनाना और बेचना

Services

⇒ Maximum decision BOD द्वारा (Board of director द्वारा)
अति महत्वपूर्ण decision शेयर होल्डर्स द्वारा
तो शेयर होल्डर्स की meeting बुलायी पड़ेगी तो meeting वही होगी जहाँ Cooperate office होगा। किसी Auditorium मे meeting होगी क्योंकि शेयर

Study Tide

होल्डर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है

→ एक Auditorium Book होगा

↓

सब share holders को Notice आयेगा

↓

छोटे share holder interest नहीं लेते पर बड़े जाते हैं क्योंकि उनकी voting value बहुत ज्यादा।

↓

Company में proxy legal है। छोटे share holder अपने voting right बड़े share holders को transfer कर देते हैं

↓

Agree हो जाने पर ROC के पास जाकर संशोधन हो जायेगा।

Adjustment → 5 page object clause बनाते हैं

बहुत सारी चीजों को उसमें add कर देंगे।

क्योंकि यह जरूरी है जो memorandum में न हो वह न बने

जरूरी है जो बनाये वो सब memorandum में हो

✓ → अधिकृत पूंजी उपबन्ध

Authorized Capital Clause

↓

कम्पनी कितने पूंजी से अधिकृत है

↓

Face value → 1,00,000 share of 10 ₹ each (माना)

↓

कम्पनी का एक share कितने का होगा यह company तय करेगी यह 10 के गुणज में होगा।

यह face value होगी

अधिकृत पूंजी - 10,00,000 ₹

1,00,000 × 10 ₹

हमारी Company अपनी पूरी life में 1,00,000 share बेचेगी और हमेशा 10 ₹ का।

Study Tide

⇒ Company share टुकड़ो में भी बेच सकती है

⇒ और ज्यादा share बेचने को clause में change करना पड़ेगा।

~~Adjustmant → यहां तक 1,00,000 में 0 दत्त कर~~

Reg fee का base अधिकृत capital है

present - 1,00,000 पर 5000 fees

10,00,000 पर 50000 fees

इसलिये अधिकृत पूंजी में Adjustment मुश्किल है

⇒ तब इसके share holder की meeting बुलाकर change किया जायेगा।

ROC को नया memorandum submit होगा और अतिरिक्त fee जमा करनी पड़ेगी।

(4) → Liability Clause

दायित्व उपबंध

↓

- 10,000 × 10 = 1,00,000

↓

इसमें 20000 10 = 20,000 (20%)

share खरीदे

Company जब profit कमाती है तो सरकार को tax देती है

उस पर - निगम कर

↓

राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा

⇒ Company को ढेर सारा profit हुआ, tax दिया

↓

बचा profit share holder को देगी।

Study Tide

(2)

भारत के आम आदमी को Company से जोड़ने को 1956 के Company Act में
कि loss के case में share holder को amount नहीं भरना पड़ेगा।

₹1000 के share इसने लिये उसके अलावा company इससे 1 ₹ भी नहीं
ले सकती – यहां face value के हिसाब से हमारा liability घटा कर दी गई
⇒ profit में हिस्सा मिलेगा। ↓ Your liability is limited

ABC Limited Company - इसमें liability limited ~~कर~~ की जाती

→ liability clause

सीमित दायित्व वाली कम्पनी
Limited Company
↓
profit मिलेगा
loss नहीं देना पड़ेगा

~~असीमित~~ असीमित दायित्व वाली Company
Unlimited
↓
profit और loss दोनों देना पड़ेगा।
↓
यह केवल कागजों में है भारत में, यह केवल विकसित देशों में

→ Company की limited / Unlimited होने की information liability clause में मिलेगी।

Study Tide

Satyam Matter - प्रत्येक employee को ₹0,00,00,000 salary थी company के सारे document public होते है No Secrecy

Practical Cases -

Case of एकल स्वामित्व →

A ने bussiness शुरू किया।

↓

A Enterprises (Name)

Accounting & legal Purpose में दोनो अलग-२

A

आदमी का Account
Saving Account

A Enterprises

Bussiness के नाम से एक account रखेगा
current Account - यह संस्था के नाम से रखता है
Check Book - A Enterprise के नाम से
sign के नीचे Bussiness stamp रहता जरूरी।

Study Tide

Bank loan - Bussiness के नाम से लिया जायेगा।
लेनदार - जिससे उधार लिया। Creditor
देनदार - जिनको पैसा देना होता है - Debitor

A | A Enterprises

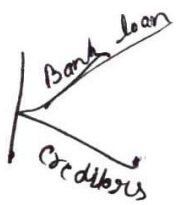

loan
10,00,000 का Bank और
लेनदार का
पर asset 3,00,000 का
किया 7,00,000 का

₹1,00,000 बाकी
बाकी पैसा A से claim करेगे
A का दायित्व असीमित है

तब तक pay होगा जब तक पूरा न हो जाये या court द्वारा दीवालिया न घोषित हो जाये।

owner का सब कुछ बिक गया
₹2,00,000 pay हुआ
5,00,000 बाकी
अब A को दीवालिया घोषित कर दिया जायेगा।

सकल स्वामित्व में साझेदो का दायित्व – असीमित है

2 Partnership – Min – 2 Max – 20 Banking – Min – 2 Max – 10

A
B

AB Enterprise
loss
₹ 10,00,000
- 3,00,000
₹7,00,000

Bank loan
creditors

तथा पैसा साझेदो से वसूल जायेगा।
साझेदो का दायित्व – असीमित

~~Atkinson, Garner, Va Malik~~

Study Tide

3 Company -

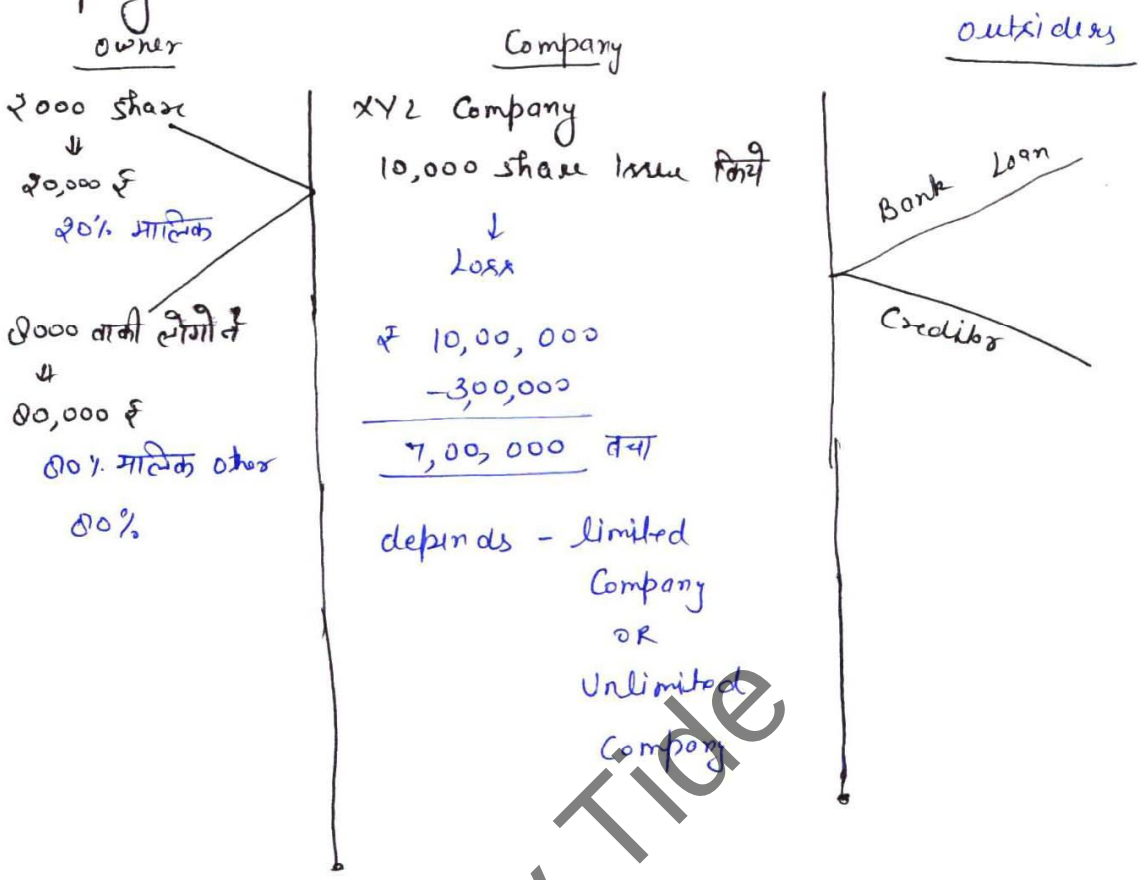

NPA → Non Performing Asset

⇒ New Partnership Concept – 2010 में आया

LLP (Limited Liability Partnership)

↓

जो पैसा अभी तक लगा चुके है वही उनकी liability है

पार्टनर को सीमित किया गया।

↓

इसका reg. अनिवार्य है

Study Tide

6- (5) → Subscription clause

↓

declaration of decision

इसमें sign करते हैं

ex. exam form के last का declaration

जो sign करते हैं – वो subscriber of Memorandum

~~करते हैं~~ कहलाते हैं

यही member of Company कहलाते

हैं (C.S. , C.A. , Advocate)

Articles →

Company की share की value यहां होगी

⇒ BOD के अधिकार यहां होंगी

Memorandum और Article बन जाने के बाद

form + memorandum + Article + Check of fee → ROC

↓10 दिन बाद

Company is Born ← कानूनी प्रक्रिया द्वारा एक artificial व्यक्ति का जन्म होता है ← Reg No जारी होगा

↓

We are promoter (जन्मदाता) of Company (प्रवर्तक) – Reg से पहले तक का सारा काम करने वाले लोग।

Pre Birth Expensive – Promotor को ही करना होता है

⇒ Contract – 2 alive person के बीच होता है

⇒ Promotor को company share देती है इसे preliminary expenses को compensate करने हेतु

Study Tide

~~Management~~

Memorandum - 6 clauses

Name Clause - Name of the Registered entity ie your Bussiness/ Company name (name should end with 'limited')

Registered office clause - Registered office clause

Object clause - Aims and objectives of the company

The Association clause - Information about its first shareholders and numbers of shares allocated to each of them.

The Capital clauses - share capital, minimum paid up capital etc

The liability clause - clause about its limited liability. State the liability of each member.

Study Tide

10-8-2015

Management

Promoter खुद या जिसे चाहे उसे management team में रख सकते हैं उसमें सारे qualified तो यह जरूरी नहीं यह कामचलाऊ टीम proposed team या प्रस्तावित टीम कहलाती है। (proposed team of management)

↓

जब share holder आयेंगे फिर वो decide करेंगे कि team रहेगी या नहीं। अब तो company के employee हैं

Public Company

बहुत बड़ी

share public को

↓

World economy उसके सम्बन्धित

उसके न रखना चाहे तो बेच सकते हैं

Private Company

छोटी

share अपने जानने वालों को

private लोगों को

(Black Money को white करने का best तरीका है)

अगर हम उसका share वापस कर नहीं रखना चाहते तो उसे किसी और को बेच नहीं सकते

Study Tide

Public Sector - 51% share - government के पास
यह public company से बिलकुल अलग

Public Company :-

पैसा चाहिये → तो share बेचे जायेंगे → यह BOD द्वारा decide किये जाते है → 1 Company में 3 Board of director होते है according to Company law → maximum BOD के लिये rule नही है क्योंकि बडी कम्पनी चलाने को बडा BOD चाहिये। → यह decide करेंगे कि काम को 1,00,000 ₹ sufficient हर share 10 ₹ → यह news public को advertisement द्वारा बतई जाती है → लोग उसके लिये apply करेंगे खरीदेंगे नही। (जब share को IPO कहते है Initial Public Offer - जब पहली बार share issue है) → बाद मे भी share issue कर सकती है तब उस share को FPO (Follow Public Offer कहा जाता है → share के साथ prospectus जारी किया जायेगा। उसको offer document कहते है (all info are included) → कम्पनी का पहला prospects ROC के पास जमा होगा।

Prospects गलत प्रस्तुत करने पर SEBI कम्पनी पर रोक लगा सकती है
DLF Company Case ↔ उस case में हुआ।
⇒ गलत info देने
⇒ Information छुपाना } गलत prospects

अगर share कोई न खरीदे तो पैसा नही आयेगा उसलिये known promoter का नाम डाला जाता है। (promoter - 1 person, 1 gp. etc)

Tata - तनिक 30 से आया
Taj gp business
Air Asia
Tata Steel

Tata gp
Adani gp
Reliance gp

Study Tide

यदि known promoter न मिले तो option I

Underwriting ~~Underwriting~~ (अभिगोपन)

Underwriting में guarantee दिलवाई जाती है किसी underwriter द्वारा → जितना share बिक गया तो ठीक बाकी यह underwriter खरीदेगा। → सारी जिम्मेदारी underwriter की है underwriter का काम शेयर Broker करते हैं Main Broker share Market में होता है और sub broker हर city में ⊕ jawkar

अब underwriting का Organizations कर रही है — Banks (Indian, Foreigner)
↓
IDBI

IDBI - Industry B' field का King
ICICI
HDFC

Master of Underwriter → specialized → Merchant Bank
deals with organization

⇒ Maximum commission 5% — underwriter का

अगर underwriter न मिला तो और Promoter भी नहीं तब company कागजों में रह जायेगी (भारत में लगभग 1.25 लाख company रजिस्टर्ड है)

↓
Defunctional Companies
Defunct Company कहलाती है — popularly

⇒ last year SEBI ने कदम उठाते हुए इनको हटाया जायेगा क्योंकि यह 1.25 लाख नाम घेरे बैठे हैं इनका death process शुरू हो गया।

Study Tide

हमारे share बिक गये ⟶ bussiness शुरू होगा पैसा invest होगा।

Public Company का share holder Meeting

3 types

1- वैधानिक सभा (~~Statiche~~ Statutory Meeting)

2. वार्षिक सभा (Annual general Meeting (AGM)) } Private में यह दो होते ही only

3. असाधारण सभा (Extraordinary Meeting) Meeting in emergency

Statutory Meeting - हर public या company के life की first meeting

यह share बेचने के बाद पहली बार होती है immediately के share बिकते ही

↓

इसमें BOD - share holder को company के development के बारे में बताते हैं और पूछते हैं satisfied हैं या नहीं यदि नहीं तो change करो ⟶ इसमें BOD को improve करना main काम होता है।

AGM → Main , साल में 1 बार

2 AGM के बीच Maximum 15 महीने से ज्यादा नहीं

दुर्घटना होने की case में ROC max 3 महीने की छूट दिए सकती है

तो Normal — 15 , Extraordinary — 15+3 = 18

→ Taxation का आधार annual होता है → 1st April से 31st March

⇒ बहीखाता तैयार होता है - Balance sheet

Profit Loss Account } Account final होगा

Study Tide

31 March

↓

31 May को BOD ने Final Account तैयार कर लिया सारी branches से

↓

यह BOD को दी जाती है

Bank को दी जाती है

Tax लगाने वालो को

GOI को भी है। Government of India

Share holder को भी चाहिये।

↓

final Account को तब तक valid, Authentic नही माना जाता जब तक CA के द्वारा Audit न हो।

↓

CA का appointment Share holder करेंगे। → यह भी CAG को report करेगी।

↓

Public Sector मे Auditor की नियुक्ति CAG करता है

31st May

↓ Audit finish

31st July

↓

Audited final Account आयेगा। – पूरी दुनिया इसका use करती है

↓

AGM का process शुरू होगा।

↓

ROC की permission से AGM की meeting date fix होगी।

↓

सभी share holder को notice + Audited final Account की Report भेजी जाती है

Study Tide

AGM की meeting होगी फिर decision लिये जायेंगे।
(यह बहुत मायने रखता है। भारत में शुरुआत होती है)

Divident Decision — Main Decision
लाभांश

↓

बचे हुये लाभांश में कितना distribute किया जाये और कितना इनके व्यापार में लगाया जाये।

↓

यह अधिकार BOD को दिया गया

↓

AGM में पहले decide होगा कि कितना बांटा जाये।

↓

इसके लिये Board meeting होती है (Company law के According हर quarter में 1 बार - साल में 4 बार)

↓

decision लेकर Media में घोषित किया जायेगा।

↓

AGM में share holder इसे improve करेंगे तभी payment होगा। इसमें change करने का अधिकार share holders को नहीं पर घटाने का है।

Extraordinary Meeting → जरूरत पड़ने पर होती है

Satyam घोटाले के बाद → immediate meeting बुलाई गई share holder की

Study Tide

Types of Share

1- Equity Shares / Ordinary share समता अंश वाले शेयर

↓

इनका dividend rate fix नहीं होता (1- ∞)

↓

अगर कुछ बचेगा तो मिलेगा

2. Preference Share पूर्वदेय शेयर

↓

वरीयता दी जाती है (2 case)

In case of dividend लाभांश

↓

पहले लाभांश इनको जायेगा उसके बाद equity shareholders को

↓

profit न हो तो किसी को नहीं मिलेगा।

↓

इसमें dividend का rate fix होता है

In Case of closing Company

↓

Asset बेच कर पैसे इकट्ठा होंगे

↓

Outsiders का payment के बाद वरीयता preference share holder को मिलेगा।

↓

इनको Vote देने का अधिकार नहीं

⇒ Equity share holders को Voting Right हो Meeting में No calling (Equity ही popular है)

Owner

⇒ Preference share – 8 types

1 popular- Convertable Preference Share

↓

Selected time बाद यह equity share में change हो जाता है

Study Tide

Memorandum में Capital clause में share बताने पड़ेंगे।

1,00,000 equity share of rupees 10 each — ₹ 10,00,000

5,000 15% preference share of ₹ 100 each — ₹ ~~50,00,000~~ 5,00,000

Total Authorized Capital - 15,00,000

Debenture ऋणपत्र → share की तरह जारी होता है

loan के nature का होता है from public

साधिकाना हक नहीं

यहाँ return अनिवार्य होगा क्योंकि loan public से लिया है तो Interest देना पड़ेगा।

↓

इसमें terms & Condition पहले ही clear होती है

↓

10% debenture

⇒ Debenture — 2 types

↓

one type → यह अ selected time बाद यह equity share में change हो जाता है

Short-term Loan

↓

अगर loan 1 साल में वापस देना

Long term Loan

↓

practically India में loan long term होता है

Bonds → Contract

इसके जरिये भी loan लिया जाता है Long term

Technically Debenture & Bonds are same

⇒ Debenture convertable है equity में, लेकिन Bonds नहीं

Registered Company → Company के अलावा कोई अन्य संस्था जब public से loan लेती है तो Bonds जारी करती है यह

Study Tide

Registered Company $\xrightarrow[\text{public से}]{\text{loan लेगी}}$ Debanture जारी करेगी

Other Organization $\xrightarrow[\text{public से}]{\text{loan लेगी}}$ Bonds जारी करेगी।

→ सबसे ज्यादा Bonds Indian gov. जारी करती है।

~~National~~ ~~De~~

किसान विकास पत्र
इंदिरा विकास पत्र
} सरकारी Bonds

2014 की नई सरकार किसान विकास पत्र को redesign करके फिर लाया कर रही है।

Europe → Crisis of Confidence (सरकार में विश्वास नहीं)
वर्तमान स्थिति सरकार के Bonds में नहीं)
(ज्यादा खतरनाक)

America → Demand Supply Crisis (कम खतरनाक)
Real Crisis

⇒ पूरी दुनिया में करीब 150 loan जारी हुआ।

Zero-Coupon Bond → Indian
ब्याज पर – 0%
लेकिन यहां return मिलता है। Higher rate of discount पर जारी होते हैं

100 ₹ face value पर 40% discount
↓ 5 साल बाद
100 ₹ वापस (तो 40% discount का फायदा होगा) पर)

Study Tide

प्रतिभूति — Equity / Ordinary Share
Securities — Preference
↓ — Debenture
Government Securities — Bond
Private Securities

~~प्रतिभूति~~ कोई विशेष name नहीं।

सरकार द्वारा जारी Bond — Sovereign Bond — किसान विकास पत्र आदि
पूरी दुनिया में (~~संप्रभुता~~ Bond)

↓

⇒ Europe - Sovereign debt Crisis

Quasi Sovereign Bond → ~~किसी~~ इससे कंपनी द्वारा जारी पर सरकार द्वारा समर्थित

↓

Quasi / partial

↓

वैसे कंपनियां ~~quasi~~ ~~so~~ ऐसे bond जारी करेंगी।

Financial Investment / Asset	Real Investment / Asset
1. Equity Share	Land
2. Preference Share ⇒ FPI	Building
3. Debenture	Plant ⇒ FDI
4. Bond	Machine

दोनों Investment जरीवे के इस्तेमाल को तोड़ने की जरूरी।

Study Tide

11-08-2015

Share तीन तरह से निर्गमित होता है - Issue of share

1. At par समतुल्य -
2. At a premium प्रीमियम में जारी करना
3. At a discount

At par - 10 ₹ का share 10 ₹ में ही issue होगा
face value के बराबर

At a premium - जिन shares की demand ज्यादा है अपने share की face value के साथ extra value जोड़ देते है

10 ₹ + 5 ₹
face value premium

Company Law ← C.L. कहता है premium की no limit depends on Company.
अगर निवेशकों को deserving price न दी तो investor वहां नहीं खरीदेंगे

dog
cat ⇒ good will is best asset in bussiness
Rat ↓
~~Sell~~ Sale बढ़ता है
Profit Margin बढ़ता है

Q H.W - dog goodwill
cat goodwill
Rat goodwill
} ?

Study Tide

Section 78 of Company Law

Premium का पैसा केवल 5 purpose में use हो सकता है और यह अलग account में रखा जाता है

⇒ premium का पैसा authorized capital से ज्यादा होगा तो यह ~~~~ Capital Clause का उल्लंघन नहीं होगा।

at discount → जिन companies के पास promoter और good will नेक न है या कोई good will न हो वह discount दे कर share जारी करते है

Reliance - Vimal Suit इनकी company है

Investment decision ⇒ BOD decision लेगा। कि पैसा कब कहाँ लगाना है

Financing decision ⇒ कैसे investment finance किया जाये supply कहाँ से आयेगे यह भी BOD decide करेगा।

⇒ undistributed profit - best option profit के बाद जो पैसा बच जाये। वह निवेश में लगाया जाता है

↓

अगर यह पर्याप्त नहीं तो share, debenture जारी कर सकते है

↙ share जारी करे जायेगे तो बड़े share holders का company के पकड़ कम होगी

10,000 + 10,000 = 20,000

20% ↓ 2000

10% ↓ 2000 सारे

~~2000~~ 0

↘ debenture में कर्ज है पर share वाली problem नहीं होगी

Study Tide

लाभांश = 50,000 10,000 लोगो के बीच

divident per share $\frac{50,000}{10,000}$ = 5 ₹ लाभांश 50%

अब 20,000 share

$\frac{50,000}{20,000}$ = 2.5 ₹ लाभांश ↓ 25%

divident कम होने पर market मे share की demand कम होगी।

Solution ⇒ Right Issue या Right Share Problem ~~होते है~~
↓
इस puzzle को कि share जारी करे या debenture ?

यह पहले से मौजूद share holders को दिया जायेगा।

↓

Right share (Equity Share)

10,000

20% | 2000

5000 Right share

तो company हमे 20% share जारी करेगी हमको 5000 का 20% 1000 share offer किया जायेगा। फिर हमारी choice पर है हम खरीदे या नही।

Bonus Share ⇒ additional payment
केवल equity share holders को जारी होते है

Bonus Act 1965 - अगर किसी संस्था मे No of employee साल के दौरान 20 को touch कर जाये तो Bonus लाग करेगी। (Government & Private also)
Salary 10,000 से कम वही इस Act के दायरे मे आते है (8.33% अलग से दिया जाता है)

Study Tide

Salary 10,000 +

⇒ 0.33 से कम नहीं जाया दे सकते हैं

⇒ Yearly income पर दिया जाता है

⇒ एक employer अपने employee को कितना भी benefit दे सकता है पर 10,000 से ज्यादा वाले को भी दिया जा सकता है

Bonus share में existing share holders को free में share जारी करती है।

2:1 के ratio में Bonus share जारी करेगी

10,000 issued + 5000 जारी किये = 15000

↓ 20% ↓ ↓ 20%

2000 occupied 1000 हमें मिलेगा। 3000

⇒ Bonus share, Right share दोनों में share holders के voting right पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

Company की खूबी - ownership & Manajement में अच्छा संतुलन

drawback भी →

Sweat Equity share - BOD को जारी होते हैं

at a high rate of discount

BOD (employee) को owner के प्रति ज्यादा accountable बनाने को। (2% तक)

जवाबदेह

Study Tide

BOD बनने हेतु आपको share खरीदने होंगे → Qualifying Share
यह maximum 5000 तक हो सकते हैं

IP - Intellectual Property

BOD ↓ की
↓
Sweat Equity Share

अभी तक का सारा Primary Market में आता है
↓
Market for the first time
↓
पहली बार share बेचा गया।
Company ने बेचा — public को। IPO FPO

Secondary Market
↓
Share Market
↓
जो share public ही बेचेगी और public ही खरीदी।

Company को जब primary market से पैसा मिल गया तो share Market की जरूरत क्या? क्योंकि sale purchase public के बीच होता है। Company का यहाँ कोई लेना देना नहीं।

↓

Study Tide

Investment ← debenture → debt — Return – Compulsory
Investment ← equity → मालिकाना हक — Return – Condition

~~Return~~ → ~~Main~~
जब Invest करेंगे तो ध्यान रखेंगे – Return का (लाभांश का)
Safty का
लेखीलता Flexibility का
↓
कभी पैसे की जरूरत पड़े तो हम पैसा प्राप्त कर सके अपने invest से

Investment has to be flexible

२०१५ में किसान विकास पत्र शुरू – ब्याज – ८.७%
100 महीने बाद पैसा double (10 साल 4 महीने)
Tax फ्री है

⇒ इसमें flexibility नहीं है। time से पहले वापस नहीं मिलेगा।
लेकिन लोगों के पास २ विकल्प हैं
(i) Bank द्वारे सरकारी प्रतिभूति के आधार पर loan मिल जायेगा। (80-90% तक)
(ii) Bank पैसा देगा पर discounting करके, loan नहीं दो

अब अगर Bank को पैसे की समस्या है तो RBI के पास जायेंगे। RBI पुनर्कटौती करके Bank को दे देगा।

→ कटौती का concept Banking को flexible बना रहा है
जिस Rate पर कटौती या पुनर्कटौती होगी → Bank Rate
कटौती और पुनर्कटौती की दरों में अंतर time पर depend करता है

Study Tide

⇒ Lowest flexibility → Life Insurance

LIC अलग है → Life के Both sides को cover करता है।

⇒ ₹0,00,00,000 का insurance long time हेतु 20 साल हेतु

ECS - Electronic

⇒ LIC में पैसा death के बाद Nomini को मिलता है। 1 से ज्यादा Nomini हो सकते है। Nomini को बदल सकते है

⇒ Lock in period - 5 साल

शुरू का 5 साल LIC का पैसा खर्च नहीं कर सकते।

1 ~~Apr~~ Sep 2010 से 5 साल किया गया पहले 3 साल था।

5 साल बाद भी पैसा निकाल सकते है पर पूरा नहीं कितना निकाल सकते है यह LIC company बतायेगी।

Developed Country में LIC Policy बेची जा सकती है - Flexibility

⇒

Share बाजार की जरूरत

Bank ने share बेचा फिर investment किया। हमारे Financial Investment का Bank Real Investment करेगा।

Share खरीदने के बाद दुर्घटना होने पर पैसे की जरूरत हो तो हम B Company के पास जायेंगे पैसा मांगेंगे तो company को नीचे बेच कर पैसे देने पड़ेंगे company बंद हो जायेगी। यही flexibility share में मिलती है share Market में जाकर share बेचा जा सकता है और पैसा प्राप्त किया जा सकता है। हमारे investment को flexible बनाने के लिये share Market की जरूरत है

Study Tide

⇒ Company का share Market में कोई participation नहीं होता।

India में Share Market → २५ share Market

→ 1 Unique

२ Main < BSE – Mumbai
NSE – Mumbai

२२ – Regional

UP – Kanpur

Bihar – Patna

BSE → Bombay Stock Exchange (1875 का)

NSE – National Stock Exchange (1995 में नई आर्थिक नीति में develop)

1 Unique – ~~NCEX~~ – Multi Commodity Exchang (MCX)

→ Gold की trading होती है

→ share के अलावा अन्य चीजों की trading होती है

→ Dollar की trading होती है

⇒ हमारी trading किस Market में होगी Company decide करेगी Exchange में जाके list करवाना होता है साथ fee देना होता है

ABC Company ने BSE और NSE दोनो में listed करा लिया

↓

Listed Company → उसके share बिकते हैं

Share Market में public Company जाती है private नहीं जा सकती है

Study Tide

Unlisted Companies - वह public Company जो अपनी Company को listed नहीं कराती।

ex - Sahara

BSE - 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा Share Market हो गया No of listed Company के आधार पर

America
- Nasdaq - IT Company listed
- Dowjones - all other
- दुनिया का सबसे बड़ा बाजार व्यापार के आधार पर

Japan - Nikkio

china -

hongkong -

Study Tide

Share Market में कीमतों के बढ़ने और घटने का कारण

↓

प्रभावित करने वाले कारक Factors

- आर्थिक कारक Economic Factors → ↓ → demand & supply
- अनुमानित कारक Spaculation Factors → ↓ → Risky बनाता है
- अन्तर्राष्ट्रीय कारण International Factors

12/Aug/17

आर्थिक कारक :-

(i) demand & Supply

(ii) कम्पनी के performance का effect shares की value पर पड़ता है

(iii) divident - most important practically not legaly

well settled - Blue chip Company - Reliance

Growing Company -

Low Company -

⇒ Growing Company के shares में फायदा जायदा।

⇒ जो Company जितना % divident देगी उसके shares की मांग उतनी ज्यादा होगी और कीमते बढ़ेगी

⇒ बड़े कम्पनियां policy बनाती है कि हर साल अपने share holders को 20% divident देगी इससे good will बढ़ेगा।

↓

इसके लिये company जब ज्यादा फायदा होगा तब कुछ पैसा लेकर एक जगह रिजर्व कर दिया जायेगा - Divident equisation reserve

कम्पनी तिमाही result बनाती है और यदि पिछली तिमाही में फायदा हो तो paper में publish किया जायेगा और shares की मांग बढ़ेगी। goodwill बढ़ेगी।

अगर loss होगा तो बहुत छोटे में news आयेगी

सूचकांक -

1995 - ₹ 10 - चीनी

1996 - ₹ 12 ₹/किलो

1997 - ₹ 15

1990 - ₹ 20 ₹

↓ 20%. ↑ 50% 25%.

Study Tide

सूचकांक के लिये एक Base year लेते हैं।
माना 1995 को Base year लिया फिर इसके ही आगे के year का comparison करेंगे।

			सूचकांक	
1995	—	₹ 10	100	← Value मानी, सूचकांक माना
1996	—	₹ 12	120	
1997	—	₹ 15	150	) — 30 point की बढ़ोतरी
1998	—	₹ 20	200	) 50 point की बढ़ोतरी
2015	—	₹ 40	400	

(i) BSE – Base year पुराना – BSE का Base year → 1977-78
(ii) NSE NSE का Base year → 1995

⇒ सूचकांक – कीमत बढ़ी या घटी यह जानते हैं
– सरकार भी policy निर्धारित करती है
→ महंगाई भत्ता – महंगाई के कारण salary same रहने पर भी क्रय शक्ति में कमी होती है तो हमारा loss कम करने को दिया जाता है

→ Tax लगाने में भी सूचकांक use होता है
माना। जमीन 1970 में 100,000 में ली
और 2015 में 50,00,000 में है तो कितना Tax लेगा
सरकार पता करेगी सूचकांक से कि 1970 में 1,00,000 की value आज के 36,00,000 के बराबर तो सरकार 14,00,000 पर tax लगायेगी।

Study Tide

⇒ माना 10 Kg चीनी use की पर के
↓
50 पैसे 1 Kg बढ़ा

1 Kg नमक use किया
↓
2 ₹ किलो बढ़ा

इसके ज्यादा effect पड़ेगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है **भार ज्यादा** है

⇒ भार या quantity भी price के साथ matter करता है

⇒ जिन चीजों का हम use नहीं करते उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका weight हमारे लिये 0 है

⇒ सूचकांक — कीमत, भार — दोनों का ध्यान रखते हैं

BSE Vs NSE

└ दो main सूचकांक
- listed सभी कम्पनियों के price और भार share की value और मात्रा
- India के Top 30 कम्पनियों की कीमतों को लेकर सूचकांक बनता है (कीमत और भार लेकर)
↓
SENSEX

NSE

└ India के Top 50 कम्पनियों की कीमतों को लेकर सूचकांक
↓
NIFTI

⇒ किसी देश के financial health का indicator - share बाजार

Study Tide

अनुमानित कारक

⇒ अनुमानो के आधार पर चलता है - Share Market

⇒ यहाँ demand supply का rule follow नहीं करता।

⇒ यहाँ मांग का नियम काम करता है

⇒ माना कोई share 100 ₹ आज और कल 150 ₹ हो गया तो मांग कम होगी या ज्यादा ?

↓

1 व्यक्ति अनुमान लगाता है दाम कल और बढ़ेगा — खरीदेगा। - Bull आशावादी

1 " " " " " " और घटेगा — बेचेगा - Bear निराशावादी

खिवाली का दौर ↑ — ↓ बिकवाली का दौर

हिजड़िया

मंकड़िया

⇒ India का Biggest Market — BSE

↓

Bull Statue

Study Tide

⇒ 1991 - Open the door policy

⇒ India में Consumer weak है और producer बहुत powerful हैं।

↓

क्योंकि awareness नहीं है

Qu ⇒ Supply chain Management — consumer ← तीन के जमाखोर — producer

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था - चिरस्थायी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था

(विकृत रूप)

↓

जनता का शोषण कर रहे हैं

Bata - Italy (90 देशों में व्यापार)

⇒ ~~संसार~~ अनुमान के आधार पर Speculation Inflation आती है

↓

अनुमानित महंगाई

⇒ अनुमानो के आधार पर सबसे ज्यादा चलने वाला बाजार – भारतीय बाजार

हर्षद मेहता घोटाला –

4-5 लाख करोड़ ₹ mange किये
गलत तरीके से Bank से manage किया
4-5 कम्पनी के share को Target किया
Acc umunt को target किया 1 share = 3000 ₹
अलग अलग नाम अलग जगह के ac Bulk के share खरीदा
share Masket में रोज दाम बढ़ा उसने रोज खरीदा रोज दाम बढ़ा।
10-15 दिन बाद भारत के आम लोगो ने भी अनुमान लगाया देखा।
अगले दिन फिर बढ़ा।
⇒ 4500 तक rate आ गया। सब पुरा India अनुमान लगा रहा था कि rate बढ़ेगा।
⇒ फिर demand public ने की 15 दिन बाद 1 share = 13500 ₹
⇒ हर्षद मेहता ने सारे share बेच दिया।
उसके उसके बहुत फायदा हुआ
(यह अनुमान के आधार पर था)

~~Internati~~

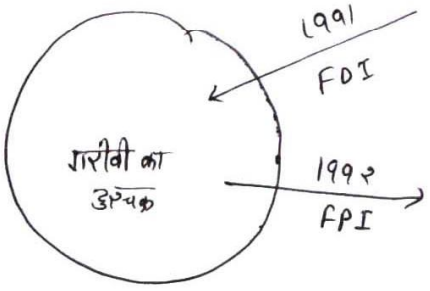

1992- Pepsi
1995- Coke

Limca – Indian – coke
Thums up – Indian – coke
Camca cola - Indian – coke
Gold Spot - Indian -

Study Tide

क्योंकि वैश्वीकरण मे प्रत्येक कम्पनी को अधिकार है कि वो वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभूतियो को बेच सके और कोई देश मना नही कर सकता क्योंकि यदि कोई मना करेगा तो उसके लिये आगे आना मुश्किल होगा। और भारत जैसे इतने बड़े बाजार मे कोई कम्पनी आने का मौका खोये उसकी संभावना कम ही है अन्तराष्ट्रीय बाजार मे पूंजी काफी थी और सस्ती थी।

Foreign Direct Investment - विदेशी कम्पनियो को भारत मे आके व्यापार करने देना जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़े।

Foreign Portfolio Investment - भारत की प्रतिभूतियो को कही भी जाकर बेच सकता है International Market को और उस पैसे को भारत आकर invest कर सकती है companies.

Study Tide

Goodwill is a type of intangible bussiness asset. It is defined as the difference between the fair market value of a company's asset (less its liabilities)

Types -

The cat who stays faithful to the location and not the person.

Cat goodwill is adherent.

Cat goodwill is most valuable

Ex- hotel, restaurent and petrol stations

The dog who stays faithful to the person and not the location

Dog goodwill is personal

Dog goodwill is unsalable

ex a photographer, chef etc

Rat is casual and attracted to neither person nor the location

Rat goodwill is fugitive

Rat goodwill is valueless

यह mix goodwill है न तो व्यक्ति पर आधारित न ही संस्था पर।

SENSEX → 1978-79 base value is 100.
domestic & international both market

NIFTI → 3 Nov 1995 base value is 1000

Study Tide

Red Notice - Nated Notice A series domestic & International both

Blue Notic - enquiry Notice B Series

Green Notic - Warning Notice C Series

Black Notic - It is to circulate information about unidentified dead bodies or deceased person who were probably using false identities (D Series)

E Series (Stolen Property)

Orange Notice - A copy of each notice prototype is available at Interpol Global Communications.

Light Blue cornered notice — ~~by~~ issued by DRI [Directorate of Revenue Intelligence]

Blue Corner Notice — is issued in cases of economic offenses

Red Corner Notic - warrent to arrest (interpal गिरफ्तार करता है)

Study Tide

Free Floating Share -

Free Flat Methodalogy ? - सभी बड़ी कम्पनियाँ यह use कर रही है क्यों? और क्या है?

Market Capitalization - Value of share x No. of share issued
current share price by company

Base Year choose करने का आधार ?

Study Tide

13/8/15

International

1992 से पहले विदेशी निवेशकों को पैसा लगाना allow नहीं था लेकिन 1992 के बाद भारत की कम्पनियों में विदेशी पैसा allow कर दिया गया।

⇒ विदेशी कम्पनियाँ जब विदेशी कम्पनी अधि के तहत Registered होती हैं जब वो भारत आती हैं तो उनको दोबारा Reg नहीं कराना पड़ता

MOU → वो Memorandum की एक copy ROC के पास जमा करती हैं और Gov के साथ MOU sign करती हैं terms & Condition वाली

⇒ Memorandum of understanding

↓

terms & Condition निश्चित (भारत सरकार निर्धारित करती है इनको दोनों को मानना अनिवार्य

⇒ अगर कम्पनियाँ अपनी मर्जी से जायेंगी तो government compensation नहीं pay करेगी। लेकिन अगर भारत सरकार कम्पनी को भगायेगी तो compensate करना होगा।

↓

वापस भेजेगी

⇒ Indian Company अपना share American Market में ₹ में ले जायेगी इनको America का RBI – Federal Bank में जमा करेगी। Federal Reserve Bank भारतीय कम्पनी के लिये $ में प्रतिभूति निर्गत करेगी जो वहाँ खरीदेंगे या बेचेंगे

American Depository Receipt → Federal Reserve Bank जब भारतीय कम्पनी से ₹ के अंकित share लेकर $ में अंकित प्रतिभूति जारी करेगी जो ADR कहलायेगी।

A.D.R.

Study Tide

यही काम वह Europe के Market में भी कर सकती है

Europe में दो currency - euro, dollar

Europe के ~~Bank~~ बाजार में इसका नाम Global Depository Recipt G.D.R.
(~~डॉलर~~ $ & euro दोनों में होगा) होगा।

और विदेशी कम्पनी भी भारत में यही करेगी - Indian Depository Recipt I.D.R.

यह कम्पनी और निवेशकों के बीच खरीद होगा

↓

यह आयेगा Primary Market में। IPO - Initial Public Offer

⇒ भारतीय कम्पनी का A.D.R foreign में बिकेगा क्योंकि यह growing company है और यह पैसा भारतीय कम्पनी भारतीय बाजार में निवेश करेगी और यह पैसा भारतीय ~~का~~ बाजार में आयेगा।

⇒ 1991 के बाद A.D.R और G.D.R की सहायता से विदेशी ऐसे देश में पैसा लगा सकते थे जो तेजी से बढ़ने वाला था

⇒ A.D.R
G.D.R } equity

FCCB - Foreign Currency Convertable Bond

↓ बाद में equity में change ↓ debenture nature

यह RBI ने India के बाहर जारी किये dollar में विदेशियों (पूरी दुनिया) से loan माँगा)

RBI को dollar में loan मिला। dollar बढ़ा और भारतीय कम्पनियों को ₹ में loan दिया गया।

Study Tide

अब भारतीय कम्पनियां direct loan ले सकते है

Metro development — Japan से soft loan
(कम interest और long term)

भारतीय कम्पनी भारतीय बाजार में debenture जारी करती है
लेकिन विदेशी बाजार में Bond जारी करती है

↓ ~~अगर~~ Reliance पैसा loan लेके invest करेगी

भारत में → RBI के पास विदेशी मुद्रा रिजर्व बढ़ेगा

भारत के बाहर → RBI की कोई भूमिका नहीं

External Commercial Borrowing — भारतीय कम्पनियों / सरकार } Bond विदेशी बाजार में जारी करना

बाह्य वाणिज्यिक उधार

निवेशक
- Personal व्यक्तिगत — LIC करवाना
- संस्थागत — LIC का Invest करना

Share Market को open किये गये विदेशी निवेशको को flexibility देने के लिये। अन्यथा हमारे कम्पनियो के share कोई नहीं खरीदता।

तब से share बाजार में International effect पड़ना शुरू हुआ।

1992 के बाद हमारा Share Market Volatile अस्थिर हो चुका है।

Study Tide

विदेशी निवेशक भारी मात्रा में share खरीदते बेचते है इसलिये share Market में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है।

यहां पर भारतीय छोटे खरीदारो की value शून्य दर्शाक की है जो Market ऊपर नीचे होने का wait करते है

निवेशक भी अनुमान लगाते है और दुनिया के बाजारो को प्रभावित करते है

Share Market पर शिकंजा कसने को 1992 में SEBI आया।

⇒ सारे transaction SEBI के under में हुये

⇒ अगर Market fluctuate करता है तो SEBI check करता है legal कारणो से वहा या अन्य कारण से

⇒ Share Market में SEBI Most Powerful है

वह किसी company को रोक सकता है share बेचना खरीदना रोक सकता है

⇒ जो Company unlisted है क्या वो SEBI के under में आये?

ex. Sahara ने debenture जारी किये यह एक Public कम्पनी थी कहा गया पैसा लगाये आपको 5-7 साल बाद पैसा मिलेगा। इसमे आपस में sale purchase की संभावना कम थी इसलिये listed नही कराया यह आया कि ₹5000 करोड़ का loan public ने दिया। असल में public से 5000 करोड़ आया बाकी fake investors से 20000 करोड़ आया - Black Money को White में convert की कोशिश) 5-7 साल बाद पैसा वापस नही दे पाये तो असल investors High Court गये। फिर Sahara supreme Court गये और कहा हम unlisted है तो हम SEBI के under में नही आते। तब Supreme Court ने आदेश दिया - कि SEBI ~~unlisted~~ Sahara की भी जाँच कर सकता है

Study Tide

और प्रोडक्ट सामने आया।
फिर SEBI ने Unlisted Company की जाँच शुरू की

New Topic

विदेशी पूँजी और भारत का विकास

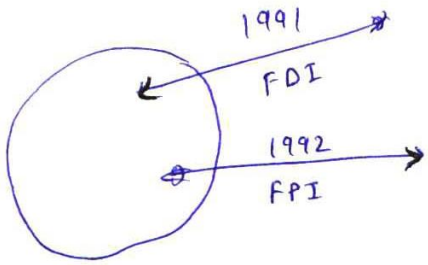

FDI - Real Investment
FPI - Financial Investment

FDI

Capital
Technology
Entrepreneurship
} तीनों आते हैं भारत में

इनका प्रयास होता है मेजबान देश में लम्बे समय तक रुकने का
इनकी मजबूरी होती है बीच से वापस नहीं जा सकते
रुपार्ई हो
ENRON कम्पनी 90 के दशक में महाराष्ट्र आयी थी फिर वापस गयी
time से पहले तो उनका investment हट गया।

FPI

Capital आता है
Capital involvement के कारण अत्यन्त अस्थिर। कभी भी लगाये कभी भी निकाल ले
↓
HOT MONEY
↓
क्योंकि यह एक जगह टिकता नहीं है
इस पर firm grip नहीं होती।

Study Tide

Online Trading -

सबसे पहले एक Account Opin करना होगा - Demat Account

electronic form में प्रतिभूतियाँ save की जाती हैं
पैसे नहीं होते

जिस संस्था में DA. खुलेगा वह संस्था - Depository Participant (D.P.)

↓

बहुत से लोग, Bank उसका काम करते हैं

Bank — Primary function - saving जमा करना, loan देना (essential)

Secondary function - all other. (non - essential)

(primary function करेगा तभी Bank कहलायेगा otherwise नहीं।)
but Secondary जरूरी नहीं

⇒ IDBI, ICICI, Axis, HDFC } D.P. in India

Angle Share खान } अन्य संस्थायें D.P.

⇒ एक Demate को ~~Saving~~ Account से जोड़ा जायेगा।

⇒ यह DP हमारा Broker है हम Direct नहीं कर सकते DP के through करेंगे

⇒ हमारा purchase order direct share बाजार नहीं जायेगा DP लेके जायेगा और DP SEBI की permission से ही जायेगा। इसीलिये DP SEBI के पास listed होते हैं

⇒ फिर हमको software दिया जायेगा password मिलेगा
9:30 - 3:30 तक trading

⇒ माना हमने 200 ₹ के 100 share purchase का order दिया यह order DP के पास जायेगा। तो हमको DP का Broakage देना होगा।

Study Tide

⇒ हर DP का brokage अलग अलग (लगभग 10 ₹)

⇒ खरीदने बेचने दोनों में कमीशन देना पड़ेगा।

⇒ Security Transaction Tax (S.T.T.) - 0.1% है यह government को देना पड़ेगा।

₹ payment + share value = ₹20000
+100
200
₹20300 ₹

↓
S.T.T.
+
brokage

Demat account में 100 share आ जायेंगे और ₹20300 कट जायेंगे account से

⇒ अब share बेचा - ₹50 rate पर 100 share बेचा
फिर बार S.T.T. और brokage minus होगा।

₹5000
-100
200
₹4500

₹4500
-₹20300
4200 ₹ profit

Intraanet Trading ⇒ पहले बेचते हैं तब खरीदते हैं
हम ज्यादा खरीदना चाहे तो DP loan भी देता है

Study Tide

Stop lock - एक निश्चित कीमत गिरते ही share automatic बिक जायेगा।
e/. 300 पर limit लगा दी

FP Investor -

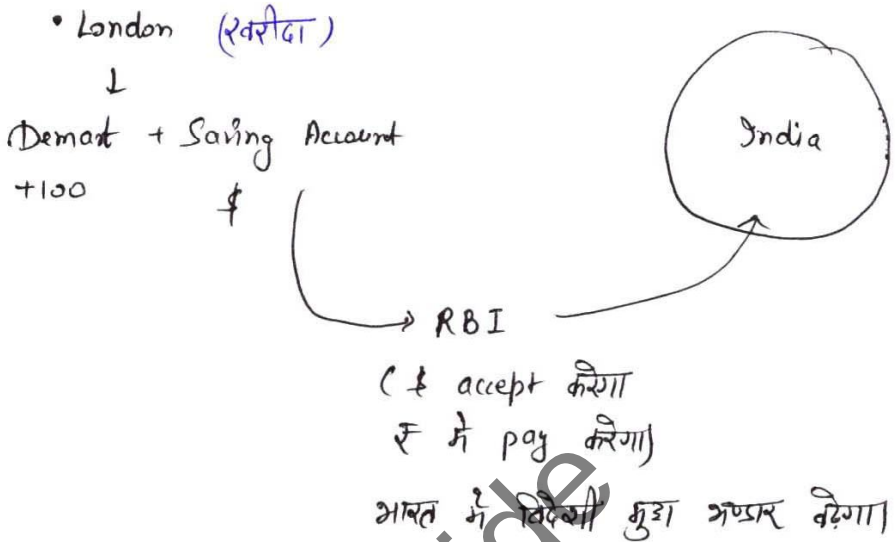

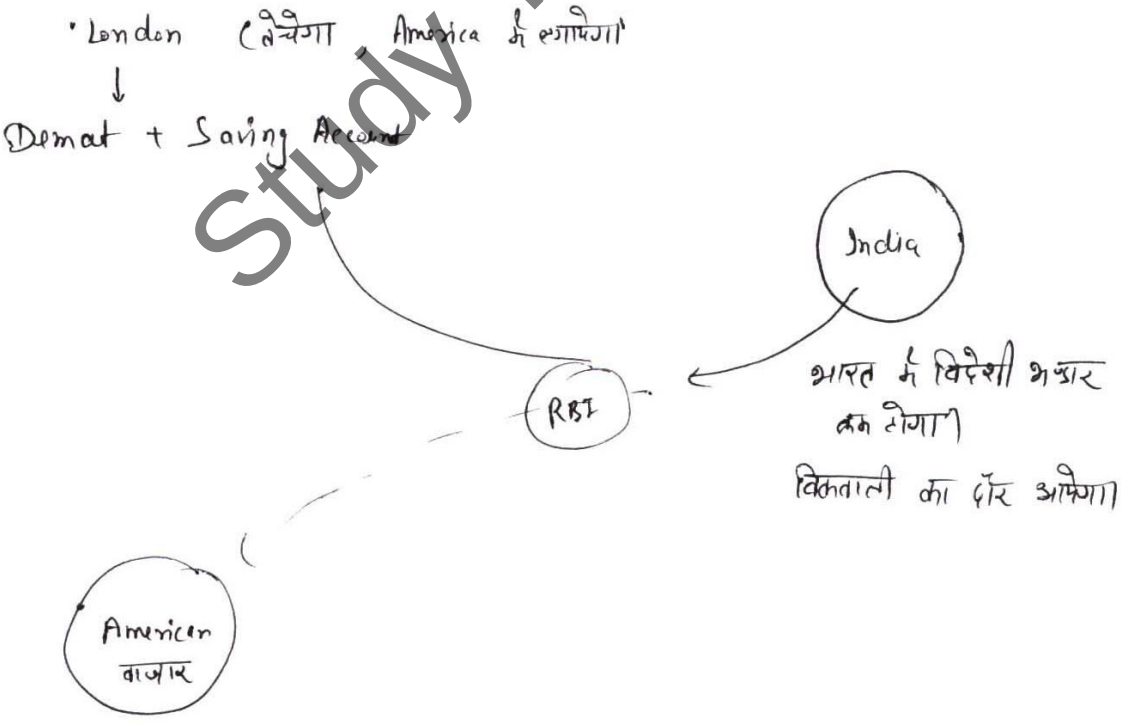

Study Tide

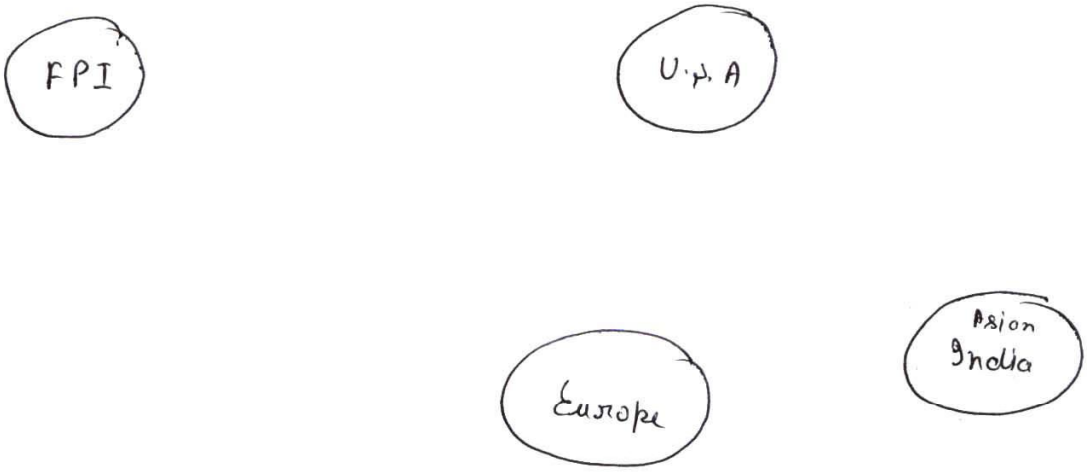

Mostly FPI Investor तभी आते हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है पर आर्थिक स्थिति कमजोर होते ही बाहर चले जाते हैं

America — Space research, War goods } Human Resource सबसे ज्यादा इसी पर खर्च करता है

⇒ America अपने casual जरूरत की goods पर खर्च नहीं करता

↓

Raw goods

↓

इनका वह आयात करता है ⇒ Main Trading Partner

↓

Japan, China, European Union

↓

इन का लगभग 40% production American बाजार में खपत

⇒ May 2011 में America में war expansences बहुत ज्यादा होने पर अमेरिका खजाना इतना कम हो गया कि केवल 1 week का खर्चा चलने लायक तब सरकार ने प्रतिभूतियां जारी की।

एक time में American President को unlimited loan लेने का अधिकार था। 1917 में इसे Canal में limited कर दिया गया।

Study Tide

⇒ May 2011 में यह limit 13.1 Trillian Dollor था

1000 000 - Million 10^6

1000 000 000 - Billion 10^9

1 000 000 000 000 - Trillion 10^{12} - America के GDP के 95% के बराबर था।

⇒ पर इतना already उधार लिया जा चुका था। तब Unal ने limit बढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा पिछले कई सालो से कह रहे थे कि War expanse कम करे पर नहीं किया गया इसलिये member नाराज थे Unat ने मना कर दिया। देश crisis में आ गया। इससे अमेरिका में मंदी का दौर आने की भरपूर संभावना थी। इससे सबसे पहला effect main 3 trading partner पर पड़ता और Japan में का 40 y. American बाजार में use होता था अब मंदी आ रही थी जिससे जापान से आयात कम हो गया और Sir plus बचने की वजह से निर्माण रुक गया उनके यहाँ भी मंदी का दौर आया। China और European में भी same effect। तब अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु Simplus को निकालना मजबूरी उसको निकाल कर भारत में dump किया-

Dumping → यह वर्तमान में भी समस्या हो

यह भारत को नुकसान पहुँचाती हो। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होती हो

China से dumping हुयी थी भी below cost पर।

WTO भी इसको गलत तरीके से किया व्यापार मानता हो इसके लिये Anti Dumping Duty का तरीका दिया WTO ने

भारत ने Tax लगाया और WTO की 1991 का Rule का उल्लंघन नहीं किया।

Study Tide

इन देशो ने भारत के खिलाफ 119 case किये यह कह कर कि हमारी उत्पादन लागत कम है यह Dumping नही। भारत की उत्पादन लागत ज्यादा थी पर उनकी आपत्ति भी यह WTO को कहा गया।

⇒ और तब Global Crisis का डर) पैदा हो गया। अंत मे बात उसी दुनिया को मंदी से बचाने की थी। फिर Conat ने Bill pass करके limit बढ़ाई ₹.1 Trillion Dollar पर शर्त लगाई कि Amerikan goremment को अगले 10 साल मे इतना ही खर्चो मे कटौती करनी होगी। और इसी का नतीजा 2013 से सरकारी खर्चे कम किये और अफगानिस्तान और अन्य देशो से सेना वापस बुलाई

⇒ May 2011 मे एक policy ~~आयी~~ - Fiscal - cliff लाया America

⇒ Fiscal - cliff - Crisis Solve करने के लिये इसे शुरू किया।

→ खर्चे मे कटौती } → इनको fiscal cliff नाम दिया।
→ Tax Rate बढ़ाया। } इनसे सरकार का घाटा कम हुआ

→ 2 साल बाद May 2013 सरकार comfortable हो गयी। उनकी Crisis Solve हो गयी

→ Tax बढ़ने से, खर्चा कम होने से बाजार मे सरकार की demand कम हुयी और Tax बढ़ने से लोगो के पास पैसे कम हुये। उनके बाजार मे demond कम हो गयी और फिर मंदी का खतरा मंडराने लगा।

FPI ~~Trade~~

USA

Europe

Asia

Study Tide

2013 में May में पूरी दुनिया crisis में थी India और Europe भी crisis में था यह Portfolio Investors के लिये बड़ी समस्या थी ऐसी स्थिति में निवेशक किसी बाजार में पैसा नहीं लगा सकते इसलिये वे safe mode में चले गये क्योंकि किसी भी बाजार में पैसा लगाते तो डूबता नहीं क्योंकि हर जगह मंदी थी तब इन्होंने gold में invest करते किया। पिछले 5 सालों में gold का return 10% के आस पास है मतलब share में No profit से तो यहाँ 10% मौजूद है इसके International Market में gold की value बढ़ेगी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दिवाली का दौर था। भारत सबसे ज्यादा gold का demond करता है और उत्पादन 0 है कोलार की खान थी पर उसमें profit लगभग खत्म होने के कारण उसे बंद कर दिया गया। FPI निवेशक gold खरीदकर safe mode में आ गया। तब भारत में gold की कीमत 34000 /10gm पहुँच गयी थी

Gold क्यों - माप में कम value में ज्यादा
यह colour change नहीं करता है

चांदी
⇒ value में ज्यादा, माप में कम
⇒ color बदल जाता है
⇒ chemical use करना पड़ता है

gold सबसे safe
इसको टुकड़े-टुकड़े करने से भी value में कमी नहीं आयेगी। Diamond के टुकड़े करेंगे तो value में कमी आयेगी।

⇒ America ने इस मंदी को ठीक करने को Federal Reserve Bank ने कदम उठाया →

QE3 - Quantitative Easing 3 third time - 2013

QE2 - 2010

QE1 - 2008

Study Tide

QE 3 → मांग को बढ़ाने के लिये

Bank देश के अंदर money supply बढ़ाई। By debentures & Bonds

Money supply - Bank से पैसा जब लोगों तक आयेगा तब बढ़ेगी। Market में आयेगा

कम्पनी लोगों के द्वारा लिये गये debenture और Bonds का पैसा चुकाना शुरू किया। सरकार time से पहले भी वापस कर सकती है

Call Option -

put Option - उधारकर्ता ने debenture खरीदा 10% ब्याज पर 5 साल के लिये 2 साल बाद other कम्पनियाँ 15% ब्याज पर loan दे रही है तब यह option अधिकार देता है कि debenture वापस करके पैसा ले सकते है

यह option लगाने पर कम्पनी कभी भी पैसा वापस कर सकती है loan को पूरा कर सकती है

Pre Payment - जब निश्चित समय से पहले loan चुका दिया जाये।

⇒ American gov. ने ~~put~~ call option use किया। तब ~~Amer~~ FRI ने decide किया कि QE 3 3 साल तक चलायेगी और 85 billion डॉलर हर ~~साल~~ महीने बाजार में लायेगी

⇒ June 2013 में - 85 million dollar आया - American Market

American Economy demand के साथ बढ़ती है

Indian Economy ~~dem~~ supply के साथ बढ़ती है

⇒ American बाजार क्या July में FPI निवेशक gold से पैसा निकालकर share में वापस आये और International Market में gold का दाम नीचे आ गया। भारत में दाम 26000 से नीचे आ गया।

Study Tide

⇒ जब American Economy मजबूत हुयी तो उन्होंने भारत में लगा पैसा निकालकर American बाजार में गया। Share market 700 अंक नीचे गया। और विदेशी मुद्रा भण्डार 300 बिलियन डॉलर से 270 बिलियन डॉलर पर आ गया। यही उन्होंने यूरोपीय बाजारों के साथ किया।

⇒ American Market में One way Traffic शुरू हो गया।

⇒ फिर सब निवेशक America पहुँच गये। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में dollar की

⇒ मांग बढ़ गयी। dollar की value बढ़ी (क्योंकि supply constant है।)

विनिमय दर
Exchange Rate - dollar की कीमत है

1 $ - 55 ₹ ⟶ 1 $ - 70 ₹ हो गया।

⇒ China की Policy Export Oriented है

↓

~~आयात~~ निर्यात

निर्यात आयात से हमेशा ज्यादा रहा

इसका विदेशी मुद्रा भण्डार बहुत ज्यादा है

China - 4000 बिलियन डॉलर

1990 - 1 बिलियन से कम

भारत - 355 बिलियन डॉलर
↓
present

Growth Rate Export - Growth बढ़ाकर export बढ़ाये

Export Rate Growth - export बढ़ा कर growth बढ़ाये

China का निर्यात कम हो रहा था तब China ने अंतिम emergency तरीका अवमूल्यन का अपनाया। जब export suffer करे तो यह Temporary relief देता है ~~+~~ 1 dollar = 40 yuan से

1 dollar = 50 yuan कर दिया गया

इससे ⊕ विदेशी सामान ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उन्हें कम कीमत में ज्यादा सामान मिलेगा। इसके currency में same रहेगा पर केवल dollar में कमी आयेगी

↓इससे भारत पर असर

भारत के सामान की मांग कम हो गयी और निर्यात भी कम होगा।

Study Tide

भारत के पास विकल्प ↴

भारत भी अवमूल्यन करे। भारत करेगा तो अन्तराष्ट्रीय बाजार में २ देशों की मुद्रा की value कम होगी। तब सत देश यही करेंगे। और dollar मजबूत होगा। यह गलत तरीके से व्यापार है पर WTO इसे गलत नहीं मानता क्योंकि यह देशों के भले हेतु।

⇒ भारत 100 ₹ = 160 ₹ नेपाल का

1958 भारत-नेपाल संधि - Free Movement

बिना Visa- Passport के व्यापार

Dollar मंहगा होते ही असर ↴

आयात - मंहगा -

निर्यात - 1000 $ निर्यात किया

$ RBI में जमा किया। पहले 1000 $ = 55000 था

अब 1000 $ = 70000 मिलेगा

निर्यातक की कमाई ₹ में बढ़ेगी।

NRI द्वारा भेजा गया पैसा - 71 Billion Dollar

↓

रेबुटेन्स

Rebutance

भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने में इनका सहयोग।

⇒ American Economy का पूरे world economy पर प्रभाव पड़ता है

अ ↓

शेयर बाजार ↓

विदेशी मुद्रा भण्डार ↓

आयात ↓

निर्यात ↑

सोने की कीमत ↓

⇒ Europe develop करेगा तो Euro की मांग बढ़ेगी। dollar की value कम होगी।

Study Tide

⇒ PPP Model - Public Private Partnership

1$ = 40
1$ = 4 1$ = 80
1$ = ₹

Crude Oil - Gulf Country

dollor मजबूत - कच्चे तेल की कीमत कम होगी।

⇒ America ने sale oil का बनाना बढ़ाया तो कच्चा तेल खरीदना कम हो गया। इससे Saudi Arabia पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा।

Russia का main income - Oil & Natural gas बेचना

⇒ कच्चे तेल का दाम घटना ↓

16 May 2014 - 116 $ / Barrel - 1 Barrel - 159 lt

International Market में 1 $ बढ़ेगा तो भारतीय कम्पनियों पर 8000 करोड़ का बोझ बढ़ा।

OPEC - घटते दाम को रोकता है। उत्पादन कम करके पर एक बार नहीं रोक पाया। सबसे अस्त्र निर्यातक सबसे बड़ा उसका निर्यात बन्द हो गया।

Problem- 80 $ / Barrel उनका extraction cost - America का उनकी Technology थोड़ी पुरानी। पर New Tec develop होती है Gulf Country पीछे में आ जायेगी।

⇒ दाम घटने से Russia की कमाई बहुत कम हो गयी। America ने इसको Russia को पीछे से use किया।

depreciation - demand supply के कारण से की value कम होना

अवमूल्यन = जानबूझ कर मुद्रा सस्ती करना।

Study Tide

First Time dollar की value तय होना ।

PPP - Purchasing Power Parity - Technique जिस की सहायता से First Value ~~set~~ करते हैं

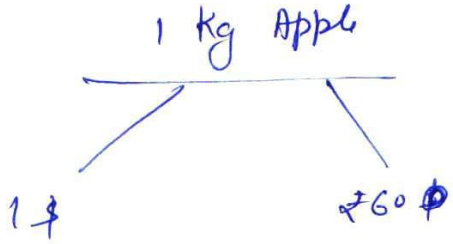

1 $ = 60 ₹

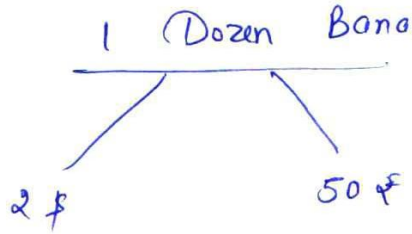

1 $ = 25

America वह वस्तु लेगा जो उनके यहाँ ~~महंगा~~ सस्ता है हमारे यहाँ महंगा।

1 $ = 60 ₹

⇒ Hamburger - Non-Veg Burger सबसे पहले लिया गया।

↓

America में बहुत सस्ता

India में बहुत महंगा

1 $ = 100 ₹ ex.

America Saudi

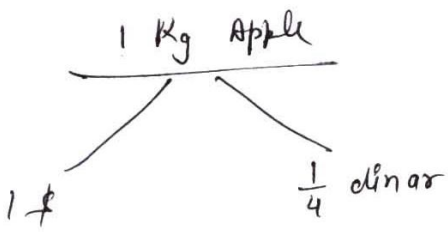

1 Dinor = 4 $

4 × 60

1 Dinar = 240 ₹

1 $ = 60 ₹

Study Tide

FPI निवेशको को Free Moremont available होने के कारण अस्थिर बनाया है इन्होंने दूसरी डलिया को।

⇒ 1992- FII of 1992 policy — Foreign Institutional Investors Policy 1992

- → विदेशी निवेशको हेतु नियम बनाये गये।
- ⇒ केवल संस्थागत निवेशको को भारत में निवेश करने की आज्ञा दी गई।
- ⇒ व्यक्तिगत निवेशकों संस्थागत निवेशको से ज्यादा अस्थिर होते हैं
- ⇒ केवल NRI – व्यक्तिगत निवेशको को अनुमति दी गई।

20 साल बाद

1 Jan 2012 - QFI का concept आया RBI का Qualified Foreign Investors

↓

इसमें व्यक्तिगत निवेशको को निवेश allow किया गया।

19 Mar 2014 - FII, QFI } इनको Merge करके RBI ने RFPI में डाल दिया

Registered Foreign Portfolio Investment

RFPI < 10% कोई एक निवेशक भारत की एक कम्पनी में 10 % से कम share खरीद सकते है

NRI

↓

10% होते ही FPI – FDI में आ जायेगा और Tax बढ़ जायेगा।

सारे inrestor मिलकर 24% खरीद सकते है

1 — 8
2 — 9
3 — 24-17 = 7

Total 24%

7

Study Tide

NRI — 1 NRI → 5% खरीद सकता है

Total NRI → 10% खरीद सकते है

1 NRI → 3
2 NRI — 5
3 NRI — 2
] Total 10%

1 भारतीय कम्पनी का 34% share विदेशियों के पास हो सकता है

RFPI — 24%
NRI — 10%
34%

⇒ हवाला Channel- काला धन हवाला चैनल से भारत से बाहर हो जाये फिर वही पैसा अलग निवेशकों के साथ भारत आये इस तरह Black — White में change किया जाए।

Round Tripping नाम दिया गया इसको

⇒ हवाला Network →

Swiss Bank - गोपनीयता Secrecy

Study Tide

IRDA - April 2000

18/8/2015.

Tax →

RFPI

NRI

Income tax Act 1961 → FDI पर निगम कर (Annual Basis पर)

1966-67 - April से शुरू होकर उससे पहले June था।

Total Income पर tax लगेगा

Income में income को 5 भागों में बांटा ।

Tax

(i) Income from salary (वेतन श्रमिक से प्राप्त आय)

(ii) मकान, संपत्ति से प्राप्त property (House Property)

(iii) Profit from Business and Profession

(iv) पूंजीगत लाभ (Capital gain)

(v) अन्य स्रोतो से प्राप्त आय

= Total Income

Salary - Annual ₹,00,000 (fix Salary) - gov / private

Home 0

Business 0

पूंजीगत लाभ 0

अन्य 0

₹,00,000 = Total

Income - ₹,50,000 तक छूट

उससे ऊपर tax लगेगा

Business / Profession - किसी भी चीज का व्यापार (वस्तु)

↳ Teaching - (सेवाये) → Income tax + Service Tax

asset < Real / Financial } Capital Asset

Study Tide

Asset बेचने पर profit - Capital gain — tax लेगा
loss - Capital loss — tax नहीं

⇒ अन्य - लाभांश पर tax , lottery , debenture
Miscellaneous Bank द्वारा interest पर tax

Building - मकान शीर्षक से प्राप्त आय :- ⇒

- बंद मकान
- किराया → Rent → Taxable
- स्वयं रहे → House Tax → (परन्तु exception अपवाद रुपये के form में कोई प्राप्ति न होने पर भी देना होता है) → Income Tax department tax नहीं लगाता
- मकान में व्यापार - house Tax में नहीं

Value Department Municipal Corporation लगाता है

⇒ law के अनुसार हर घर में क्षमता होती है आय का सृजन करने की
⇒ पहले Rent पर रहते थे 3000 पर फिर Bank से loan लेकर मकान खरीद लिया। उसके हमारी Salary 3000 से बढ़ गयी इस तरह real term में आय का सृजन कर रही है

⇒ एक ही मकान का एक ही शहर में अलग-2 value होगा तो उसका rental value अलग होगा

House tax से मुक्त - Offices gov. , Monument Building , Religious मकान , महल , Charitable Buildings , Union office

Job main
Capital gain :-

Capital Asset → Real, Financial

⇒ भारत में Loss → Taxable नहीं।

Study Tide

Real

Land

Building

↓

demand ज्यादा

supply कम

always profitable

Time limit - 3 year

↙ ↘

दीर्घकालीन पूंजीगत सम्पत्ति

↓

बेचने 3 साल या उससे से ज्यादा हमारे पास रहे फिर बेचे तो यह

↓

काफी profit Tax से benfit

↓

दीर्घ कालीन पूंजीगत लाभ

अल्पकालीन पूंजीगत सम्पत्ति

↓

3 साल से कम रहे तो यह

↓

काफी Tax

↓

अल्पकालीन पूंजीगत लाभ

Financial

Share

Debenture

↓

यहाँ पर Time limit - 1 year

↙ ↘

दीर्घ कालीन

↓

1 साल से ज्यादा रखकर बेचे

↓

Long term Capital gain

↓

0% Tax Rate

अल्प कालीन

↓

1 साल से कम रखकर बेचे

↓

Short term Capital gain

↓

15% Tax Rate

debenture - 5%

⇒ Share बाजार में stability लाने के लिये long term में छूट दी जाती है।

FPI - निवेशकों हेतु :

↓

1 साल से ज्यादा रहते → Tax 0%

1 साल से कम के लिये - Tax 15% ← 2 exception

↓

अगर मॉरीशस Route से आये या singapure Route से आये तो उनके लिये Shoort Term profit पर 0% tax.

Study Tide

⇒ Mauricus Route - ज्यादा profitable

40-50% भारत में निवेश इसी route से

(Total FPI का)

Capital के Movement को देश का Tax System Control करता है

Sony - Japan

2. G. - North Korea

⇒ 1991-92 भारतीय अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी।

Tax नियम कानून ज्यादा सख्त होने इससे निवेशक भारत नहीं आते।

और भारत को पैसे की जरूरत थी। इसीलिये Tax Rule ढीले रखे गये

Rate

निवेशको हेतु पूरा world एक market है

⇒ Round Tripping → Black - White Money

⇒ DP में रख गया जो निवेशक भारत सरकार के सामने अपनी detail बताना चाहे वो पहले clean chit, P Notes (Participatory Notes) प्राप्त करो

↓

इसके द्वारा निवेश करने वाले अपनी पहचान छुपा सकते है

1997 - P. Chidambaram ने बताया भारत में P Notes के through निवेश Total FPI का 65-70% था। (Open - Secret)

↓ फिर हंगामा किया गया (Gov. policy Black Money को White Money में convert करने का काम कर रही थी

↓

9.30 बजे P. चिदंबरम ने statement दिया - सरकार P Notes को खत्म करने की सोच रही है

↓

Share बाजार में बिकवाली शुरू हुआ

↓

Sensex 2000 तक गिर गया। विदेशी कुछ अरब कम हुआ।

Study Tide

फिर SEBI ने Market बंद कर दिया। P Notes Crisis - Self

↓

फिर statement आया कि ऐसा कोई खतरा नहीं

↓

फिर 1700 point सूचकांक recover कर गया।

↓

फिर भी 600 का घाटा हुआ।

FDI - Bussiness करने आते हैं उनके ~~Bussi~~ Profit पर Tax लगेगा (निगम कर)
profit from bussiness देना होता है - 40% Tax

FPI → उनका profit- Capital gain में 0% & 15%

Indian Company पर - पहले 30%
अब 25% (2019)

शेयर खरीदकर भी FDI होता है।

- एक बार में सारे क्षेत्र में FDI को मंजूरी नहीं दी गयी थी
- कुछ क्षेत्र अब भी ऐसे हैं जिसमें FDI की मंजूरी नहीं
- वर्तमान में भारत में FDI का 5 Rate

  26% →
  49% →
  51% →
  74% →
  100% → उसकी विदेशी कम्पनी अकेले आकर व्यापार कर सकती है

→ 1995 में Insurance में FDI को मंजूरी दी 26% हिस्सेदारी
अब 49%

→ 51% में भी Indian partner चाहिये पर share 49%.
74% - - - - - - - - - 36%

Study Tide

⇒ LIC - 1956 में गठन हुआ Market में दबदबा

⇒ LIC को छोड़ बाकी सभी Company । Indian । विदेशी

ICICI	prudential	→ Combinations
HDFC	———	1975, 03, 05 } Cricket World Cup – Britain में sponsored
Tata	AIG	
Birla	Sunlife → विदेशी	
Kotak	Mahindra	
PNB	Met life	
Bajaj	allianz	

⇒ FDI - 100% allow → automobiles field में
Hundai, Honda, Suzuki

→ Telecommunication
Vodafone,

→ Single Retail
Pepsi Coke, Rebook

Retail — Big Bazar

Hole sale
↓
FDI - 51%
↓
Walmart को
India में 10 outlet मिले
↓
पर holesal के लिये है
↓
49% share Bharti group के

Single
↓
1 वस्तु का

Multi Retail
↓
बहुत सारे वस्तुओं का
↓
Sep 2012 - 51% FDI allow
लेकिन विरोध हुआ लेकिन 3 साल बाद भी
Walmart नहीं आया।
↓
1st company आयी PSL

Study Tide

⇒ Rebook – 100% FDI – Single Retail

⇒ Hard drink बनायेंगे तो Single Retail से बाहर आ जायेंगे।

एक विदेशी निवेशक भारत की किसी कम्पनी का share खरीदे तो किसमे आयेगा →

FDI में →

माना भारत सरकार ने FDI 100% कर दिया Telecommunication में।

Vodafone के पास २ option

↙ अपना पैसा, Technology निवेश करेगा। Tower लगाये etc

↘ भारत में काम करने वाली कम्पनी को takeover कर ले।

२ profit ← (इसमें काम शुरू करने में ज्यादा time नहीं लगेगा।)

(एक प्रतिस्पर्धी को हराकर आ रहा है।)

⇒ Vodafone जब आया तो Hutch का अधिग्रहण कर लिया।

⇒ 1 Company दूसरी का जब अधिग्रहण करती है तो भुगतान कैसा share में होता है

Case → लक्ष्मी मित्तल ने जब business शुरू किया तो loss में जो कम्पनियां थी उन्हें

खरीदा → काल्पनिक पर loss को profit में बदला।

↓

main Competetior – Arselor gp.

↓

लक्ष्मी मित्तल ने Arselor gp को खरीदने का offer दिया।

↓

		individual	Total
⇒ FII + QFI	RFPI	<10%	24%
NRI		05%	10%

⇒ FDI allow नहीं → कृषि, Atomic Energy

Study Tide

⇒ 26% share खरीदते ही सभी asset के 26% के partner हो जाते हैं –

↓

FDI बन जाता है

↓

Financial Investment ——→ Real Investment में convert हो जाता है

⇒ 26% Vodafone + 74% Reliance

Case - 2

अगर Reliance केवल 20% ही बेचे (maximum 26% हो सकता है))

↓

Vodafone 20% , Reliance 80% – FDI

Case 3 Reliance 85% Vodafone 15% – FDI

Case 4 Reliance 89% Vodafone 11% – FDI

Case 5 Vodafone 10% Reliance 9% – FDI – 40% tax

Case 6 Vodafone 9% Reliance 91% – FPI

9% < 10%

↓

15% Tax only

⇒ उपरोक्त सारे नियम listed Companies हेतु है

↓

Public Company

⇒ पहले 0% share खरीदा – FPI – 15% Tax

6 महीने बाद 5% share खरीदा – FDI – 40% Tax } According to Math

⇒ 1 Year में कभी भी 10% touch होगा तो पूरे साल FDI ही माना जायेगा – 40% Tax लगेगा।

Study Tide

⇒ पूरे साल के दौरान एक भी बार share 10% को touch करेगा फिर बेच भी दे तो भी FDI में ही रहेगा।

7) Private & Unlisted Companies में Portfolio Investment का कोई concept नहीं

↓

यहाँ FDI में ही count किया जायेगा। - 40% Tax लगेगा।

Insider Trading → भेदिया / आंतरिक कारोबार

↓

⇒ कम्पनी - के अंदर की कुछ information बहुत sensitive होती है जो leak out नहीं की जा सकती है leak की जायेगी तो गड़बड़ी

⇒ ~~इसके~~ कुछ अति ↓ ऐसा करते हैं तो Insider Trading माना जाता है

↓

2013 में इसके लिये सजा का प्रावधान है Criminal Offense

⇒ रजत गुप्ता case

Hedging → illegal

→ एक तरह investment के Risk कम होता

Arbitrate - पंच

Outer Court Settlement

Court । Arbitrater appoint होता है जो settlement कराता है

जल्द से जल्द solve करता है

Income Tax Return - सरकार को आय का ब्योरा देते हैं

31 July तक limit - Normal

31 August (जुर्माना)

Study Tide

Private Company - share privately जारी
sale purchase नहीं
- Authorized Capital - 10,00,000
↓
10 लोगों के नाम ~~50,00,000~~ 50,000
के share जारी किये
तो 2,50,000 तक हर के लिये
50,000 पर tax भी नहीं लगेगा।

अवमूल्यन →

20/8/2015

UTI Bank - Axis Bank

Mutual Fund

Company को Promote करने हेतु इसको लाया गया।
⇒ 1964 में पहली बार आया - Unit Trust of India - mutual fund
⇒ Mutual fund दिन ब दिन बढ़ रहा है
⇒ शेयर बाजार की जानकारी न होने पर इसके जानकार व्यक्ति के साथ मिलकर share Market में पैसा लगाते है
⇒ छोटे level पर भी Investment होता है

Study Tide

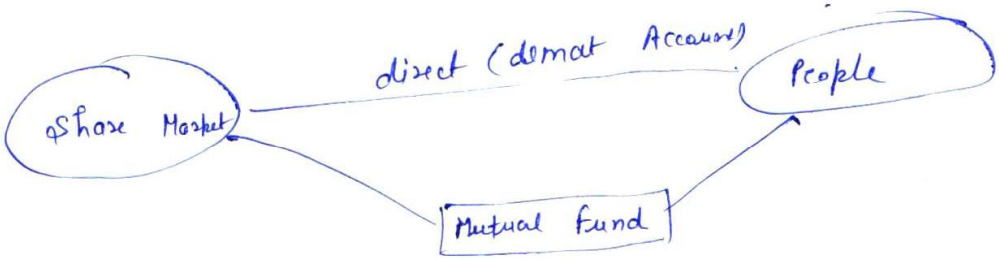

Mutual fund के जरिये निवेश करते है तो Risk घटेगा।।

1000

Risk

कम — Share Market के अच्छे जानकार

No effect — आम व्यक्ति Share Market जाएगा जहाँ rates का उतार-चढ़ाव होता रहता है

⇒ 2001-2002 के बाद Banks के Profit में आने के बाद यह Mutual fund का काम कर रहे हैं

Govt – SBI Mutual Fund

Private
ICICI — Reliance Mutual fund
Axis — Tata

⇒ इनका Return ज्यादा

⇒ LIC के अलावा Insurance Companies भी Mutual fund की तरह काम करती है LIC का Investment अच्छा है

⇒ Mutual fund public को unit बेचता है (Companies के share और Debt ?) की तरह) Unit खरीद कर Mutual fund में निवेश करते हैं

ULIP – Unit Link Insurance Plan

Mutual fund

close Ended
↓
Primary Market
एक निश्चित time तक open
↓
Mutual fund unit जारी करता है और rate बताता है (as like shares)
1,00,000 unit 10₹ ⇒ Fund
यहाँ fund का size fix होगा।

Open Ended
↓
Secondary Market
↓
यहाँ share market की तरह 9:30-3:30 की timing नहीं। कभी भी खरीद बेच सकते हैं लोग इसके fund में पैसे लेकर Share Market में लगाते हैं

Study Tide

⇒ Mutual fund की unit का rate - NAV

(Net Asset Value)

↓

unit का भाव किसी specific day पर

→ Official document में आयेगा कि हमारे खाते में कितना unit जमा है।

→ Asset Management Group - यह हमारे investment को manage (AMG) करने वाला group, Mutual fund में

↓

यह हमारे पैसे को share Market में invest करेगा

share Market में दो निवेश करेंगे (यह फैसला जनता का होगा)

3 ~~चार~~ option AMG लोगों को देगी

F_1 = Growth Fund	F_2 = Debt Fund	F_3 = Balance Fund (Most Popular)
100% equity	100% Debt	[60% equity + 40%]
		↓ इसका parantage.

→ लोगों को चुनना है ~~इसमें~~ किसमें invest करें। माना इसको चुना

↓

अब किस कम्पनी के share में investment है - यह Mutual fund तय करेगा। तय करेगा।

→ अगर fund का NAV गिर रहा है तो हम Fund change कर सकते हैं — Changer कहलाता है

→ साल में 4 बार Free of Cost Fund changing, इसके बाद पैसे लेंगे।

Study Tide

⇒ F_2 fund (Debt fund) loan के रूप में जाना जाता है इसलिये इसे Protector fund कहते हैं

⇒ F_1 की value गिरने पर यही value transfer होगी व loss recover नहीं होगा।

⇒ Mutual fund यही ध्यान रखते हैं कि लोगों को नुकसान न हो otherwise लोग invest नहीं करेंगे।

⇒ Mutual fund में अधिकतम फायदा है 20 साल से

Best Mutual fund Scheme - **SIP** (Systematic Investment Plan)

↓

Return सबसे ज्यादा

ICICI Prudential - 17% return

⇒ हर महीने 1000 ₹ पहले 15 साल के लिए = 60000

5 साल बाद मिलेगा - 1,01,500 ₹ (Return 17% → 101500 − 60000 = 41500 - Return)

⇒ Saving is a function of Income.

Balance Shut

Asset & liability बताई जाती है

10000 × 10 = 1,00,000 Company

1000 × 10 = (10,000) हमने

Building - 1,00,000

↓

10 करोड़ - 1 के मालिक हम

↓

कुछ दिन बाद Market Price - 1,50,000

Study Tide

⇒ Mutual Fund की अलग अलग schemes का Nav अलग-अलग जगह पर हो सकता है

⇒ Mutual Fund वाले इससे पैसे charge करते हैं

Entry load → enter करने का charge
Exist load → बाहर आने का charge

} दोनों को सरकार ने बंद कर दिया अब

Insurance

General

~~गाड़ियां~~, ~~Stock~~, ~~Marine~~ पर सिर्फ Insurance है Investment नहीं

गाड़ियों का – insurance compulsory (autovehicle Act के तहत)

Life

Insurance भी investement भी

death होने पर पैसे मिलेंगे।

Policy Mature होने पर पैसा मिलेगा।

life के दोनों sides cover ~~dead~~ dead & alive also

⇒ LIC - first insurance

⇒ 1995 - LIC में 26% FDI
Now 49% FDI allow

⇒ पहला Premium pay करने के बाद कभी भी death पर पैसा मिलेगा।

⇒ Insurance Company → Invest करती है

↓ कहाँ

Topic

Study Tide

Topic

Budget

⇒ Private Budget

main - Income

Public Budget

main = Growth Rate (8%)
Target

gov. reverse order में बजट बनाती है।

8% growth Rate के लिये खर्चा तय होगा - Budget Expendeture

Target - ₹ 500

↓

कैसे बजट पर होने वाले खर्चे को प्राप्त किया जाये।

↓

Income

Non - Tax

↓

Public Sector
loan &
विनिवेश।
Licnse fee
Penalty
Passport fee
Court fee

Tax

ex.

Income

Tax — 350

Non Tax — 50

400

Target 500

New Target 600 ₹

↑

महंगाई बढ़ने पर सरकार की प्रभावित

- 100 घाटा

₹ - 200 घाटा

↓

उसे पूरा करने को खर्चे में कटौती नहीं कर सकती gov. क्योंकि इसके growth Rate पर मर्क पड़ेगा।

↓ 2nd option

gov. income बढ़ाये

↓

या तो नये Tax लगाये

या Tax बढ़ाये

12.6% — 14%

सेवा कर (1 June से)

Study Tide

⇒ भारत का Tax Rate, global average से ज्यादा।

⇒ Tax Rate बढ़ेगा → महँगाई बढ़ेगी → आम आदमी प्रभावित → क्रय शक्ति में कमी → demand में कमी → Worse thing in Economics

⇒ Tax Reform जरूरी - GST, DDT

⇒ अब घाटे को सरकार कैसे पूरा करेगी?

(100 ₹)

1 option
Borrowing
↓
loan ले
↓
3 option

2 option
④ ~~विनिवेश~~ (Disinvestment)
↓
अल्प निवेश
Asset बेच कर पैसा एकत्रण करना

Study Tide

① • Borrowing from RBI – मौद्रिक नीति का हिस्सा

② • . from Public (Market Borrowing) – राजकोषीय नीति का हिस्सा

③ • लोक निधि के पैसे को उपयोग करना ⇒
Using Public Account

⇒ वर्तमान में भारत सरकार चारों option use कर रही है

1. Borrowing from RBI

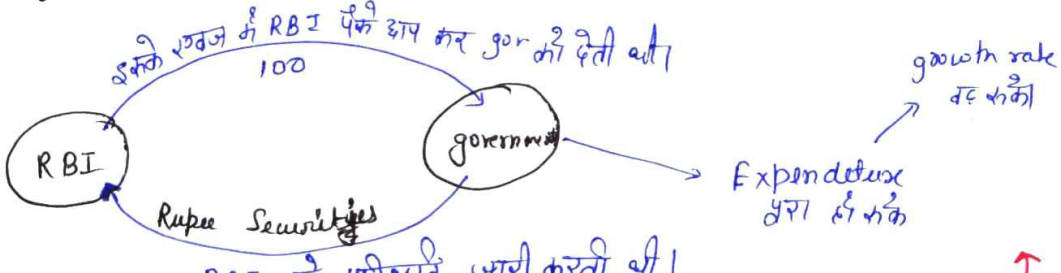

RBI को प्रतिभूति जारी करती थी।

Treasury Bill – भारत सरकार के यही जारी करती थी

Adhoc
संविदा
↓
भारत सरकार
यह जारी करती थी
RBI को

Regular Treasury Bill

(इस system का नाम
पहले की वित्त व्यवस्था था)
deficit financing
↓
यह भी growth oriented है
main उद्देश्य growth को maintain
करना

⇒ पर यह system 1997 में खत्म हो गया। (Treasury Bill वाला)

⇒ सबसे बढ़िया system gold system को माना गया है

⇒ Comfortable Country → Dollar Stock (e.g. China)
→ Gold Stock – (producing country)

Study Tide

⇒ Gold System — working

↓

जितना Note छापे उसके बराबर gold RBI में रखा जायो

↓

100 ₹ छपा → Market में आया

↓

demand supply बढ़ेगी। supply प्रभावित होगी

↓

(worst case) demand बढ़ी पर supply नहीं

↓ demand supply में 100 ₹ का gap

अर्थव्यवस्था अस्थिर

↓ gold system का फायदा

100 ₹ का gold हमारे पास था तो 100 ₹ का gold International Market में दे देकर हम 100 ₹ उधार ले सकते हैं

↓

Demand — Supply बराबर हो जायेगी

⇒ Use only for gold Producing Country.

भारत का system — न्यूनतम 10 सुरक्षित (आरक्षित) प्रणाली

↓

200 करोड़ (आरक्षित)

115 करोड़ gold — 85 ₹ करोड़

⇒ Minimal Reserve — हमारा Reserve कम से कम 200 करोड़ का होगा। यह एक formality है (यह एक शुरुआत है पर इसके ऊपर जो नोट छपेगा उसका आधार सरकारी प्रतिभूति है RBI की duty है कि Note छापकर सरकार को दे

Study Tide

⇒ सरकारी प्रतिभूति का देश के बाहर value नहीं है
⇒ Borrowing का अकीकृत अधिकार gov. को।
⇒ पुराने नोट के आधार पर नया नोट छापकर RBI देती है (यह भी आधार होता है

21/Aug/18

RBI से borrow करने की व्यवस्था आगे चल कर मुसीबत का कारण बनी।
⇒ 1956-61 - के Pivot plan में बहुत पैसे की आवश्यकता थी
1960 में पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी RBI ने बहुत नोट छापे और बाजार में पैसा दिया। (प्रतिभूतियों के रूप में)

⇒ इसका नुकसान deficit financing का तीसरी योजना पर पड़ा। देश में Money supply बढ़ी। पर Money अकेला demand तो दे सकता है पर supply नहीं demand — supply के बीच gap पैदा हुआ और महँगाई भारत का जन्म हुआ जो आज तक मौजूद है।

⇒ 1945- 10gm सोना 18 ₹ था।
1955- 55 ₹
1962- 95 ₹ था

⇒ 90-91 में भारत की खराब स्थिति gov. की policy की वजह से थी।
⇒ 1991 में नई आर्थिक नीति आयी - आर्थिक सुधार
पुरानी policy छोड़कर नई नीतियाँ बनाई गयी।

⇒ सरकार इस deficit borrowing को बंद नहीं कर सकती थी तब एक alternative option ढूँढा गया - विनिवेश का
विनिवेश मंत्रालय बनाया गया — विनिवेश मंत्री- अरुण शौरी
↓ ↓
economist
World Bank, IMF

Study Tide

⇒ Indian Express का editor बनाया गया 1987 में।

⇒ 1987 में उन्होंने Reliance gp के खिलाफ लिखा, जिसके कारण Reliance का share आव गिरकर 330 ₹ से 70 ₹ आ गया।

⇒ 1997 में ऐतिहासिक समझौता हुआ - RBI एवं वित्त मंत्रालय के मध्य

वित्त मंत्री - यशवन्त सिन्हा

(deficit financing) Adhoc Treasury Bill को बंद कर दिया गया।

⇒ पर Regular Treasury Bill अब भी लागू है

एक नया concept आया - Ways and Means Advances (1997)

इसमें RBI हर एक quarter पर एक limit तय करती है कि सरकार चाहे तो अपने day to day expense पूरा करने हेतु ले सकते हैं लेकिन बजट में होने वाले खर्चे को पूरा करने हेतु नहीं।

माना किसी quarter (3 महीने) में - 6000 करोड़ decide किया fix

July 2014 में

⇒ deficit financing 1997 में खत्म हुआ।

&

ways & Means Advance

दोनों में अंतर

deficit financing	Ways & Means Advance
Unlimited	limited
Interest कम	Interest ज्यादा
बजट के खर्चे पूरा करने को use कर सकती है	यह बजट के खर्चे हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता।

Study Tide

⇒ 1997 में C. Rangrajan ने deficit financing & ways and means Advance में अंतर बताया था — Throw Net

official site / Authentic site

⇒ Borrowing from Public (Market Borrowing)

इसमें सरकार अपनी प्रतिभूति Public को जारी करेगी। (किसान विकास पत्र, Bonds, etc)

2014 की नई सरकार ने भी इसे जारी रखने का फैसला किया।

किसान विकास पत्र को redesign करके Bank के जरिये बेचने की योजना है, पहले केवल Post offices द्वारा मिलते थे

⇒ इस loan से Market में money supply में कोई फर्क नहीं पड़ा।

Qu. Market side का Negative Side -

Inflation

मुद्रा स्फीति

मांग जनित
Demand Pull

Cost जनित
Cost push

(1) Demand Pull - किसी अर्थव्यवस्था में demand = supply (Balanced Economics)

यदि demand बढ़ी, pulled up हुयी / gap बढ़ेगा supply demand के बीच में / महंगाई बढ़ेगी।

Demand
|
Supply

⇒ बाजार में मुद्रा बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है

⇒ demand कुछ कारणों के द्वारा ऊपर खींच ली जाती है - जैसे कि deficit borrowing
जरूरत से ज्यादा money supply

Study Tide

=> 75-85 Billion का घाटा - deficit borrowing से

(2) Cost Push - उत्पादन लागत बढ़ने पर बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ेंगे जिससे मंहगाई होगी। इसे Cost Push कहते हैं जबकि demand = supply है तब भी

उत्पादन लागत बढ़ने के कारण

(i) Raw Material का मंहगा होना -

(a) घरेलू अन्तराष्ट्रीय कारण - (लड़ाई या अन्य कारणों से)
कच्चे तेल का दाम बढ़ना।
भारत 80% आयात करता है
पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ना। जिससे परिवहन लागत बढ़ेगी।

(b) घरेलू कारण - काला बाजारी, प्राकृतिक आपदायें, सरकारी नीतियाँ
कृषि का खराब होना - for agro industry

(2) Profit - Market में goodwill बढ़ते ही लोग profit Margin बढ़ाते हैं जिससे बिना लागत बढ़े भी कम्पनियाँ दाम बढ़ाती हैं इससे बाजार में मंहगाई बढ़ती है ex. Celebration Chocklate - 150 ₹
उसके अन्दर के चीजों की कीमत - 100 ₹
मतलब अन्दर के चीजों की value में भी profit तथा ऊपर से भी profit 50 ₹।

=> 1969 में MRPP India (Jira - 1973)
↓
Monopoly & Restrictive ~~trade~~ of Practise Policy
↓
2003 में खत्म

Study Tide

⇒ Advertisement में Companies का खर्चा बढ़ा है।

(3) Government - Tax Policy & governance problem

(4) ब्याज दर → Interest Rate - Bank से loan के बदले ब्याज मिलता है
Bank interest Rate बढ़ा रहा है
Mutual fund में भी घरेलू पूंजी मांग बढ़ रही है

⇒ Shares में भी public पूंजी की मांग बढ़ रही है

⇒ घरेलू पूंजी पर मांग का दबाव बढ़ रहा है इसके हमारे पास choices बढ़ रही है पर दबाव भी बढ़ रहा है पूंजी की लागत ब्याज है पूंजी की उपलब्धता कम demand बढ़ता जा रहा है तो इसका दाम बढ़ जायेगा। पूंजी महंगी होगी ब्याज दर बढ़ेगा।

⇒ Already भारत के बाजार में पूंजी की उपलब्धता कम साथ ही महंगी और मांग दिन ब दिन बढ़ रही है जब भारत सरकार भी बाजार से उधार लेगा तो करोड़ो में संकट करेगा जिससे पूंजी पर दबाव और बढ़ेगा और बाजार में पूंजी महंगी होगी। ब्याज दर भी बढ़ेगी

↓
उत्पादन लागत बढ़ेगी
↓
Cash push Inflation होगा।

भारत में पूंजी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षा कम तथा महंगी।

⇒ अब सरकार अगर Market Borrowing करेगी तो यह भारतीय कम्पनियो के लिए खतरनाक है कदम क्यो ?

⇒ 1991 में जब FDI & FPI आया।
92

✓ ⇒ 1991 में

Study Tide

1991 में विदेशी कम्पनियाँ भारत आयी। उत्पादन लागत कम, तकनीक नयी इसकी वजह से भारतीय उद्योग धन्धे बेकार पर थी प्रतिस्पर्द्धा जैसे करने की क्षमता कम थी।

भारत के उद्योग धन्धे ज्यादा पूंजी उपयोग कर रहे थे। जबकि विदेशी कम्पनियाँ अन्तराष्ट्रीय मुद्रा उपयोग कर रही थी जो कि पर्याप्त मात्रा में थी और सस्ती थी। तो उनकी उत्पादन लागत कम थी हमारी ज्यादा। अब अगर सरकार Market Borrowing करती तो ज्यादा उद्योग और पीछे चले जाते।

↓

तब 1992 में FPI लाया गया। भारत की कम्पनियों को सस्ती पूंजी उपलब्धता का मार्ग सुझाया कि आप प्रतिभूति बेचकर अन्तराष्ट्रीय बाजार में आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं

⇒ लोक निधि के पैसे को उपयोग -

Using Public fund

Public Account लोक निधि - भारत में लोगो की small savings।

⇒ सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है - Non Working life है Social Security Scheme के तहत कई योजनाएँ चलाई गयी। जिसमे Famous पेंशन। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके spouse को Half पेंशन मिलती थी।

↓ 2006 में पेंशन योजना खत्म कर दी गई नया पेंशन स्कीम NPS है पर विरुद्ध

Provident fund, Gratuity

किसी संस्था के (Private + gov)

⇒ Provident fund - PF यह ESS के तहत आता है, employer 20 से अधिक हो जाये तो यह PF Act में आ जायेगी। (1952)

Study Tide

⇒ माना हमारी Monthly Salary - 3000

PF Act के दायरे में आने के कारण PF का पैसा कटेगा - Normal 10%.
Risky work 12%.

1 Month बाद - 3000
- 300 (10%)
2700 ₹ दिये जायेंगे।

⇒ employee के 300 के साथ कम्पनी भी 300 ₹ जोड़ कर employee के PF account में जायेगा - Total 600

⇒ 30 साल बाद 600 ₹ ब्याज के साथ लगभग - काफी पैसा मिलेगा
↳ duration, Salary, Interest Rate } तीनो का असर पड़ेगा

80 लाख कर्मचारी - केंद्र
+
राज्य सरकार कर्मचारी
+
निजी क्षेत्र
} Total 5 करोड़ लोग
average 1 आदमी पर 1 हजार
5 करोड़ पर 5 हजार करोड़

⇒ PF का पैसा सिर्फ SBI में जमा होता है लेकिन यह SBI use नहीं कर सकता यह भारत सरकार के वित्त निधि में जमा होता है और भारत सरकार इस पैसे को use करके ब्याज देना होगा। यह भी loan के Nature का है अतः मंत्रालय ब्याज पर तय करता है। पिछले वर्षों में - 8.30 - 9.30 के बीच था
वर्तमान - 8.75%

TDS - ब्याज पर
① fix deposit पर 8% annual मिलता है
पर 10000 से अधिक होते ही Tax कटता है जिसे TDS कहते हैं
इससे पैसा 8% से कम मिलता है

Study Tide

22/01/25

Types PF

(1) Statutory - provident fund - वैधानिक
(2) Recognised " " - प्रमाणित RPF
(3) UnRecognised - अप्रमाणित UPF
(4) Public Provident Fund - PPF

1 Statutory → सरकारी कर्मचारियों हेतु (SPF)
100% tax discount

2 Recognised (RPF)
3 UPF > private field में आता

RPF → अगर employer ने income tax commissoner या PF commissoner से approval Recognised कराया हो उसमे employee को नायदा - जब Retirement पर पैसा मिलेगा तो Tax नही करेगा

UPF → उसमे last में पैसा मिलने पर Tax करता है

ex. ₹500,000 लाख - income

employee	employer
100000	100000
Tax Interest 500000	500000
	↓
	240000

एक पर Tax लग जायेगा

=) पर employer नही कराने जाते क्योकि Income Tax कमिश्नर और PF कमिश्नर घूस लेते है काफी सकलिये)

Study Tide

PPF → Most Popular

18+ का कोई भी person इसका member हो सकता है

इसमें 1 साल में minimum - 500
maximum - 1,50,000 } for 15 year

इस पर ब्याज मिलेगा / Maturity पर पैसा मिलेगा Tax free

⇒ एक साल में अलग अलग income वाले लोगों में काफी popular

⇒ SPF या अन्य PF के साथ भी इसका member बन सकते है

⇒ Investment diversify होना चाहिये।

विनिवेश

Disinvestment - limited to the asset

⇒ Investment पर asset generate होता है

⇒ ↓
बेचकर investment वापस मिलता है

government asset → PSU → Public Sector Undertaking

public Sector भारत सरकार का asset है।

asset वह होता है जो owner के लिये आय का सृजन करे

⇒ 1945 - 5 public Sector थे केवल

⇒ Steel Authority of India

⇒ PSU का profit - regular होता है

PSU

Profit में
↓
सरकार हेतु आय स्रोत

Loss में
↓
सरकार को pay करना पड़ रहा है
gov की asset नहीं
liability हो गये है

Study Tide

⇒ Air India - government (four other से 1.5-2 गुना ज्यादा)
all air lines are in loss केवल 1 profit में Indigo

⇒ 2013 - 1300 करोड़ देने के बावजूद यह पैसे से recover नहीं हुआ।

⇒ Loss PSU - Liability Nature के नहीं पर Asset से Liability में convert हो जाये हैं और इनको वापस Asset में change किया जा सकता है

विनिवेश →

⇒ gov ने decide किया PSU के share को बेचा जायेगा पर भारत सरकार की PSU खरीदेगा कौन? PSU बड़े होते हैं इनके थोड़े से share खरीदने को काफी पैसा देना पड़ता है-

ex. ~~loss~~ 2014 - Coal India - 10% share
" 22600 करोड़ ₹ में बिका

⇒ Private Sector इसे तब तक नहीं खरीदते जब तक 51% share न बेचा जाये और तब यह विनिवेश न रहकर निजीकरण में आ जायेगा।

⇒ भारत सरकार ने फिर PSU के share दोनों निवेशकों और public को जारी किये जाये इसे IPO PSU कहते हैं
भारत सरकार ने 5-10% share का विनिवेश प्रारम्भ किया।
2012 - 7-8 PSU का विनिवेश हुआ

(विनिवेश उन्हीं का होगा जो बड़े-बड़े हैं और लाभ में हैं
SAIL (Steel Authority of India)
Hindustan Fertilizer
NALCO (National Aluminium Limited Co)
TALCO

2014 - नई सरकार - विनिवेश और Borrowing दोनों को पकड़ कर रही है
- 1 किसान विमान पत्तन की शुरुआत
- last year Coal India का विनिवेश

Study Tide

⇒ विनिवेश उम्मीद से कम था 2014 तक पर Coal India ने 90-
20000 करोड़ का aim पूरा कर दिया

2015 - 2016 - 3 विनिवेश हुये - फिर 3000 करोड़ की प्र.

PFC - Apr, May, June (8-10%)

REC -

Dredging Corporation

आज कल की
⇒ IOC का 10% share बेचने जा रही है। उम्मीद - 9500 करोड़ उम्मीद
aim - ~~2000~~ 69500 करोड़ gain करने का (2015-2016)

⇒ वर्तमान policy mix - Borrowing + विनिवेश

⇒ आज की date में भारत सरकार को किन स्रोतो से finance किया जा रहा है

* Borrowing from RBI

(2) " " Market — Public से पैसा - ऋण प्रकृति Debt
" " लोकनिधि

(4) विनिवेश — Public से पैसा - equity Nature

⇒ Budget →

1951 - 2015 -
1951 - 91 - Outer Borrowing
91 - 2015 - Inter Nal Borrowing
} आज की date में प्रत्येक भारतीय पर 33000 ₹ loan

Interest - 1 ₹ — 20 पैसे ब्याज पर
20%

2014 - 18 पैसे ब्याज
18%

defense पर Total खर्च - 11 पैसा
Total subsidy - 10 पैसे
Total Plans - 22 पैसे

Study Tide

91 में 1 Billion Dollar था

↓

OR 355 Billion Dollar (एक साल के आयात बराबर)

xternal Loan — Dollar में भुगतान
490 Billion Dollar

हमारा निर्यात हमेशा आयात से कम रहा पर dollar भण्डार का उसके reason 91 के बाद FPI, FDI, NRI इससे प्राप्त dollar से रहा

=> अगर लोगो का विश्वास सरकार में खत्म हो जाये / भारत के आम लोग प्रतिभूति खरीदने से मना कर दे other available option की वजह से

↓

crisis of Confidence आयेगा

↓

goodwill खत्म होगी

↓

भारत में Europe का crisis (2008 वाला) आ जायेगा।

सरकार का smart कदम :

भारत में २ निवेशक

संस्थागत
↓
इनको force कर सकती है

व्यक्तिगत निवेशक
इनको share खरीदने को force नहीं कर सकती

Study Tide

Insurance

Other

Mutual Fund की तरह Share Market में लगाते है

भारत सरकार का समर्थन

इनके bussiness growth में सकारात्मक है क्योंकि एक निश्चित वर्ग इनके पास नहीं आता

LIC

भारत सरकार की प्रतिभूतियो का सबसे बड़ा खरीदार

भारत सरकार का संकट मोचन

LIC द्वारा बैंक सरकारी प्रतिभूति में invest करेगी

LIC संस्थागत है

बदले में भारत सरकार का LIC को समर्थन

यह समर्थन भारत के के वर्ग को LIC की तरफ खींचता है

1995 तक LIC का एकमात्र निर्णायक था

अब LIC का Market share 25% दे दिया है।

अगर gov समर्थन वापस ले तो उनकी प्रतिभूति कोई न लेगा।

कुछ साल पहले भारत सरकार ने LIC को छूट दी कि आप Market के Premium को use करके share बाजार में लगाये - New Policy

नतीजा - जब हम policy लेते है। माना 10,00,000 का insurance 20 साल के लिये करवाया

dead होने पर क्या Qu

Maturity पर क्या?

Study Tide

इन qu के answer केवल LIC agent दे सकता है क्योंकि gov LIC को guarantee देती है minimum return की पर इसकी ~~कोई~~ Insurance agent नहीं बता सकते क्योंकि वो depend करेगा share Market की performance पर।

Other में

No minimum guaranteed return

↓

एक idea मान के चलते है

↓

~~मानते~~ वह ग्राहक पटाने हेतु profit percent ज्यादा बताता है

↓

Misguide करता है ~~कि~~

↓

और May be Policy हमारे लिये बेकार हो पर Payment हम कर चुके

↓

तो अब हम क्या करें ~~कि~~

↓

इन सब problim को हल करने के लिये IRDA ने Pre Look ~~Pa~~period rule लाया

Pre Look Period

↓

Policy recieving से 15 दिन का time

↓

Suitable न लगे तो change कर सकते है या return कर सकते है

↓

15 दिन बीत जाने पर कुछ change नहीं होगा।

⇒ कोई भी Insurance Company अपने broshure के example में 10% से ज्यादा Calculation देके नहीं कर सकते

⇒ ~~Rs~~ 10,00,00 for 20 y एक पर premium कितना देना है यह LIC Agent बता सकता है पर Other Companies का नहीं बता सकता। – fix amount नहीं बतायेगा Minimum Ammount बतायेगा।

⇒ जितना अधिक investment उतना अधिक return

Study Tide

2015 - रेल बजट (26 Feb 2015) - Unique

→ Infrastructure - मजबूत

↓

8 लाख करोड़ खर्च अनुमानित - 1.5 लाख करोड़ LIC निवेश करेगा इसका आदेश दिया गया।

→ कैसे - रेलवे बॉन्ड जारी करेगा। LIC खरीद लेगा।

→ Bank भी सरकारी प्रतिभूति खरीदता है - RBI Manage करता है

→ RBI ऐसी चीजें निश्चित करता है कि Bank को सरकारी प्रतिभूति खरीदनी पड़ती है

Net → विदेशी FPI का सरकारी प्रतिभूति में निवेश की सीमा?

⇒

Liberalization (L)	Privatization (P)
आर्थिक गतिविधियों (उत्पादन, आय, व्यय) ⇒ दो agent करते हैं - public sector, private sector	
हमारे economic agents को स्वतंत्रता दी जाये ताकि ये अपनी इच्छा से बेहतर decision ले सकें।	
⇒ भारतीय बाजार में freedom दी गयी पर complete freedom नहीं	

⇒ विनिवेश में भी हिस्सेदारी को free किया जा सकता है

IRDA Act 2003 - for Insurance Company

↓

भारत की एक insurance company विनिवेश में भाग ले सकती है और Max 10% अधिक खरीद सकता है। - ex. LIC

Study Tide

→ 2012 में विनिवेश हुआ Target 30000 करोड़ का था।
लेकिन पैसा कम आया। वित्त मंत्रालय ने Notification जारी किया और LIC
की limit 30% कर दिया। Notification जारी होते ही IRDA ने विरोध
किया।

LIC - 1956 में आया तब Insurance Act 1936 था इसी के अन्दर LIC
का registration हुआ इसलिये IRDA का विरोध गलत। कुछ
भी ऊपर कानूनी नहीं

IRDA Act - all other Insurance पर लागू।

→ भारत सरकार के Bond कोई भी खरीद सकता है
(FPI, FDI etc)
पर Portfolio निवेशक के लिये limit है केवल

राजकोषीय नीति - 8 qu
mains also

Study Tide

⇒ demand Supply से ज्यादा - महंगाई

एक limit के बाद growth rate कम होगा।

क्रय शक्ति कम, बेरोजगारी बढ़ेगी

निर्यात कम

Economy में 3 Situation

Aggregate Demand (AD) / Aggregate Supply (AS)

(1) AD = AS ⇒ अर्थव्यवस्था Banlance / Equilibrium कीमतें स्थिर

(2) AD > AS → महंगाई बढ़ेगी, मुद्रा स्फीति (Inflation)

(3) AD < AS → कीमतें घटेगी, अवस्फीति (Deflation)

⇒ भारत में (3) अच्छा / कीमतें घटेगी → क्रय शक्ति बढ़ेगी पर व्यापार लाभदा क्षणिक पर धीरे-धीरे करने मंदी का दौर आयेगा।

⇒ 3rd सबसे बेकार

Inflation is bad but Deflation is ~~best~~ worst

⇒ Gov. policy — mainly 2 aim

अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखना

संतुलन बनाये रखते हुये अर्थव्यवस्था को इसके उद्देश्य की तरफ लाना

↓

पूर्ण रोजगार की स्थिति

Dream point ← (Full Employment)

Study Tide

⇒ Human Resources
Non Human Resources > सभी पूरी तरह रोजगार में लगे हैं

↓

Full Employment

↓

उत्पादन अपने maximum पर होगा।

↓

राष्ट्रीय आय ,,

↓

all thing maximum.

⇒ यहाँ से भी उत्पादन बढ़ेगा Technology की help से

23/8/2015

Full Employment → माना एक पर 200 unit होगी

20 unit →

AD = AS = 180th पर रुक गया है

20 unit company बनाये तो demand हो
या demand हो तब supply करे

Driver कौन अर्थव्यवस्था का? – Supplier या Consumer

~~1903~~

1930 तक का economic - classical economics
मानते थे अर्थव्यवस्था का driver supplier होता है

Jay. D. Say → "पूर्ति मांग का सृजन स्वयं करती है"
Supply creates its own demand

⇒ Supplier उत्पादन करे चाहे मांग हो या न हो
क्योंकि उत्पादन होगा तो ~~मांग~~ ~~से~~ आय होगी और मांग स्वयं होगी।

Study Tide

Production = 8 → supply
↓
Income = 8
↓
Exp^n = 8
→ demand

* इस chain में तब रुकेगी जब full employment पर पहुँचेगे।

Supply side Economy
अर्थव्यवस्था का driver = supplier

⇒ यूरोप की महामंदी (ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित) — यहाँ पर माँग घटना शुरू हुआ सारे classical economic rule fail हो गये।

Keynes → from Britain → Book "General Theory of Employment"

इन्होंने अर्थव्यवस्था के driver demand को बताया।

New Theory दी → पुरानी सारी Theory के against में Theory दी।
यहाँ से नई विचार धारा शुरू हुयी Keynes Economics
आज भी यही व्यवहारिक।

⇒ Pre - 1979 में लागू हुआ — UPSC में

* Classical Theory — supplier > driver
* Keynesian Theory — demand

⇒ Keynesian Economic विकसित देशों की स्थिति को ध्यान में रखकर लिखी गयी। मंदी के समय।
इन्होंने गिरती हुयी माँग को बढ़ने के कई उपाय बताये

⇒ जबकि विकासशील देशों की समस्या - demand कैसे लगाये।
भारत के

⇒ Keynesian Theory केवल विकसित देशों हेतु suitable पर केवल मंदी के दौरान

Study Tide

⇒ हमारे देश में अर्थव्यवस्था का driver – supplier (investor)

⇒ गाजियाबाद, Noida → U.P.
फरीदाबाद, धारुहेड़ा, गुड़गाँव → हरियाणा
→ FDI जब आया तो यहाँ का Infrastructure मजबूत था (1991 में)

⇒ गुड़गाँव में production शुरू किया → Job opportunity आयी – New Youth को Job मिली

↓
Supply level economy

⇒ 3 level development में
- Government → Platform बनाये → Infrastructure मजबूत करे, Law & Order में
- I^st Investment
- Producer (foreign Companies) → Production शुरू करेंगे → Human Resource – आय बढ़ेगी तब demand बढ़ेगी
- Person

⇒ जो development गुड़गाँव में हुआ वह अन्य जगह नहीं हुआ – क्यों ?
UP gov. का failure

⇒ Gujarat developed – infrastructure मजबूत

⇒ आर्थिक उन्नति होगी तो social उन्नति भी होगी।

⇒ UP – most potential state
शहर ज्यादा → हर शहर एक विशेष economy के साथ
↓
हर शहर की विशेषता (चूड़ी, कालीन, ताँता)
↓

कन्नौज
आगरा – चमड़ा
फिरोजाबाद – glass work
मुरादाबाद – पीतल
कानपुर – चमड़ा

मलिहाबाद – आम
लखनऊ – चिकनकारी
बनारस – बनारसी साड़ी
अलीगढ़ – अलीगढ़

भदोही – कालीन

Study Tide

⇒ यह भारत के अपने है इन सब चीजो को बढ़ाता है तो हमारी आर्थिक समस्या कम होगी। क्योंकि हम तकनीक में प्रतिस्पर्धा नही कर सकते लेकिन इन देशी चीजो में दुनिया में सबसे आगे निकल सकते है

⇒ जनसंख्या में भारत सबसे आगे।

⇒ साथ ही UP में पर्यटन भी अच्छा

⇒ पर gov. infrastructure अभी तक मजबूत नही कर पायी इसीलिये FDI अभी तक नही आया।

⇒ driver मिल गया supplier-

क्या उनको incentive देना चाहिये? – Best Incentive क्या हो सकता है?

encouragement

Best Incentive → Infrastructure

Tax में कमी – (30% – 25% 2014)

Law and Order maintain

Subsidy

Incentives

↓

Inflation

AD > AS

(3-4%) – ideal

मंहगाई पर

↓

क्यों

↓

① AD = AS – कीमत स्थिर

② AD > AS – कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक attract होंगे

A – दाम ↑ – सभी इसकी तरफ attract

B – दाम स्थिर profit Margin बढ़ेगा। कीमत बढ़ने पर

C – दाम ↓

Study Tide

⇒ Consume demand ——price——> Producer Supply

चाहते है दाम गिरे — कीमत बढ़ाना

lower the price higher the supply — higher the price higher the supply

⇒ 3-4% inflation से उपभोक्ता बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा।

⇒ उपभोक्ता को अधिक प्रभावित किये driver को encourage करना best Incentive

⇒ Inflation बढ़ेगा तभी growth बढ़ेगा (production बढ़ने से)

(Growth के लिये मंहगाई जरूरी)

क्योंकि growth के लिये driver की main भूमिका

⇒ last 2014 - growth के लिये जरूरी — Inflation कीमतों का बढ़ना

⇒ 3-4% → से ऊपर मंहगाई दर बढ़ते ही consumer की क्रय क्षमता कम हो जायेगी और demand रुक जायेगी।

⇒ Growth ~~&~~ Inflation (3-4% तक) (सीधा relation)

Growth ~~∞~~ Inflation (3-4% से ज्यादा होते ही) (उल्टा relation)

⇒ High rate of Inflation growth को चौपट कर देगा।

⇒ भारत - अर्थतन - 8-10% (मंहगाई growth को खा गया)

last years — उल्टा relation

⇒ 2014
10000
10000 - 10 चीजे
पिछले साल 10 उत्पादको ने चीजे बेची

2015
10000
10000 - 10 से कम चीजे
8 चीजे खरीद पाये
इस साल केवल 8 उत्पादक चीजे बेच पाया।

Study Tide

Indian Economy

भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यवहार, हमारा अपना व्यवहार है।

Producer — इन तीनो क्षेत्र पर खर्च करते है।

Primary — खाद्य

Secondary — सामान

Tertiary — सेवा

⇒ महंगाई तभी उत्पादन बंद हुआ तब पहले कौन प्रभावित होगा।

Preference order - ① primary - कृषि (महंगाई के कारण इसकी चीजे कभी बंद नही होगी क्योंकि खाने की जरूरत उतनी ही रहेगी)

↓ हमारे उत्पादक Safe — मांग मे कमी नही आयेगी चाहे जितनी महंगाई हो)

- विकसित ⇒ Australia, Newzealand का Back bone agriculture इसलिये यह मंदी के शिकार आसानी से नही होता

⇒ भारत की Back Bone मजबूत - Agriculture

② कई बार secondary & Service sector मे तरीयता तय नही हो पाती क्योंकि कभी कभी यह एक दूसरे के पूरक होते है

② 2 चीजे Industry के खिलाफ, Service के favour मे

① Industrial good एक बार खरीदेंगे, पर Service बार बार
Mob एक बार — service data pack बार-बार

② Industrial good की demand को टाल सकते है पर सेवाओ को नही

ex. Mob टूटना तो New लेना है तो एक wait भी कर लेते है टाल सकते है लेकिन सेवाओ के उपभोग को नही टाल सकते। Recharge balance 0 हो जाये तब इसको नही टाल सकते।

Study Tide

⇒ महंगाई में चलने की नॉलत आयेगी तो Industrial goods की चली जायेगी

2nd preference - Service

3rd preference - Industrial goods

⇒ पिछले साल 2 उत्पादको का नुकसान हुआ वह Industrial field के ही होंगे।

⇒ महंगाई बहुत ज्यादा होगी तो Industry उर के साथे में होगी। और उत्पादन में कमी आयेगी। - Worst affected Sector - Industry (खास- Manufacturing)

⇒ Agriculture का growth rate fluctuate करता है क्योंकि कृषि के लिये हम मानसून पर depend करते है

⇒ जब तक हमारा वरीयता क्रम नहीं बदलेगा तब तक यही चलता रहेगा। अर्थव्यवस्था का behave same रहेगा।

मौद्रिक नीति - RBI - Inflation Theory
राजकोषीय नीति - भारत सरकार - Growth Theory } दोनो में टकराव

RBI → जब तक Inflation control नहीं होगा तब तक growth rate नहीं बढ़ता है बढ़ेगा।

भारत सरकार → Inflation का main reason demand supply के बीच gap Inflation तभी कम होगा जब demand supply

Study Tide

⇒ Agriculture वस्तुओं की मांग inelastic निश्चित होती है। इनकी मांग कीमत या आय बढ़ने से ज्यादा कम नहीं होती।

⇒ हमारा सबसे ज्यादा खर्चा सेवाओं पर (भारत के आम लोगों का)

⇒

GDP – कुल उत्पादन – 100 ₹

P (कृषि)	S (उद्योग)	T (सेवा)
14%	27%	59%
14 ₹	27 ₹	59 ₹

41 ₹

वस्तुओं का उत्पादन

सेवाओं का उत्पादन ज्यादा (क्योंकि फर्क पर खर्च ज्यादा)

⇒ 1994-95 – Service Sector बहुत बुरा था फिर Service sector के विस्फोट हुआ भारत सरकार ने मौके का फायदा हुआ Service Tax लगाया।

1994-95 Service Tax = 40 हजार करोड़ (पूरे साल में पूरे भारत का collection)

2014-15 > 2,00,000 करोड़

⇒ Supplier चीज बनाते है → features बढ़ाते है – विज्ञापन करते है → हमें मनोवैज्ञानिकी तौर पर encourage करते है चीजें खरीदने को

ex. old leg 2 ₹ में 1 ₹ बचाते थे पर वर्तमान में 1,00,000 कमाते पर भी loan लेना पसंद है तो Middle Class करते है क्या यह सही?

Old generation
| — No Major Change
Middle generation
| — 1991 की नीति (बड़ा बदलाव)
New generation

Study Tide

⇒ demand = supply करना बहुत मुश्किल।
और साथ में रखते आगे ले जाना बहुत मुश्किल (चरखे का example)
↓ लाठी की सहायता से काम
gov के पास 2 instrument
राजकोषीय & मौद्रिक

24/8/15

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

Government द्वारा

⇒ कमजोर राजकोषीय नीति के कारण मौद्रिक नीति अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती।

⇒ Main Source of Income → Public (gov के लिए)
लोक आय कहलाती है
(Public Revenue)
↓ खर्चा (पब्लिक पर)
लोक व्यय
(Public expenditure)

⇒ यह दोनों कितने powerful है केवल इनकी मदद से सारे आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते है।

⇒ अमीरों की जेब से पैसा लेकर गरीबों की जेब में डालने का काम सरकार करती है।

⇒ Public से पैसा लेकर Public पर व्यय किया।

लोक आय →

⇒ एक अच्छी Tax Policy के जरिये किसी वस्तु के उत्पादन या उपभोग को बढ़ाने में काम कर सकती है और किसी वस्तु के उत्पादन को घटाने में भी।

⇒ विकास हेतु Communication System मजबूत होना जरूरी।

Study Tide

⇒ Mob. & Computer पर लगने वाला Tax कम करके इसे बढ़ावा दिया।

⇒ इसके बहुत तेजी से इनका दाम घटा - Tax Policy, New Technology } Reason

⇒ Subsidy देकर भी उत्पादन बढ़ाया जाता है - by gov.

⇒ खतरनाक चीजों पर Tax बढ़ाने पर भी उत्पादन या उपभोग कम होने की बजाये बढ़ रहा है- Tobaco Product, Liquor

⇒ Tata Memorial के director ने request किया UP gov पर tobaco शेकने की तो gov ने इस पर 50% Tax बढ़ा दिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

Tax Policy से कई काम किये जाते हैं।

लोक व्यय -

⇒ Infrastructure पर - देशहित हेतु सर्वोपरि

⇒ कीन्स = "सरकार द्वारा किये गये खर्च का प्रभाव सारे आपके खर्च से ज्यादा Powerful"

⇒ 1994 - 1 ₹ का नोट बंद हुआ था।

⇒ मुद्रा की मांग के साथ-साथ मुद्रा की गति भी जरूरी जब शादी, festival, Shadi में मुद्रा की गति सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मुद्रा की गति- धनतेरस
कम " " " - दीपावली का Next day

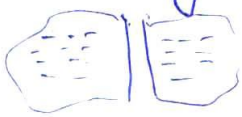

⇒ gov जब खर्च करती है तो देशहित में करती है।
↓
1. पुल 1 करोड़ में बनवाया। सरकार के इस खर्चे का असर पूरे देश को प्रभावित करेगा - यह खर्चा ज्यादा powerful
मांग बढ़ाने में power:- gov. का खर्चा
↓
का असर अर्थव्यवस्था पर होगा

Study Tide

⇒ मंदी के दौरान सरकार खर्चा बढ़ाकर demand बढ़ाती है जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित होती है सबको पैसा प्राप्त होता है

2) विकसित और विकासशील देशों द्वारा किये गये खर्च में ज्यादा खर्चा विकासशील में होगा। विकसित – maintain करेंगे
विकासशील – तथा बनायेंगे

3) Subsidy → Public distribution System द्वारा बाँटी गयी चीजों पर ताकि गरीबों का स्तर बढ़ सके।

* लोक आय और लोक व्यय से सम्बन्धित सरकार की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है"
Tax, Subsidies, प्रतिभूति देकर, ₹

2) Fiscal Sector में बड़ा Reform नहीं हुआ। इसकी वजह से हमारी मौद्रिक नीति भी कमजोर

Public Revenue

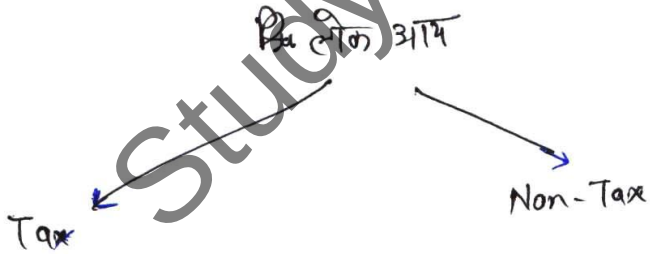

Indian Tax System

⇒

Study Tide

केन्द्र सरकार अधीन Tax

(1) Income Tax

(2) Central exise duty
केन्द्रीय उत्पाद कर
(वस्तुओं के उत्पाद पर – excise duty)
(सेवाओं के उत्पाद पर – Seavice Tax)

(3) सेवा कर

(4) सीमा शुल्क (99% – Import पर आयात

(5) निगम कर (Corporate Tax)

राज्य सरकार अधीन Tax

(1) VAT (Value Added Tax)
वस्तुओं की बिक्री पर लगता है।
~~सेवाओं~~

(2) Toll Tax

(3) Entry Tax (loaded ट्रकों से लिया जाता है)

(4) मनोरंजन कर (Movies पर 50% से ज्यादा)

(5) विद्युत Tax

(6) भू-राजस्व कर, मालगुजारी
(जमीन पर कर, किसानों द्वारा भी
(1 एकड़ – 11 ₹ 1 साल का) – U.P.

(7) Professional Tax (नौकरी करने का)
(बहुत कम)

(8) मंडी Tax (local)

Study Tide

⇒ Service का उत्पादन और बिक्री 1 ही time पर

⇒ 2 वस्तुओं के उत्पादन पर राज्य सरकार Tax लगाती है → Wine / शराब
excise duty
Opium / अफीम
↓
Morphine

UP - मेघालय, खंडवा

⇒ Sales Tax / VAT → Inter state Sales - राज्यों के बीच
Intrastate Sale - राज्य के अंदर

Interstate Sales में VAT → राज्य पर राज्य अलग
↓
तय लगता है CST → Central State Tax (केन्द्रीय बिक्री कर Act 1956)

CST
↓
इसके rules केंद्र बनायेगा
Tax Collection राज्य का
और बाद में profit देगा

In - 1961

⇒ अभी Tax से सम्बन्धित Act पर 1 Tax Exception - Service Tax (1994-95 में आया)
भारत सरकार ने इसके लिये Service Tax Rule बनाया / इसको Excise Act में Merge कर दिया। Excise के सारे Rules इस पर follow होते हैं

Positive list → gov ने कहा जिन Service Provider का इस list में नाम होगा वह Service Tax के दायरे में आयेगा।
धीरे-धीरे इसकी list बढ़ती गयी 150 से ज्यादा service provider आ गये। Apr 2012 के बाद Negative list पर काम किया गया।

Study Tide

Negative List → इसमें जिनका नाम उस पर Service Tax नहीं।
List काफी छोटी
इसके अलावा सभी पर लगेगा।

⇒ All Tax List - Self

⇒ केन्द्र राज्य के मध्य आपसी वित्तीय सम्बन्ध सुधारने को सुझाव - वित्त आयोग
↓
यह ही केन्द्र / राज्य के मध्य % का बंटवारा करता है

		Central	State
~~वर्तमान~~	12 वां वित्त आयोग -	69.5 %	30.5 %
	13 वां " " -	68 %	32 %
(present)	14 वां " " -	58%	42 %

⇒ 13th - State को Sector wise विशेष पैकेज दिया जाये।
14 वें आयोग - State को विशेष पैकेज दिया जाये यह कहा Sector का जिक्र नहीं हुआ।

Classification of Tax

⇒ → वर्गीकरण का आधार सबसे महत्वपूर्ण है
आधार बदलते ही Result बदल जायेगा।

(1) According to Nature -
(1) Direct Tax
(2) Indirect Tax

⇒ जिसके ~~पास~~ ऊपर सरकार Tax लगायेगी वही pay करेगा - Direct
किसी तीसरे पर नहीं भेज पायेगा
कि

⇒ जिसके ऊपर सरकार Tax लगायेगी वही pay करेगा - Indirect
पर bear नहीं करेगा burden transfer करेगा।

Study Tide

⇒ Direct Tax Income पर लगता है इसलिये हम इसको अच्छी shift नहीं कर सकते

⇒ Indirect Tax goods & Service पर लगता है

In Direct Tax - पहले उत्पादन पर Tax - यह Manufacturer से pay करेगा पर एक फिर बिक्री पर Tax burden को Consumer पर डालेगा

↓ seller पर भी Tax ↗

Service Tax ⇒ व्यक्ति IAS पर भी Coaching संस्थानों पर भी

करारोपण & करापात

Incidence Impact →

करारोपण - जिस पर Tax लगता है उत्पादक

करापात - जो in last pay करता है खरीदार

Indirect - GST (Reformed)

Direct - CST (Reformed)

Tax के 4 सिद्धान्त

(1) करदत्ता का सिद्धान्त → हमारा Tax System

कितना easy है कि एक आम आदमी समझ पाये और अपनी इच्छा से pay करे।

भारत का Tax System - दुनिया के सबसे complicated system में से एक।

Case- Vodafone (Tax System के loop hole का फायदा उठाया)

⇒ Language कठिन

⇒ एक तरफा है - GST पर high Rate Tax

Agriculture sector में 18% Tax free

(

Study Tide

⇒ Agriculture — Tax का paradise कहते हैं
क्योंकि लोग इसका उपयोग Black Money को White में convert करने को use करते हैं
इसके लिये Farm house बनाते हैं और Commercial use पर Tax लगेगा पर लोग शादी, पार्टी करते हैं।

Agricultural Income → 3 शर्तें पूरा करे तभी A.I माना जायेगा।

1 & 2 होके

(3) ~~है~~

(1) → Income जमीन से प्राप्त हो।

(2) जमीन खास में हो

(3) खेती में Basic और Subsequent operation करना जरूरी

↓ मस्टर लगाने से पहले खेती के काम

↓ मस्टर लगाने के बाद खेती के काम

के काम

⇒ यह है तभी Agricultural Income माना जायेगा। तभी इस पर Tax नहीं लगेगा

⇒ घास लगाने और उग आने का example

↓

घास लगाकर उसे काटकर बेचने पर मिले Profit पर Tax नहीं लगेगा। पर घास खुद उग आती है तो फिर उसे काटकर बेचा तो Tax लगेगा।

⇒ Farm house का use बीजों को संरक्षित करने, कटी मस्टर रखने हेतु किया जाता है।

Study Tide

-D- 2015

2. उत्पादन का सिद्धान्त (The Principle of Productivity) - Tax इतना हो कि gov. को पर्याप्त आय हो।

⇒ gov. के लिये कभी sufficient आय पैदा नहीं कर पाया Tax चोरी के कारण

3 सक्षमता का सिद्धान्त (Principle of Capability) - क्षमता के according Tax लगे।

⇒ Direct Tax इसको apply करता है

₹, 50,000 - इट (यहाँ तक) Direct Tax

₹, 50,000 - 5,00,000 - 10% ↓

5,00,000 - 10,00,000 - 20% ← Income Tax

⇒ Indirect Tax में गरीब अमीर सभी को same rate पर बेचा जाता है समानता है पर न्याय नहीं ₹ ₹ गरीब के लिये ज्यादा पर अमीर के लिये इतना मायने नहीं रखता।

⇒ Indirect Tax सक्षमता के सिद्धान्त को follow नहीं करता।

Direct Tax बेहतर - Reasons

① Burden shift नहीं हो सकता

② सक्षमता के सिद्धान्त को follow करता है

③ Direct Tax प्रगतिशील है।

Study Tide

⇒ 1951 में वस्तु / सेवाओं का उत्पादन very low

↓

उस वक्त 70% gov की कमाई direct Tax से थी, 30% Indirect Tax

↓

1956 में 2nd Pivot Plan

↓

वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा Indirect Tax बढ़ा

↓

1991 में Service Tax field में विस्फोट हुआ

↓

Service Tax लगाया गया

Present – Direct - 45% ↓

Indirect - 55% ↑

⇒ हमारी gov लोगों पर Direct Tax कम कर रही है पर Indirect बढ़ा रही है
ex Service Tax (12 → 14%), Excise Tax बढ़ा

Indirect Tax उत्पादन से आता है सेवाओं और वस्तुओं का सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आर्थिक वृद्धि होगी।

⇒ हमारी gov Tax policy – Direct Tax कम कर रही
Indirect बढ़ा रही

Gov ऐसा क्यों कर रही है जबकि Direct Tax बेहतर है

⇒ logic → माना सलमा income 5,00,000 , Tax 1,00,000,
4,00,000 खर्च किया तो Indirect Tax भी दिया

Direct Tax न लगे तो 5,00,000 रखेगी तो पैसा ज्यादा खर्च करेगी तो बाजार में पैसा बढ़ेगा

Burden क्यों कम किया जा रहा Direct Tax का है

Reason - क्योंकि भारत में Tax चोरी, Direct Tax field में बहुत ज्यादा।

Study Tide

=) सबसे ज्यादा Black Money को White Money में change करने का best option - Real Estate

=) Mutual fund legal
↓
अब यही काम illegal तरह से - सबने इकट्ठा करके । fund बनाया black Money का इसे कहते हैं- Hedge fund

फिर इस पैसे को Real Estate में लगाया जायेगा । इसीलिये Real Estate का दाम बहुत तेजी से बढ़ा । पर अब पतन हो रहा है

↓

कोई भी bussiness तभी grow करता है जब Middle class का उसमे हिस्सा हो पर Real estate की value बहुत ज्यादा होने के कारण Middle class की Range से बाहर आया । इसलिये लोगो ने खरीदना बहुत कम हो गया । यह Market suffer करेगा । केवल high Income लोग ही इस Market में रहेंगे।

↓

Real Estate सबसे बड़ा कारण

↓

demand में कमी

=) Direct Tax में बहुत ज्यादा चोरी
कुछ cases में चोरी रोकना Impossible
चोरी का example - एक bussinessman ने office हेतु vacany का add दिया

↓

Add में salary - 10,000 ₹

↓

शर्त - bussinessman salary check से pay करेगा। लेकिन ₹0,000 का check देगा । जब clear होगा तब 10,000 रखकर ₹0,000 वापस मुझे करेगे।

↓

इसमे व्यक्ति को कोई नुकसान नही

↓

पर balance sheet में बचा - ₹,40,000 (Tax बचा)
पर Real - 1, ₹0,000

Study Tide

⇒ इसमें 1,20,000 का real profit है इसको पकड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि लिखित में कहीं नहीं आयेगा। इसको रोकना impossible

⇒ Gov के लिये Direct Tax चोरी रोकना Next to Impossible पर Indirect Tax को Control करना easy है इसीलिये बेहतर होने पर भी इसे apply न किया जायेगा।

(4) Double Taxation न हो ⇒

⇒ Double ही नहीं असल में Multiple Taxation है (यह उत्पन्न है)

इन सब वजहों से भारत में Tax Reform जरूरी → Big Level पर Drastic Major

Tax Reform - ~~Start~~ from 2010

All Indirect Tax - GST (Goods & Service Tax

All Direct Tax - DTC - 2010 का

GST

⇒ उम्मीद है जल्द ही लागू (1 Apr 2016)

⇒ GST Concept 2011 का है

⇒ gov के lack of Commitment की वजह से लागू नहीं हो पा रहा

GST है क्या ⇒

Goods Case - उत्पादन एवं बिक्री अलग राज्य पर निर्भर

वस्तु का पहले उत्पादन - केन्द्र सरकार
↓
उत्पाद कर

बिकता है - राज्य सरकार
↓
VAT

Study Tide

Example

पूरे देश में एक सा ↑ Excise Rate 10%

हर राज्य में अलग-अलग ↑ VAT 10%.

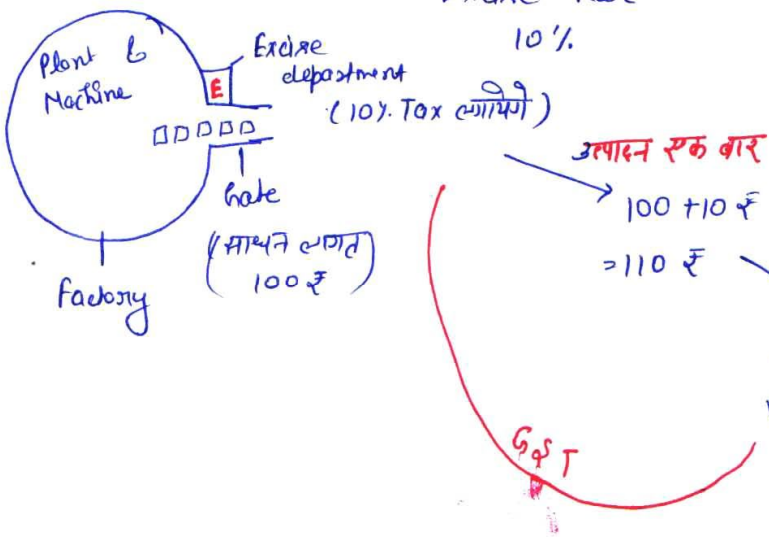

Double Taxation ↑ दुबारा बार बार

उत्पादन कर्ता पहला विक्रेता

VAT लगेगा 10%

↓

110 ₹ + 10 ₹

⇒ 120 ₹ MRP

(Inclusive of all Taxes)

↓

वस्तु की कीमत State wise अलग-2

⇒ कच्चे तेल की Refining भी उत्पादन माना गया इस पर भी Tax लगेगा

C. Excise Tax और State भी लगेगा। इसी कारण Petrol Diesel Rate vary करता है।

⇒ State और Central चाहे तो अपने Tax कम कर सकती हैं

⇒ 2013 में गोवा सरकार ने Tax कम किया 10 ₹/ ~~किलो~~ lt

I^st Problem - कीमतो में अन्तर

II^na " - 2 Agency काम करती है- Tax Collection में खर्चा बढ़ेगा।

↓

2 Network use Central, State

100 ₹ कमाया 10 ₹ Tax Dip पर खर्च

90 ₹ income

↓

Network बड़ा / ज्यादा Tax Collection खर्चा ज्यादा

Study Tide

III rd Problem - Tax department में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा
Network वाला तो Corruption भी ज्यादा

⇒ आम आदमी Tax Rate समझ नहीं पाता।

⇒ GST आयेगा तो GST – Excise & VAT को replace करेगा
केवल एक ही Tax लगेगा।
पूरे भारत में कीमतें 1 जैसी हो जायेगी

Delay क्यों हो रहा -
GST में State और केन्द्र दोनों शामिल
⇒ राज्य सरकारों की सबसे बड़ी आय - VAT के जरिये
⇒ केन्द्र और राज्य में आम सहमति नहीं बन पा रही।

I st मुद्दा → GST का ~~x~~ किसको आये केन्द्र या राज्य ?
⇒ बँटवारा किया जायेगा

II nd " ② GST का Rate एक या अलग-अलग है?
एक Rate - Necessity और luxury goods पर एक ही Tax लगेगा।

III rd " main मुद्दा ③ GST Collect कौन करेगा? Central OR State
↓ करेगा तो कर PCS pool रखेगा
↓ करेगा तो UPSC में कर pool रखेगा

इस पर आम सहमति – कि आधा आधा Collect करेगी।

④ कुछ राज्यों ने Petrol, Wine को GST के बाहर रखने को कहा गया। फिर Electricity और Entry Tax को GST से बाहर रखने की माँग आयी।
↓
Entry Tax - GST में है
Electricity + Petrol + Wine (GST से बाहर रहेगा)

Study Tide

VAT

Value Added Tax

⇒ Tax system flexible होना चाहिये।

⇒ VAT ज्यादा flexible जबकि Central Tax Non flexible।

Ex - Delhi VAT →

Delhi gov

↓

5 schedule बनाये (सभी में वस्तुओं की सूची)

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
↓	↓	↓	↓	↓
कुछ वस्तुयें	□□□	□□□	□□□	□□□
Tax - 0%	Tax - 1%	5%	12.5%	20% (Bill पास करके gov. को अधिकार इसे बढ़ाने का ↓ Petrol / Diesal ↓ 30% तक किया जा सकता है पर सरकार ने 25% किया)
↓	↓			
40 items	gems &			
daily items	jewellary			

⇒ U.P का schedule - 5

Rescheduling करके वस्तुओं पर Tax बढ़ाया जाता है Notification जारी करके। इसके लिये विधानसभा में Bill pass करना जरूरी नहीं।

⇒ अगर Tax percentage बढ़ाना हो तो Bill Pass कराना होगा।

Budget → Department of Economic Affairs बनाता है

28 Feb बजट आया

↓

Income Tax Act 1961 – बदलाव Finance Bill के जरिये होता है

↓

Income Tax में बदलाव की घोषणा की जाती

↓

पर लागू तब होगा जब Parliament pass होगा।

Study Tide

⇒ Finance Bill केवल 1 year के लिये valid

⇒ 1 साल बाद बदलाव नहीं भी करना तो भी parliament में pass करना पड़ेगा - यह Tax System को बेलोचदार बनाता है। वर्तमान परिस्थिति में globalization के दौर में ताकत होना जरूरी।

⇒ VAT में लोचशीलता ज्यादा

⇒

NBFC / NBFI

Non Banking Financial Institution

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान

Bank ← Primary } - दोनों काम करते हैं — जमा स्वीकार, loan देना
Scondary

NBFc - केवल loan देता है

विशेष scheme के तहत ही जमा करते हैं (हमेशा जमा स्वीकार नहीं करते)

RBI

New Payment Banking - ✗ जमा स्वीकार करेंगे पर loan नहीं देंगे (11 Banks को license दिया गया)

⇒ 2013 में New Banking Act आया - Banking Bussiness बहुत easy कर दिया गया।

⇒ अब Banking Bussiness शुरू करने को 500 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी।

↓

RBI के पास 26 application आया

↓

1 ने withdraw किया (Tata gp

↓

2 को मिला license (Bandhan,

Study Tide

⇒ license जारी होने के बाद 18 महीने का time दिया जाता है Infrastructure develop करने को फिर Bussiness शुरू करने का application दिया जाता है

↓

फिर काम शुरू होता है

NBFC → भारत में काफी पुराने, growth बहुत बढ़िया

ex Manipuram gold

Most popular → Muthu finance

⇒ यही लोग gold के बदले loan देते हैं

Margin Money - संस्थाये 100% loan नहीं देती

Bank asset value के Base पर Margin लेता है

ex. 10,00,000 की building पर 20% Margin यानि 8,00,000 का loan मिलेगा।

क्योंकि Land का rate fluctuate करता है तो Bank का पैसा safe नहीं Home loan में Bank मकान के Value का 80% loan देता है

100% loan देने पर नुकसान - पूरा loan मिला

↓

मकान खरीदा किराये पर दिया

↓

Return आया सारा पैसा चुका दिया

↓

Customer की जेब से कुछ नहीं गया

Certain time के बाद मकान Customer का

इसीलिये Bank नहीं देता RBI ने Margin Amount 40% बढ़ा दिया

⇒ Gold पर 50,000 तक छूट इससे ज्यादा के gold पर proof of ownership चाहिये (proper Bill जरूरी)

⇒ Bill loan लेने में काम आता है

⇒ Gift में gold + bill देना चाहिये।

Study Tide

⇒ Central - avg rate 25 - 26% रखेंगे। एक Tax Rate रखेंगे।
State - avg rate 10 %. रहेगा।

⇒ GST - 122nd Amendment

IV th मुद्दा - State कहते हैं कि GST लगने के बाद हमारी Income में कमी हो तो हमें Compensation दिया जाये।

↓

13 वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया - 50 हजार करोड़ का fund

↓

जो Compensate करे।

State ने कहा शुरू के 5 साल Compensation मिले पर Central केवल 3 साल तक देने को तैयार

⇒ सहमति हुआ कि 3 साल तक Compensation मिलेगा 4th साल 75 % Compensation और 5th साल 50 % मिलेगा।

⇒ Double Taxation का प्रभाव सबसे ज्यादा - Sales Tax में

क्योंकि वस्तु का उत्पादन एक बार पर बिक्री कई बार

1980 में इसे Improve करने की कवायद शुरू हुई। Instrument design किया गया — VAT पर यह लागू नहीं हो पाया। Committee बनी L.K. Jha समिति — इन्होंने Mod VAT (1986) का Concept आया। पर इसमें भी कमियां थी → फिर वापस पुराना Tax लागू हुआ → 2000-2001 में New VAT आया → फिर लागू हुआ → Double Taxation रोकने में इसकी बड़ी भूमिका।

VAT हर जगह है जहाँ double Taxation है -

Cen VAT - Central VAT — Excise में लगता है — इसे भी खत्म किया गया।

Servica Tax - double Taxation खत्म किया गया।

Study Tide

VAT क्यों बेहतर → Comparative with Old Tax

⇒ Example → Tax Rate - 10%

पुराना Tax System →

Ⓐ (पहला विक्रेता) → Ⓑ खरीदार (बेचेगा को) → Ⓒ (बेचेगा) → Ⓓ को

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
100 ₹	110 ₹	165	220 ₹
10 ₹ (Tax)	40 ₹ (VA - Value Addition खर्चा + profit)	35 ₹ (VA)	
110 ₹	Sale 150 ₹	200 ₹	
	Sales Tax - 15 ₹ - Tax	+20 ₹ (Tax)	
	165 ₹	220 ₹	
①	②	③	

एक ही value पर 2 या 2 अधिक बार Tax pay करे तो double Taxation.

100 ₹ पर Tax 3 बार — double Taxation (Multiple Taxation also)

40 ₹ पर 2 बार

35 ₹ पर 1 बार

Cascading Effect - 1 ही value पर बार बार Tax

⇒ Consumer का नुकसान — सरकार का फायदा

10 + 12 + 20 = 45 ₹ (Tax)

⇒ जितना लम्बा Network उतना ज्यादा Tax

VAT के बाद →

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
100	100	154	192.50
Tax 10 ₹	40 (VA).	+ 35 ₹	
110 ₹	Tax 150 ₹ = 150	189 ₹ Tax	
	40 का 10% +4	38.5	
	154 ₹	192.50	

(मूल्य वर्द्धन पर Tax)

Study Tide

⇒ VAT ज्यादा बेहतर केवल बढ़े हुये पैसो (VA) पर Tax.

⇒ VAT - Multipoint Tax System
Excise - One Time

⇒ VAT के बाद चीजो में गिरावट मूल्य में क्योंकि Cascading effect खत्म

200.0 - old
192.5 - VAT
7.5 £ का फायदा

⇒ Consumer का फायदा = gov का नुकसान
10 + 4 + 3.5 = 14.5 £

45 £ - old
17.5 - VAT
27.50 £ का नुकसान

⇒ VAT के बाद सरकार (State) की Income में कमी हुयी।
⇒ ऐसा जरूरी नही कि State की Income में कमी हो
Income में बढ़ोत्तरी भी संभव

↓

Logic - Tax per unit - प्रति वस्तु Tax कम होगा लेकिन VAT के बाद कीमते गिरेगी Market expand करेगा। Sale बढ़ेगा। पहले सरकार बेचते थे अब वे बेच पायेगे।

Total Tax

↓

Total Tax बढ़ जायेगा। ज्यादा बिक्री से

⇒ पहला राज्य VAT लागू किया - Haryana (2005)
last राज्य - UP

⇒ Delhi - 1 Apr 2005 से लागू। Delhi gov quaterly detail देती है Taxation का। देखना था बढ़े हुयी या कमी। Report में आया कि पिछली बार से एक बार 3 करोड़ का फायदा हुआ।

⇒ VAT अभी भी भारत में 1, 2 जगह लागू नही - Andman Nicobar
Lakshdeep
exam में पूछेगा - VAT पूरे भारत में लागू नही ↑ reason

DTAA - IR का part

Study Tide

⇒ Wealth Tax 1957 का जो एक तरह रद्द कर दिया गया।

DTC - 2010 का (Direct Tax को replace करेगा)

DTC delay का कारण - 8th Clause

GAAR - General ~~Agency~~ Entry Avoidance Rule

→ हमारा Tax System weak, लोगों ने Tax बचाया (Biggest Case - Vodafone)

→ Vodafone - 9,~~000~~ हजार करोड़ बचा लिया

→ Hutch का अधिग्रहण भारत के बाहर किया तो Income Tax बच गया

→ प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री ने Vodafone पर 9000 करोड़ का दावा किया

→ Vodafone ने pay किया फिर Supreme Court गये

→ आदेश आया कि 9 हजार करोड़ 1800 करोड़ ब्याज के साथ वापस करें। GOI ने 10800 करोड़ Vodafone को pay किया।

Retrospective - Back date से Tax लागू करना (गलत)

→ मंहगाई अक्सर Back date से लागू होता है

→ ऐसे लागू करने वाला Britain प्रथम देश।

⇒ GAAR का feature →

Tax Authority को special Power दिया गया है

↓

अगर पता चला कि जान कर Tax बचाया गया

↓

तो वे उस Transaction को Tax सीमा में लाकर Tax pay करेंगे। करायेंगे।

↓

भारत जैसे भ्रष्टाचारी देश में use की बजाये misuse होने की पूर्ण सम्भावना

② External front पर कोई Reporting Machanism नहीं।

↓

India से कितना Capital बाहर गया RBI के पास है पर वापस आके Capital कहाँ है किस form में पता नहीं

↓

GAAR में Reporting Machanism लागू किया गया है कि वे RBI को external front का पूरा ब्योरा दें।

Study Tide

⇒ इस पर कमेटी आयी पार्थ सारथी सोम कमेटी - इन्होंने Report दी - कि भारत सरकार GAAR लागू करे पर धीरे धीरे (3 Nov 2012)

⇒ 28 Feb 2013 में election से पहले एक लुभावना बजट ~~आया~~ नहीं आया फिर 5 Mar 2013 को आया क्योंकि Goa में चुनाव था

⇒ इस बजट में कहा गया कि decide किया गया है कि GAAR को 3 साल के लिये टाल दिया जाया

↓

अब 1 Apr 2016 को फिर लागू ~~होगा~~ होता है साथ ही GST भी आयेगा।

⇒ 2014, 2015 दोनों Budget में DCT पर silent है बजट। पर wealth Tax खत्म किया और कहा।

↓

"DTC जिन प्रस्ताव की बात कर रही है वह प्रस्ताव इस Direct Tax में कर चुके है"

↓

अब फिलहाल की DCT का मामला न है। पहले GST आयेगा और शायद यह रुका रहा तो DCT का कुछ हो। (यह देखना होगा)

According to Rate - Classification of Tax.

① प्रगतिशील Progressive Taxation
② समानुपाती Proportional Taxation
③ प्रतिगामी Regressive Taxation

1 प्रगतिशील - इसमें ~~अमीर~~ गरीबो से पैसे नहीं पर अमीरो से पैसे Tax लिये जाते है गरीबो को Tax में छूट

Income Tax प्रगतिशील - Direct Tax

2015 - 2016 -

2,50,000 — 0% NIL (यहाँ तक)

Study Tide

₹,50,000 से ऊपर इस हेतु धारा 80(c) main में इसमें 1,50,000 तक निवेश करने पर Tax में इस उसमें list की है इसी ex सरकारी प्रतिश्रितियाँ, LIC policy, Provident fund, PPF,

धारा 80(d) - Medical Insurance

यदि Mediclaim लिया है तो 80(c) के 1,50,000 के अलावा ₹5000 पर और Tax नहीं पड़ेगा

₹,50,000 + 1,50,000 + ₹5000 = 4,50,000 पर Tax इस

automation tax इस — निवेश

70
25
45

⇒ Share, debenture पर इस नहीं

Upto ₹,50,000 — NIL

Next ₹,50,000 — 10%

If yearly income - 3,00,000 - ₹,50,000 पर इस

50,000 पर 10% tax

~~₹50,000~~ + 5000 = ~~₹550~~

Tax

Next - 5,00,000 — ~~20~~ 30%

Above 10,00,000 - 30%

If 7,00,000 income

5 { ₹,50,000 - 0%
₹,50,000 - 10% - ₹5000
₹,00,000 - ₹0% - 40000
65000 tax

Study Tide

₹ 50 000 तक - NIL
Next ₹,50,000 तक - 10%
Next 5,00,000 तक - 20%
Next 10,00,000 तक - 30%
] - Income Tax

=) Progressive होने के कारण सक्षमता के सिद्धान्त को follow करता है।

CESS - Education CESS (Tax)

जितना Tax बनता है उसका 2% CESS देना होगा। इस पैसे को शिक्षा को बढ़ाने में use होगा

Tax 65000 — 2% Tax — 1300 Tax

फिर आया 1% high education CESS आया

Tax 65000 - 1% Tax — 650 Tax

मतलब 65000 Tax पर 3% extra Tax

=) Service Tax 12% और CESS - 12% का 3% -0.36

12+.36 = 12.36% - Service Tax था

↓

अब 14% है — 14+ 14 का 3% = 14.42% हुआ

↓

पर gov ने कहा 14% में यह दोनों include है

=) Best Tax

2 Propational Tax - Most Simpler Tax

=) जिसका जितना income उसका 10% Tax दिया जायेगा। इसमें Tax की मात्रा अलग अलग होगी पर आय में आय की असमानता है। इसलिये यह सरल है पर सक्षमता के सिद्धान्त को follow नहीं करता

=) India में कहीं भी पूरी तरह समानुपाती नहीं

Study Tide

3 Regressive - जिसमे गरीब अपनी income का ज्यादा % tax देते प्रतिगामी है जिनका income ज्यादा वह कम % देते हो यह समानता के सिद्धान्त को follow नही करता।

⇒ हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष कर का घात बढ रहा हो उसके ऊपर लगने वाला Indirect Tax कैसा Tax है

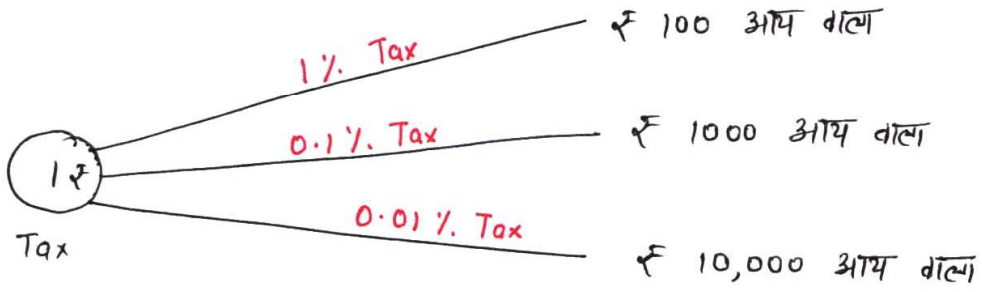

Regressive - हम पर लगने वाला Indirect Tax

Equility & Justice

⇒ हमारी Reservation Policy - Justice dependent not equality

⇒ Way to Improve - Indirect Tax को प्रगतिशील बनाया जाये पर how, it is a mystery till today!

⇒ लोक व्यय प्रतिगामी होना चाहिये Income बढ़ने के साथ rate घटे। गरीबी कम हो तो rate कम हो।

Classification - According to Usage

1 Ad - ~~vade~~ valorum

2 Specific

1 Ad - Valorum - Excise duty

↓

Basic excise duty - minimum - 10 % वर्तमान में

Study Tide

⇒ ~~10%~~

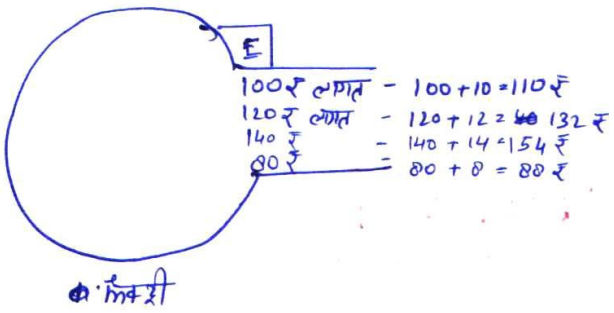

⇒ जब Value पर Tax लगे - Ad Valorum example

⇒ लागत पर Tax लगता है जितनी साधन लागत बढ़ेगी उतना Tax बढ़ेगा। जितनी मंहगाई बढ़ेगी उतनी साधन लागत बढ़ेगी। उतना Tax बढ़ेगा।

⇒ मंहगाई का % बढ़ते ही gov को खुद ही extra paise मिलेंगे बिना Tax rate बढ़ाये

⇒ Ad Valorum is flexible क्योंकि अगर बीच में change करना चाहेंगे तो देगा नहीं Parliament में bill pass कराना पड़ेगा इसलिये यह व्यवस्था अच्छी

⇒ चेलैया समिति ने कहा - "भारत का Tax system ad valorum होना चाहिये"

Specific -

⇒ Toll Tax में प्रत्येक गाड़ी पर Tax, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो। यह specific Tax है -

⇒ Parking Tax - Specific Tax

⇒ Agra Tourist - Specific Tax प्रत्येक को same rate

माना gov चीनी पर Specific Tax लगायेगी यानि पर ₹/किलो।

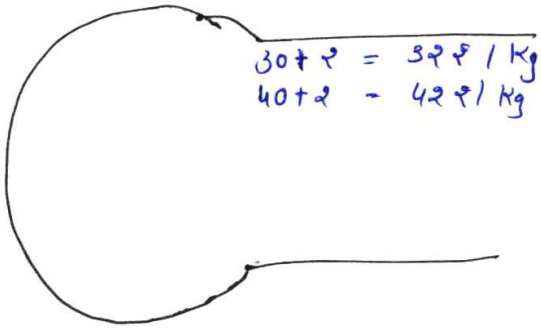

Study Tide

⇒ Specific किसी special चीज पर लगता है Kg, रु., वजन etc

⇒ जहाँ Ad Valorum use नहीं हो सकता वहाँ Specific Tax use होता है

BUDGET

⇒ Department of Economic Affairs - बनाता है

⇒ पहले growth rate तय → फिर खर्च → फिर पैसा → माध्यम → Tax & Non Tax → इनसे पूरा न होने पर → अन्य विकल्प → उधार, विनिवेश, FDI, FPI

सरकार की प्राप्तियाँ
- पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Recipt)
- राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Recipt)

सरकार के खर्च
- पूँजीगत व्यय (Capital Exp^n)
- राजस्व व्यय (Revenue Exp^n)

1 पूँजीगत प्राप्तियाँ - "जिन प्राप्तियों के बाद या तो सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाये या सम्पत्तियों में कमी हो जाये।"

- Liability बढ़ेगी (दायित्व)
- Asset कम होगी

(i) Liability बढ़ेगी - loan लेने पर कहीं से भी लिया जाये - Borrowing / Rent उसको वापस भी करना पड़ता है gov को

(ii) Asset कम - विनिवेश (Disinvestment)
ऋण की वसूली

Study Tide

NPA - Non Performing Asset

ऐसा Asset जिसके आय का सृजन खत्म हो जाये जिसको loan दिया जाये वह सारा पैसा डूब जाये।

यही हमारे पुराने Banking Sector के पतन का कारण था।

इसमे 86% - Gov. Bank loan देते हैं - Performing Asset

⇒ भारत गरीब देशो को ~~ब्याज~~ देता है पर ब्याज नही लेता। तो इस पर भारत को कोई फायदा नही। क्योंकि पैसा ब्याज नही मिलता बस मूल वापस मिल जाता है और भारत की asset मे कमी हो जाती है - NPA - इसे ऋण की ~~चोरी~~ कहते है

⇒ Past की Massive Borrowing से present मे सरकार घाटे मे है क्योंकि 1₹ मे 90 पैसा खर्चे मे जाया है जिसमे सबसे ज्यादा ब्याज

खर्चे - Planned खर्चा Vs Non Planned खर्चा

Development खर्चा Vs Non Development खर्चा

⇒ Interest → किस तरह का खर्चा - Fixed & Compulsory

ऐसे खर्चे की Planning नही होती जो देना ही देना है।

⇒ Non - Planned Expenditure

⇒ विनिवेश → Present मे पैसा ज्यादा

पर future मे पैसा सृजन करने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि इसका Rent किसी और को मिलेगा।

⇒ Borrowing → Present मे पैसा ज्यादा

future मे पैसा कम, प्रभाव पड़ेगा।

Borrowing / विनिवेश - मे कोई बेहतर नही।

⇒ इसलिये सरकार को हमारी पूंजीगत प्राप्तियो का use नही करना चाहिये - Villain

यह बाद मे नुकसान मे आ जायेगे।

Study Tide

राजस्व प्राप्तियाँ -

जिन प्राप्तियो के बाद न तो सरकार के दायित्व मे कमी हो न ही उसकी सम्पति मे कमी हो।

2) जो पूंजीगत प्राप्तियां नही वे राजस्व प्राप्तियां

2) यह Best है - सरकार की अपनी कमाई है

⇒ Revenue - Interest , किराया , Profit ,

⇒

खर्चा

1 पूंजीगत व्यय - "जिन खर्चों के बाद या तो सरकार के दायित्व मे कमी आ जाये या सम्पत्तियो मे वृद्धि हो जाये।"

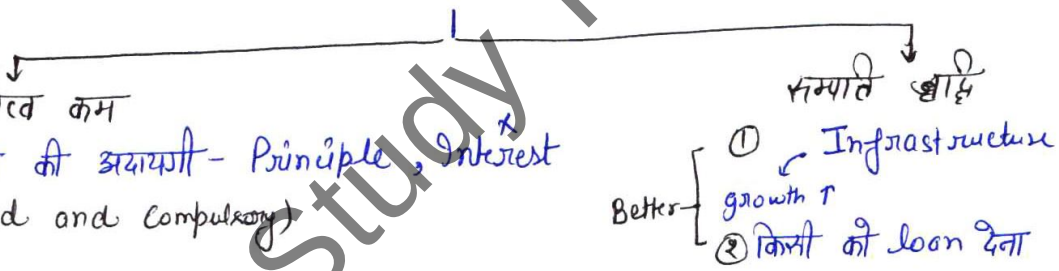

Study Tide

⇒ माना 100 ₹ loan लिया / आज 100 ₹ 50 ₹ ब्याज के साथ वापस किया / क्योंकि यह Debt Service Charge कहलाता है ब्याज।

मूल - Capital exp"

ब्याज - Revenue Exp" - यह इसके का asset use करने के कारण दिया।

⇒ Infrastructure अच्छा होगा तो growth बढ़ेगी।

⇒ loan देने पर ब्याज मिलेगा । Asset मे बढ़ोत्तरी होगी।

2. राजस्व व्यय - "जिन खर्चों के बाद या कारण न तो सरकार के दायित्व के कमी हो न तो परिसम्पत्तियों मे बढ़ोत्तरी हो"

⇒ राजस्व व्यय - Maintenance Cost है

Salary Payment, Law & Order maintenance,
Interest भी इसी मे आयेगा
बाकी सब maintenance पर खर्चा करने ही पड़ेगा।

⇒ पूंजीगत व्यय देश को आगे ले जाने का खर्चा और राजस्व उसके maintenance का खर्चा। - Municipal Corporation

⇒ पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय भी बढ़ेगा।

सरकार का घाटा

| खत्म करने का तरीका

खर्चे कम करके — income बढ़ा कर

1. खर्चा कम करके →

(i) पूंजीगत व्यय - Repayment of loan - नहीं घटा सकते क्योंकि fixed & Compulsory

(ii) - Infrastructure - कम नहीं कर सकते क्योंकि growth प्रभावित होगी।

Infra. निवेश रुक जाये तो → देश

गड्ढे मे

Study Tide

राजस्व व्यय - Interest नहीं घटा सकते
Maintenance भी नहीं घटा सकते।
Law & Order पर कम नहीं कर सकते
Salary कम नहीं कर सकते।

2 scope - पेंशन खत्म करो
Subsidy खत्म करो } 2004 की report

↓

4 इसी आधार पर पेंशन खत्म कर दिया गया
अब Subsidy पर बात चल रही है कि खत्म किया जाये या बेहतर तरीके से लागू किया जाये।

DBT का Concept आया - Direct Account में Transfer - benefit
↓
इसी में जन धन योजना आयी।

2 प्राप्तियों को बढ़ाकर - Borrowing
Asset बेचना } इन दोनों का present में फायदा Future में नुकसान

Revenue - Tax
Non-Tax] - सबसे ज्यादा scope
↓
Tax Reform जरिये। ही सम्भव। यह पर्याप्त मात्रा में आय का सृजन कर सकते हैं

FRBM Act - Fiscal Responsibility & Budget Management Act
↓
Revenue Let Consolidation (वित्तीय)
↓
Suggestion
राजस्व प्राप्तियां बढ़ाई जाये Tax को Reform & Systematic करके।

Study Tide

⇒ भारत सरकार Case - 3 में है खर्चा ✓ आमदनी से ज्यादा।

RR	RE
राजस्व प्राप्ति - 100 ₹	राजस्व व्यय - 150 ₹
⇒ Tax और Non Tax से प्राप्तियां काफी कम खर्चे की तुलना में।	

Revenue Deficit

① राजस्व घाटा = RR - RE (RR < RE)
कम ज्यादा

↓

राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय से कम

⇒ 100 - 150

= -50 ⇒ (50)

घाटे को negative में न लिखके bracket में लिखेंगे।

⇒ भारत सरकार राजस्व घाटे में है पर भारत का एक राज्य गुजरात, राजस्व Surplus में है इसीलिये गुजरात में पूंजीगत व्यय (Infrastructure) ज्यादा है

"आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया"

② पूंजीगत खाता

पूंजीगत प्राप्ति (CR) — Total - 300

- Borrowing 200 ₹
- विनिवेश 100 ₹

300 - 50 = 250 ₹ राजस्व घाटा

पूंजीगत व्यय (CE)

- Repayment of loan 50 ₹ (~~राजस्व घाटा~~) 250 - 50 = 200
- Infrastructure 200 ₹ ↓ Growth में काम आएगा।

Study Tide

→ पूंजीगत प्राप्तियाँ तब तक पुरी नहीं जब तक पूंजीगत व्यय हो पर यदि पूंजीगत प्राप्तियो से राजस्व प्राप्ति पर ज्यादा व्यय हो तो यह गलत है।

"कर्ज लेकर घी पीने वाला हिसाब"

पूंजीगत प्राप्ति का राजस्व भाग पर व्यय

↓

उसके future में earn करने की क्षमता कम हो जायेगी।

Golden Rule of Budget → पूंजीगत प्राप्तियाँ हमेशा पूंजीगत व्यय पर खर्च हो।

~~New~~ (2) प्रभावी राजस्व घाटा -

2010 में पहली बार use हुआ word. — प्रणव मुखर्जी (वित्त मंत्री)

Revenue A/C

RR	RE
100 ₹	150 ₹

राज्य सरकारो को दी गयी अनुदान सहायता

Grant - 30 ₹
C.E - 20 ₹
R.E - 10 ₹

State को grant — Capital Exp^n C.E.
— Revenue Exp^n R.E.

C.E का use देश निर्माण में होगा राज्य द्वारा तो

Total घाटा 150 - 20 = 130 ₹

↓

प्रभावी राजस्व घाटा

Study Tide

27/8/2018

Structure of Budget

बजट का स्वरूप

बजट व्यवस्थित ढंग से दो खातो मे show करेगे →

1 राजस्व खाता (Revenue Account)

2 पूंजीगत खाता (Capital Account)

Revenue Account →

राजस्व प्राप्तियां

1 यह "हमारी अपनी कमाई"
→ Person level पर

(a) माना हमारी salary - 8000
saving - 2000
इसी saving से बाद मे उपभोग किया जायेगा। - Best Case
→ Regular कमाई पर्याप्त हो व्यय हेतु और saving भी आवश्यक

(b) Salary - 10000
No Saving
यह worst नही पर इतना भी बुरा नही। गुजारे लायक

(c) Salary - 10000

राजस्व व्यय

1 यह "हमारा Personal खर्चा"
- Person level पर
हमारा खर्चा - 6000

व्यय - 10000

व्यय - 12000 - 2000 का घाटा
न income बढ़ा सकते
न खर्चा कम कर सकते
2 option ← Borrowing
~~पैसा~~ asset बेचे

Study Tide

~~राजस्व प्राप्तियां~~

⇒

Debt Trap - एक loan को चुकाने के लिये दूसरा loan लेना। यह सबसे ज्यादा नुकसान देय एक बार इसमे फसने के बाद निकलना मुश्किल।

⇒ राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति से ज्यादा नही होना चाहिये।

⇒ क्योकि इसमे loan और ब्याज बढ़ता ही जायेगा और एक दिन loan देने वाले ~~loo~~ लोग मना कर देगे क्योकि उनका कर्ज से इवे व्यक्ति से return देने का यकीन खत्म हो जाता है।

⇓

यही यूरोप का संकट है

⇒ यूरोप मे लोगो का सरकार से यकीन उठ चुका है (निवेशको का)

⇒ यूरोप के निवेशक यूरोप की बजाये अन्य देशो की प्रतिभूतियां खरीद रहे है

⇓

Crisis of Confidence

राजस्व व्यय

⇒ Jan मे २००० का loan लिया पाय इसा करने को, loan मिल गया ब्याज दर समय तय हो गया। 6 महीने का time तय हुआ।

⇒ Feb मे भी salary 10000 खर्चा १२००० Jab मे खर्चा १२००० + ब्याज 100 ₹ माना

Total खर्चा ~~१२०००~~ १२१०० ₹

अब २१०० loan लेना होगा।

⇒ किसी अन्य व्यक्ति से २१०० का loan मांगा। यह Risk ज्यादा है इस लिये ब्याज दर भी ज्यादा लेगा ब्याज - २०० ₹

⇒ March मे पाय और बढ़ जायेगा

१२००० + २१०० + २०० = १२३०० ₹

⇒ हर महीने loan की माला ज्यादा ↑ ब्याज भी ज्यादा। ↑

⇒ 6 महीने बाद खर्च 1000 हो गया तो 7th महीने मे loan 5000 होगा

↑

debt Trap

Study Tide

प्रभावी राजस्व घाटा = केन्द्र सरकार का राजस्व घाटा – राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु दिया गया अनुदान

Total Income	Total Exp^n
100	150
+ 300	+ 250
400	400

⇒ No Sir plus No deficit – यह सरकार का कहना है

Real Condition →

Income

राजस्व प्राप्ति – 100 ₹
पूंजीगत प्राप्ति –
उधार – 200 – घाटा
विनिवेश – 100
400 ₹

Government Exp^n

RE	150
CE	250
	400

⇒ World level पर घाटे में सिर्फ उधार को लिया जाता है

⇒ 200 ₹ का घाटा – राजकोषीय घाटा

③ राजकोषीय घाटा → Fiscal Deficit

⇒ सरकार के Total खर्चे में Borrowing का योगदान
⇒ यह घाटा सरकार के दोनो खर्चों को ध्यान में रखके निकालेंगे।

Study Tide

⇒ राजकोषीय घाटे में बढ़त का मतलब सरकार के Total खर्चे में Borrowing का % बढ़ गया।

last year - 100 ₹ पर 10 ₹ - उधार

This year - 200 ₹ पर 16 ₹ - उधार ↑ → राजकोषीय घाटा बढ़ा

⇒ भारत में घाटे को GDP से Compare किया जाता है

GDP - 1 साल में देश का कुल उत्पादन

Production = income = expenditure

माना राजकोषीय घाटा - 5% last year

GDP = 100 ₹ (income) ⇒ 5% Borrowing = 5 ₹

⇒ राजकोषीय घाटे का बढ़ना → सरकार के खर्चे में Borrowing का बढ़ना

↓

Debt Trap की तरफ बढ़ना

⇒ राजकोषीय घाटा 1 year के base पर आता है

2014 - 100 ₹ GDP — 5 ₹ उधार

2000-2013 तक - loan - 45 ₹ तो अब Total 45 + 5 = 50 ₹

loan = 100 का 50% = 50 ₹

↓

Debt to GDP ratio

$$\frac{\text{Debt}}{\text{GDP}} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{GDP}} \Rightarrow \frac{50}{100} = 50\%$$

इसका बढ़ना गलत।

⇒

$$\frac{\text{Debt}}{\text{GDP}} = 69\% \quad \text{(Global Average)}$$

Study Tide

India. $\frac{Debt}{GDP}$ = 60% था ⇒ अब 90% के आस पास

China $\frac{Debt}{GDP}$ = 46% था — 3 साल पहले

America $\frac{Debt}{GDP}$ = 100% + था

Europe $\frac{Debt}{GDP}$ = 150% + था

Greece $\frac{Debt}{GDP}$ = २२१% था

Japan $\frac{Debt}{GDP}$ = 342% था

अब →

China = २१२% हो गया है

Global - 90 - 92% के आस पास

पोटे की वित्त व्यवस्था (1997 में बंद)

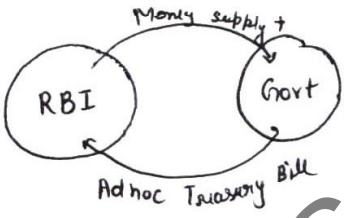

Demand ↑

Supply ↑

मौद्रिक नीति ↑

⇒ Capital Receipt ← राजकोषीय नीति

सरकार के लिये पूंजीगत प्राप्ति

⇓

पूंजीगत व्यय

⇓

पूंजी निर्माण पर बढ़ेगी

⇓

उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी

⇓

उत्पादन होगा ⇒ Supply बढ़ेगी।

Study Tide

Problem -

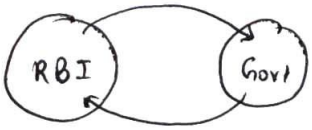

→ Capital Receipt → Revenue Exp^{n} – Leakage

⇓

C. E

⇓

Capital formation ↓

⇓

Production ↓

⇓

Production में कमी आयी

⇓

Supply में कमी

Problem Solving → जब तक राजस्व घाटा खत्म नहीं होगा तब तक यह ठीक नहीं होगा।

राजस्व घाटा कैसे करना → राजस्व व्यय घटा कर

राजस्व प्राप्ति बढ़ा कर

⇓

Tax Reform

(4) Budgetary deficit - 1997 में खत्म

खर्च	कमाई	
500	300	500-300 = 200 का घाटा

सरकार RBI से Note लेके घाटा पूरा करती थी प्रतिभूति जारी करके।

⇒ बजटीय घाटा → सरकार का घाटा पूरा करने को

RBI द्वारा छाप कर दिये गये नोट की value

Study Tide

⇒ वजटीय घाटे के खत्म होने के बाद राजकोषीय घाटे का concept आया।
राजकोषीय घाटा - World Level

(5) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) -

राजकोषीय घाटे में ब्याज का योगदान

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज

= 135 - 125 = 10
P.D.

⇒ ब्याज प्रत्येक घाटे को बढ़ाने में जिम्मेदार
(सिर्फ वर्तमान साल ही नहीं बल्कि पिछले सभी loan का भुगतान घाटे को बढ़ाता है।)

⇒ सरकार की policy को evaluate करने को प्राथमिक घाटा लेंगे।
क्योंकि राजकोषीय घाटा बढ़ाने में ब्याज का बहुत बड़ा हाथ।

⇒ पर प्राथमिक घाटे को ध्यान में नहीं रखा जाता क्योंकि पुरानी सरकारों ने जो loan लिया उसे infrastructure पर भी use किया और उसके होने वाला फायदा आज की सरकार भी ले रही है तो केवल ब्याज भराना सही नहीं इसीलिये केवल राजकोषीय घाटा ही महत्वपूर्ण।

Study Tide

27/8/2015

Banking

⇒ 2011-2012 के बाद Bank profit में आ गयी

⇒ Bank's Main Aim → Profit

⇒ 2013 - 500 करोड़ की पूंजी के साथ RBI से licence लिया जा सकता था

26 application — 1 back (Tata)

↓

2 approved (bandhan)

RBI - Regulator

↓

Commercial Bank

↓

Indian Economy

Bank → दूसरे के पैसा कमाने का bussiness

Trading in Equity

Person ⟶ Bank ⟶ loaner (15%)

Person ⟵ Bank (10% ब्याज)

Bank ⇓ 5% का लाभ

3% खर्चा

2% लाभ = 2 ₹ का लाभ

⇓

∞ लाभ

$\frac{\text{Return}}{0} \times 100 = \frac{\text{₹}}{0} \times 100$

$\infty \times 100 = \infty$

⇒ Banks लोगो पर निर्भर — Saving के लिये भी

— loan के लिये भी

RBI

↓

Commercial Bank

Deposit Rate → 100 (10%) जमा → People

People ← 100 (15%) loan ← lending rate

Study Tide

⇒ lending rate > deposit rate → Always

R.B.I
↓
C. Bank

People
Bank asset
Bank → liability

People
liability – Bank
Asset → Bank

Balance Sheet → किसी भी bussiness की asset और liability का schedule । एक particular type में बनता है।

Balance Sheet

Liability		Asset
Bank loan 50 lakh	=	50 lakh का मकान खरीदा – People
Deposit 100	=	Loan & Advance 100 – Bank

⇒ Liability और asset हमेशा बराबर होते हैं।

⇒ Bank के loan देने की क्षमता → Bank के deposit पर depend करती है + Bank के अपने profit पर

⇒ Credit Worthiness – Loan लेने वाले का Background Bank check करता है ताकि उनका loan safe रहे। otherwise Bank डूब जायेगा

↓

यही old Bank के डूबने का कारण था Bank के Loan NPA हो गये थे

↓

Non Performing Asset

Study Tide

⇒ Banking Sector Reform के समय Banks का NPA - 58000 करोड़

1998 - 1999 - 58000 करोड़ ₹ (NPA)

↓

Asset जिस पर ब्याज नहीं

⇒ Defaulter

(1) Return करने की स्थिति नहीं रहने पर Defaulter

(2) जान कर रकम को Defaulter घोषित करवाना

⇒ KYC → Know Your Customer

इसमें Account में सारी details जोड़ दी जायी।

↓

defaulter घोषित होने पर

↓

RBI को Report जायेगी

↓

RBI सारे Bank को details भेज दी जायेगी

↓

इस तरह Banks Computerization के जरिये जुड़कर defaulting को रोक रहे हैं।

⇒ पिछले कुछ सालो में Banks का NPA फिर बढ़ना शुरू हो गया है।

1998 - 1999 - 58000 करोड़

2011 - 2012 - 1,37000 C ↑NPA

2012 - 2013 - 1,85000 C ↑ NPA

2013 - 2014 - 2,45000 C ↑ NPA

2014 - 2015 - 2,67000 C ↑ NPA

Problem क्यों? → Govt Bank - 86% 14% - Private Bank

Bank की मजबूरी अधिक loan देने की। पर loan सबको नहीं मिलता पहले Credit Worthiness check होती है Borrower की।

Study Tide

Borrower — 2 types

1. Prime Borrower → इसको loan देना पूरी तरह safe
2. Sub-Prime Borrower → इसको loan देने में Risk भी शामिल

gov, gov. employee, सरकारी पति मूर्तियाँ, — Prime

Advocate Police इनको छोड़कर

⇒ जिस अनुपात में Profit बढ़ रहा है उस अनुपात में Prime नहीं बढ़ रहे हैं सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में।

⇒ Prime को 30 ₹ loan दे दिया। पर 40 ₹ बच गये अब Bank की मजबूरी Sub Prime को loan देने की।

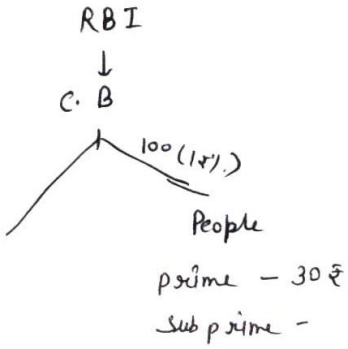

⇒ जैसे जैसे Bank का Profit बढ़ेगा, Bank की Problem बढ़ेगी कि पैसा loan कैसे दो Bank अपने पास पैसा रख भी नहीं सकती।

↓

इसलिये Bank को Sub Prime को loan देना मजबूरी।

↓

Bank का sub prime loan बढ़ा

↓

NPA बढ़ा

⇒ सरकारी बैंको का 86% हिस्सा NPA में होने का कारण - सरकार पर corporate को ~~बड़ा~~ बड़ा loan देने का दबाव साथ ही return के लिये कम दबाव।

Study Tide

⇒ Govt Bank का Law & Order Weak – NPA बढ़ने का कारण

⇒ RBI ने बदलाव किया – NPA Recover हेतु

अगर बैंको का पैसा डूब जाये तो उनका Debt equity में change हो जायेगा और Banks को मालिकाना हक मिलेगा।

⇒ Kingfisher – 3200 करोड़ loan लिया

↙

1800 करोड़ – SBI से

⇒ Return के लिये Bank ने Kingfisher house बेचा – 100 करोड़ में

⇒ Debt Equity में change होने पर Bank directly बेच सकेगी asset borrower के

⇒ 2008 की मंदी – Sub Prime Crisis

⇒ बड़े Bussiness में उधार चलता है उधार चुकाने को एक time period होता है – Credit Period

⇒ Debtor – देनदार – उधार जिसको बेचा

⇒ Creditor – लेनदार – जिससे उधार खरीदा

माना Total Debtor – 5,00,000 ₹

Debt Collecting Agency → व्यक्ति ने अपने 5,00,000 ₹ के debtor को 4,00,000 में बेच दिया। अब पैसा वह Agency लेगी।

⇒ 2008 से पहले बहुत ज्यादा loan Sub Prime Borrowers को दिया गया।

↓

Bank को doubt हुआ तो उसने इकट्ठे Bank को कम rate में बेच दिया – 120 Bank एक chain में

↓

इस तरह सारा पैसा डूब गया

Study Tide

⇒ 120 में में Europe gov ने Banks को Bail Out Package दिया Borrowing करके। और आज तक ~~Bank~~ Europe loss में हैं

भारत में A R C → Asset Reconstruction Company

↓

Recovery करते हैं

⇒ Bank loan देगी तो lending Rate – Bank तय करता है।

⇒ Risk ज्यादा → ब्याज दर ज्यादा

⇒ कम क्षमता → ब्याज दर ज्यादा

⇒ हर एक Bank Base Rate declare करती है यह minimum rate of Interest है जिस Bank loan देगी।

⇒ Base rate – Prime lending Rate – पहले (old name)

↓

Bench Mark – (विकसित देशों में)

↓

B P L·R – (भारत में)

⇒ Peoples को attract करने को Bank नई-नई scheme लाये।

⇒ SBI loan लाया → first half में ब्याज rate बहुत कम

↓

Second half में काफी ज्यादा

↑

इसको जबरदस्त response मिला।

exam ⇒ RBI ने इस loan को Teaser Loan नाम दिया।

⇒ SBI ने इसे फिर बंद कर दिया।

Study Tide

Exam Chronic Capitalism - gov + Beaurocrat + Cooperate → उत्पादन
मिलकर
↓
(Consumer) जनता का शोषण

⇒ Deposit
- Demand Deposit — मांग जमा
- Time Deposit → fix deposit — सावधि जमा

R.B.I
|
C.B
|
People
↓
Deposit

1 Demand Deposit - payable on demand
Banking Regulation Act 1949 के अनुसार Banks को right नहीं दिया गया कि people की demand पर पैसा देने को मना कर सके - ex. ATM

2 Time Deposit - Payable at maturity

⇒ ATM - VAT के अन्तर्गत आता है। पैसा न मिले उसके कई कारण हो सकते हैं पर Bank deny नहीं करेगा।

⇒ Bank Branch deny नहीं कर सकती केवल 1 case में मना हो सकता है - Internet Connectivity नहीं है

↓
उसके अलावा अगर Bank के पास sufficient पैसा नहीं है तो
↓
Bank किसी और other Bank nearest से loan लेना सिर्फ 1 day के लिये
↓
14 day का extension मिल सकता है
↑
Call Money Market

Study Tide

Call Money - 35- 40 % Interest Rate

→ Bank to Bank Loan

→ हमारा Demand Deposit Bank का demand liability

Time Deposit → माना 2 साल के लिये किया।

या

Fix deposit

हमारा asset , Bank की liability

6 महीने बाद जरूरत पड़ जाये तो इसे तोड़ा जा सकता है

↓

Bank इस पर charge लेती है - 1-1.5% की कमी ब्याज दर में

Pre closure charge लेती है - Nominal

↓

Bank के पास पैसा न हुआ तो Bank next day pay करेगी।

Demand Deposit →

बचत खाता (Saving Account)	चालू खाता (Current Account)
1 व्यक्ति के नाम पर	1 संस्था के नाम पर (firm, Company) ⇒ यह व्यक्ति के नाम पर नहीं खुल सकता सिवा किसी Act में नहीं ⇒ Bussiness सम्बन्धित खाता ⇒ अब Banks ने person के current account open करने शुरू कर दिये।
2 इसमें per day Transaction limited * 1 day - 4-5 Transaction allowed	⇒ Transaction Unlimited ⇒ इसमें ज्यादातर Transaction check से Income Tax Act 1961 - 20000 से ऊपर का खर्च check से pay करेंगे क्योंकि इस पर Tax लगेगा। नहीं लगेगा। बिना इसके खर्च नहीं माना जायेगा।

Study Tide

3 exception → gov के account में जमा करे तो ₹0000 के ऊपर किसी में भी जमा कर सकते हैं

→ Truck Driver – payment case

→ Banking सुविधा न हो वैसा होगा

⇒ Chuck – Chuck date से 3 Month तक valid

↓

Stale Chuck → unvalid

3 चलत खाते पर ब्याज मिलता है

~~₹0H~~ के

31 Mar ₹011 – rate 3.5% था

1 Apr ₹011 – rate 4% कर दिया गया

₹011 के बाद अब Bank, interest rate खुद तय कर सकती है

3 चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता

अभी तक RBI ने एक ब्याज दर को तय करने की छूट नहीं दी।

Gov. Tax लेती है - Income पर

Bussiness - Profit पर Tax

⇒ Saving Account में 50000 से ऊपर हेतु PAN Card आवश्यक था पहले निर्धारित था अब Tax limit 50000 थी / Tax छूट दे गयी पर limit वही रही

⇒ A.I.R → Annual Information Report — 10 cases में

→ अगर हमारे Bank Account में साल में ~~एक~~ में 10,00,000 से ज्यादा धीरे धीरे पैसा आयेगा

→ KYC से PAN Card जोड़ दिया गया एकसे सारे खातेधारो की detail सभी के पास available.

Study Tide